

आज की जनधारा

सीधी और सच बात, साहस के साथ



पेज-06

RNI No.- CHHHIN/2021/80816

वर्ष : 07, अंक : 26, विलासपुर, मंगलवार 26 मई 2026

रायपुर, विलासपुर, जगदलपुर, मध्यप्रदेश से प्रकाशित | www.aajkijandhara.com | email: aajkijandhara@gmail.com | ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष-10, वि.सं. 2083 | पृष्ठ : 12 | मो. : 9425203900, 9425243430 | ग्लोबल : 2.00 रु.

दिवशा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

युवती की जान चली गई, वजह जो भी हो पता चलना चाहिए-निष्पक्ष हो जांच

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश के चर्चित मॉडल टिप्पणी शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्वतः-संज्ञान मामले पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी एम पंचोली की बेंच ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने मीडिया से इस मामले में आरोपियों के इंटरव्यू न चलाने का आग्रह किया। साथ ही कोर्ट ने सुनवाई के दौरान साॅलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की पूरी जांच को आज ही अपने हाथों में ले रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड पर लिया है।



चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने उम्मीद जताई कि सीबीआई तुरंत जांच अपने पास लेकर इस पर कड़े स्तर की सुनवाई शुरू करेगी। कोर्ट ने कहा कि एक मासूम युवती की जान गई है, वजह चाहे जो हो

, उसका पता चलना चाहिए। उसके स्वतंत्र निष्पक्ष और गहराई से जांच होनी जरूरी है। क्योंकि मामले में अपराधिक साजिश का भी एंगल शुरूआती जांच और आरोपों से सामने आ रहा है।

रिटायर्ड जज सास को हाईकोर्ट का नोटिस

एक्ट्रेस दिवशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी सास और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस राज्य सरकार और दिवशा के पिता नवनिधि शर्मा की उस याचिका पर जारी हुआ, जिसमें ट्रायल कोर्ट से मिली गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत का विरोध किया गया है। सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश महाधिका प्रशांत सिंह ने कहा कि गिरिबाला जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। वहीं, गिरिबाला सिंह के वकील मुंद्र सिंह ने कहा- यह कहना गलत है कि हम जांच में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हमें पीटिशन के दस्तावेज नहीं मिले हैं, इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए। वहीं भोपाल जिला कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह मामले की सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी है। पुलिस प्रतिवेदन नहीं मिलने के कारण सुनवाई स्थगित की गई। कोर्ट ने पुलिस को कल तक प्रतिवेदन पेश करने के निर्देश दिए हैं।

दिवशा के पति और सास के खिलाफ एफआईआर दर्ज

दिवशा शर्मा की संदिग्ध मौत के बाद उनके पति समर्थ सिंह और उनकी सास जो कि एक पूर्व जिला न्यायाधीश हैं, गिरिबाला सिंह के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि रसूख के कारण स्थानीय स्तर पर जांच प्रभावित हो रही थी। साॅलिस्टर जनरल ने कोर्ट को बताया कि इसी प्रक्रियागत अनियमितता को दूर करने के लिए आज ही जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट 14 शेष पृष्ठ 10 पर

एनटीए ने अब तक सबक नहीं सीखा

नीट पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

नई दिल्ली। नीट पेपर लीक मामले में घमासान लगातार जारी है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि यह दुखद है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने पहले हुए नीट पेपर लीक केस में सबक नहीं सीखा है। साथ ही शीर्ष अदालत ने केंद्र, एनटीए और सीबीआई से मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए परीक्षा एजेंसी की जगह एक मजबूत और स्वायत्त निकाय स्थापित करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर जवाब मांगा है।



एनटीए को 2024 में अदालत की ओर से जारी निर्देशों के अनुपालन पर गुरुवार तक एक हलफनामा दाखिल करने को कहा। पीठ ने कहा कि यह दुखद है कि उन्होंने सबक नहीं सीखा है। यह मामला पहले भी इस अदालत में आया था। एक समिति, एक निगरानी समिति गठित की गई थी जिसने कुछ सिफारिशों की थीं और उन्हें स्वीकार कर लिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मांगा हलफनामा: शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि एनटीए समिति को ओर से सुझाई गई सिफारिशों के

अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों पर एक हलफनामा दाखिल करें। शीर्ष अदालत ने फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (एफआईएमए) की ओर से वकील तन्वी दुबे के माध्यम से दायर याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि वह सभी समान मामलों को एक साथ नथी कर रहा है। अदालत ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पूर्व प्रमुख के. राधाकृष्णन के नेतृत्व वाली केंद्र की ओर से नियुक्त समिति को एनटीए के कामकाज में सुधार करने और उसके निर्देशों के अनुपालन के लिए उठाए गए कदमों का विस्तृत विवरण देने का निर्देश दिया।

फेमा की याचिका, उठाई ये मांग: मेडिकल संस्था ने बार-बार पेपर लीक होने के कारण 22.7 लाख से 14 शेष पृष्ठ 10 पर

10 दिन में चौथी बार बढ़े पेट्रोल-डीजल के दाम

7 रुपये से ज्यादा की आई तेजी

नई दिल्ली। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल (क्रेड ऑयल) की ऊंची कीमतों और अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने सोमवार को एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर दी है। पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है जब पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़े हैं। लंबे अंतराल के बाद हाल में 15 मई को पहली बार तेल की कीमतों में वृद्धि हुई थी। तब से लेकर अब तक पेट्रोल 7.35 रुपये और डीजल 7.82 रुपये प्रति लीटर महंगे हो चुके हैं। इनकी कीमतों में अभी और वृद्धि हो सकती है। तेल अधिकारियों का कहना है कि इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह



अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें और रुपये के अल्पमुल्यन के कारण बढ़ी हुई आयात लागत है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने कहा कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार अस्थिरता और अंडर-रिक्वरी (लागत से कम पर बिक्री) ने तेल खुदरा विक्रेताओं पर भारी दबाव बना दिया है। 15 मई: पेट्रोल और डीजल की कीमतों में प्रति लीटर करीब 3 रुपये की वृद्धि हुई थी। 19 मई: पेट्रोल 14 शेष पृष्ठ 10 पर

गुलमर्ग गोंडोला में तकनीकी खराबी, बीच हवा में अटके करीब 300 पर्यटक; रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

श्रीनगर। प्रसिद्ध गुलमर्ग गोंडोला में सोमवार को अफसर-तफरी मच गई जब अचानक तकनीकी खराबी आने के कारण केबल कार सेवा बीच में ही रुक गई। इस घटना के चलते करीब 300 पर्यटक हवा में ही अलग-अलग केबिनो में फंस गए। जानकारी के अनुसार गोंडोला के संचालन के दौरान अचानक तकनीकी गड़बड़ी आ गई, जिससे केबल कार आगे नहीं बढ़ सकी और यात्री बीच रास्ते में ही अटक गए। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम को मौके पर बुलाया गया। घटना की सूचना मिलते ही फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज और स्थानीय प्रशासन की टीमों तुरंत मौके पर पहुंचीं। राहत और बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार सभी फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और तकनीकी टीम भी खराबी को ठीक करने में जुटी हुई है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जिससे राहत की बात है।

बीजापुर में 10 करोड़ का तेंदूपत्ता जलकर खाक

किराए के गोदाम में 10 दिनों में स्टोर किए गए थे 18 हजार बोरे, बुझाने में जुटी सीआरपीएफ



बीजापुर। जिले में सोमवार दोपहर एक निजी तेंदूपत्ता गोदाम में भीषण आग लग गई। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया और वहां रखे लगभग 18 हजार बोरे जलकर खाक हो गए। शुरुआती अनुमान के मुताबिक खस हदसे में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड तुरंत मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। आग इतनी भीषण थी कि हालात को देखते हुए वन विभाग, पुलिस और नगर पालिका की टीम के अलावा सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गईं।

वन विभाग ने तेंदूपत्ता स्टोरेज के लिए गोदाम को किराए पर लिया था। जिसमें 10 दिनों के भीतर तेंदूपत्ता के लगभग 18 हजार मानक बोरे स्टोर किए गए थे। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। यह मामला बीजापुर कोतवाली थाना क्षेत्र के ईटपाल इलाके का है।

जानकारी के अनुसार, ईटपाल इलाके में वन विभाग ने तेंदूपत्ता स्टोरेज के लिए एक किराए का गोदाम लिया था, जिसमें दोपहर करीब 2:30 बजे भीषण आग लग गई। उस समय गोदाम में 14 शेष पृष्ठ 10 पर

बंगाल में घुसपैटियों और विदेशी कैदियों के लिए होलिंग सेंटर शुरू

लालगोला के पद्मा भवन में रखे गए तीन बांग्लादेशी

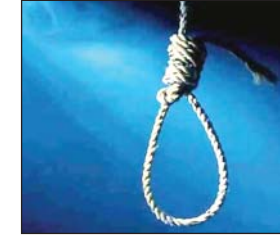


कोलकाता। बंगाल में सीमा पार से होने वाली अवैध घुसपैट और सजा पूरी कर चुके विदेशी नागरिकों के प्रत्यर्पण की जटिल प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार के ताजा आदेश के बाद प्रदेश के हर जिले में होलिंग सेंटर बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। गौर करने वाली बात यह है कि गत 23 मई को इस संबंध में आधिकारिक दिशानिर्देश जारी होने के महज 48 घंटों के भीतर ही इस पर कड़ाई से अमल भी शुरू कर दिया गया है। होलिंग सेंटर का निर्माण शुरू: इसी कड़ी में मुर्शिदाबाद के

लालगोला स्थित पद्मा भवन की तीसरी मंजिल पर राज्य का पहला सक्रिय होलिंग सेंटर अस्तित्व में आ चुका है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस सेंटर में तीन बांग्लादेशी नागरिकों को लाकर रखा भी जा चुका है। सुरक्षा और गोपनीयता के लिहाज से फिलहाल इन तीनों की विस्तृत पहचान उजागर नहीं की गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये सभी पुरुष हैं और इनकी उम्र 30 से 40 वर्ष के बीच है। तीन इण्डियॉ के लोग रखे जाएंगे: इन केंद्रों में: सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, इन होलिंग सेंटरों का उपयोग मुख्य रूप से तीन विशेष श्रेणियों के विदेशी नागरिकों को रखने के 14 शेष पृष्ठ 10 पर

छत्तीसगढ़ में बढ़े आत्महत्या के मामले : देश के टॉप फाइव राज्यों में प्रदेश का चौथा स्थान

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आत्महत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन खुदकुशी की खबरें आ रही हैं। रोजाना खुद ही जान देने के मामले इतने बढ़े हैं कि छत्तीसगढ़ देश में आत्महत्या के मामलों में चौथे स्थान पर है यानी देश में टॉप फाइव के स्थान पर आ गया है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की रिपोर्ट 2023 के मुताबिक राज्य में 7,868 आत्महत्याएं दर्ज की गईं। आत्महत्या दर प्रति एक लाख आबादी पर 26 रही, जो राष्ट्रीय औसत 12.3 से दोगुने से भी अधिक है। एनसीआरबी के अनुसार, आत्महत्या दर के मामले में छत्तीसगढ़ देश के राज्यों में चौथे



स्थान पर रहा। इससे पहले सिक्किम केरल और तेलंगाना जैसे राज्य हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2022 में राज्य में 8,446 आत्महत्याएं दर्ज हुई थीं, जबकि 2023 में इसमें करीब 6.8 प्रतिशत की कमी आई। एनसीआरबी की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ आत्महत्या दर के मामले में देश में तीसरे स्थान पर था। उस समय राज्य की आत्महत्या दर 28.2 दर्ज

धर्मद का मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान लेकर भावुक हुई हेमा मालिनी

बेटी अहाना नहीं रोक पाई आंसू

नई दिल्ली। इस साल जनवरी में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कला, साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान और खेल सहित विभिन्न क्षेत्र की हस्तियों को सोमवार को देश के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी, इनमें से 66 हस्तियों को आज सम्मानित किया जा रहा है। इस साल की सूची के मुताबिक कुल पांच लोगों को पद्म विभूषण, 13 विभूषितियों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्म श्री से नवाजा जाएगा। 2026 में कुल 131 हस्तियों को



पद्म पुरस्कार दिए जाने हैं, जिनमें से बाकी बचे 65 विजेताओं को अगले चरण में सम्मानित किया जाएगा। धर्मद का मरणोपरांत पद्म विभूषण; हरमनप्रीत कौर समेत कई हस्तियों को सम्मान: पद्म विभूषण सम्मान 2026 में सबसे पहले दिवंगत अभिनेता धर्मद सिंह देओल (मरणोपरांत) को प्रदान किया गया। यह सम्मान उनकी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने ग्रहण

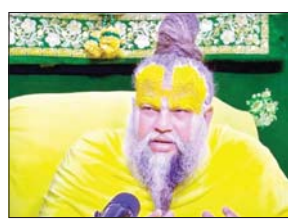
किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से नवाजा गया। उनकी नेतृत्व क्षमता में भारतीय टीम ने इस वर्ष वनडे वर्ल्ड कप जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी। सोनर रूफ के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल को रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया।

असम में युनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश

गुवाहाटी। असम विधानसभा में युनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) बिल सोमवार को पेश किया गया। इसे पटल पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की ओर से राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अतुल बोरा ने रखा। इस बिल को दो हफ्ते पहले कैबिनेट से मंजूरी मिली थी। इस बिल पर 27 मई को चर्चा होगी। यदि यह बिल पारित हो जाता है, तो असम देश का तीसरा ऐसा राज्य बन जाएगा। इससे पहले उत्तराखंड और गुजरात ऐसा कर चुके हैं। सीएम सरमा के मुताबिक अनुसूचित जनजातियां (जजाड़) और अनुसूचित पिछड़ा जातियां (मैदानी) यूसीसी के दायरे से बाहर रहेंगी। साथ ही पारंपरिक धार्मिक रीति-रिवाजों, प्रथाओं और अनुष्ठानों को भी इससे छूट दी जाएगी।

प्रेमानंदजी की अपील- मैं रहूँ न रहूँ, हमेशा साथ रहूँगा

मेरी चिंता छड़िए, श्रीजी का ध्यान लगाइए; तबीयत बिगड़ने के बाद 9 दिन से पदयात्रा बंद



मथुरा। 'बिल्कुल चिंता मत करो। हम मिलें न मिलें, बोलें न बोलें, हम आप सबको बहुत प्यार करते हैं। अंतिम बात यही कि चिंता नहीं करनी। न ये चिंता करनी है कि कैसे हमारा उथान होगा। बिना बोले तुम्हारे दिमाग में हम होंगे।' ये भावुक अपील वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज ने वीडियो जारी कर अपने शिष्यों और भक्तों से की। 1 मिनट 19 सेकेंड का वीडियो रविवार को केली कुंज आश्रम ट्रस्ट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया। 17 मई यानी 9 दिन से प्रेमानंद

महाराज की रात्रि पदयात्रा बंद है। शिष्यों ने तब बताया था कि प्रेमानंद महाराज की तबीयत ठीक नहीं है। वह भक्तों से एकांतिक मुलाकात भी नहीं कर रहे हैं। प्रेमानंद महाराज की दोनो किडनी खराब हैं। उनकी हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस होती है। प्रेमानंद महाराज ने आगे कहा कि देख लेना तुम वही करोगे, जो गुरुदेव कहेंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। जो जहाँ जिस सेवा में आए, उस सेवा में रहिएगा। खूब नाम जप करो। मंगल होगा। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे।

बदलता इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़ता भारत: रायपुर-विशाखापट्टनम कॉरिडोर से खुलेगा तरक्की का द्वार



'गति शक्ति और आत्मनिर्भर भारत के विजन से छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई उड़ान'

को एकीकृत करते हुए देश को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास निरंतर जारी है। विकास के इसी दूरदर्शी दृष्टिकोण का एक उत्कृष्ट उदाहरण रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर है। यह कॉरिडोर केवल दो शहरों को जोड़ने वाली सड़क परियोजना नहीं है, बल्कि यह एनए भारत की नई रफ्तार का प्रतीक है, जो उद्योग, व्यापार, निवेश और रोजगार के नए क्षितिज खोलने जा रहा है।

मध्य-पूर्वी समुद्री तट को जोड़ने वाला महामार्ग: रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर देश के मध्य भाग को पूर्वी समुद्री तट से जोड़ने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक मार्ग है। यह छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के बीच निबंध कनेक्टिविटी (संपर्क) स्थापित करेगा, जिससे सड़क परिवहन, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी। इस परियोजना को प्रधानमंत्री की 'गति शक्ति' और 'आत्मनिर्भर भारत' की सोच को केंद्रित करने के लिए देश में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

विकास का मूलमंत्र: किसी भी राज्य या देश के विकास का सबसे मजबूत आधार उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। जहां विश्वस्तरीय सड़कें, सुगम परिवहन और अत्याधुनिक लॉजिस्टिक्स सुविधाएं होती हैं, वहां उद्योगों का तेजी से विस्तार होता है और निवेश आकर्षित होता है। यह कॉरिडोर माल परिवहन को अधिक तीव्र, सुक्ष्म और लागत प्रभावी (कम खर्चीला) बनाएगा। इसके परिणामस्वरूप उद्योगों को कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होगा और तैयार उत्पाद कम से कम समय में बाजार तक पहुंच सकेंगे।

चूँकि विशाखापट्टनम बंदरगाह देश के प्रमुख समुद्री द्वारों में से एक है, इसलिए इस कॉरिडोर के माध्यम से छत्तीसगढ़ को सीधे पोर्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि राज्य के उद्योगों की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक सीधी पहुंच स्थापित होगी, जिससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी।

छत्तीसगढ़ को मिलने वाले प्रमुख लाभ: रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के लिए गेम-चेंजर साबित होने वाला है। छत्तीसगढ़ खनिज संपदा, ऊर्जा संसाधनों, कृषि और वनोपज से समृद्ध राज्य है। यहाँ लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट और स्टील उद्योगों की अपार संभावनाएँ हैं। पूर्व में बेहतर परिवहन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क के अभाव के कारण उद्योग अपनी पूरी क्षमता का लाभ नहीं उठा पाते थे, परंतु यह कॉरिडोर इन चुनौतियों को समूल समाप्त कर देगा।

औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन: कॉरिडोर के निर्माण से रायपुर, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, कांकेर और जगदलपुर जैसे क्षेत्रों में नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित होंगे। स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, खाद्य प्रसंस्करण (फूड प्रोसेसिंग) और एमएफएमई (लघु उद्योगों) को एक नई ऊर्जा मिलेगी, जिससे घरेलू और विदेशी निवेशकों का रुझान इस क्षेत्र की ओर तेजी से बढ़ेगा।

हृदयनी बढ़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के आने से रोजगार के अवसर भी आनुपातिक रूप से बढ़ेंगे हैं। सड़क निर्माण, वैयर्थहरीकरण, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, नई औद्योगिक इकाइयों और परिवहन सेवाओं के माध्यम से हजारों प्रत्यक्ष

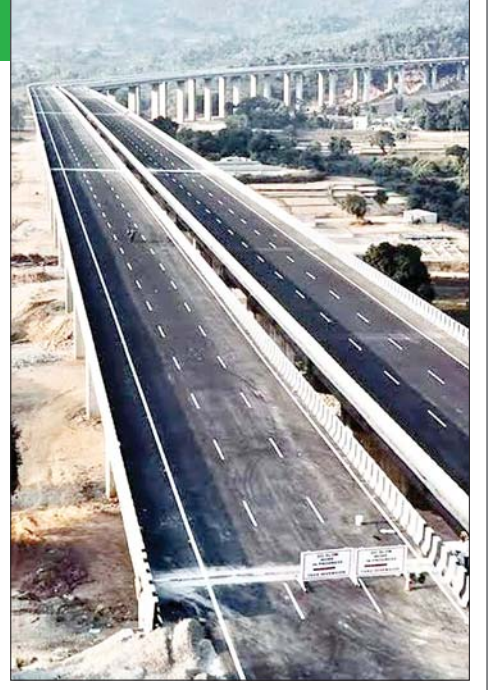
और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। स्थानीय युवाओं को अपने ही क्षेत्र में जीविकोपार्जन के साधन मिलने से पलायन की समस्या पर काफी हद तक रोक लगेगी।

बस्तर क्षेत्र का कायाकल्प: यह कॉरिडोर बस्तर सभाग के लिए विशेष रूप से परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। लंबे समय से विकास की मुख्यधारा से कटे क्षेत्रों में बेहतर सड़क और व्यापारिक संपर्क स्थापित होगा। बस्तर के बहुमूल्य वन उत्पाद, अनाज, हस्तशिल्प, कृषि उपज और लघु उद्योगों को बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी, जिससे आदिवासी समुदायों की आय में वृद्धि होगी और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। कृषि और वनोपज को सही मूल्य

छत्तीसगढ़ देश में धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ मक्का, दलहन, फल और लघु वनोपज का भी प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है। बेहतर परिवहन व्यवस्था से किसानों और वनोपज संग्राहकों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में सुगमता होगी। परिवहन लागत घटने से सीधे तौर पर किसानों का मुनाफा बढ़ेगा।

पर्यटन उद्योग को नई उड़ान: चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिरपुर और बस्तर के सांस्कृतिक पर्यटन स्थलों तक पहुंच सुगम होने से राज्य में पर्यटन उद्योग को भारी बढ़ावा मिलेगा। इससे होटल, गाइड, स्थानीय परिवहन और हस्तशिल्प व्यवसायियों की आय दोगुनी होगी।

व्यापार और निर्यात में ऐतिहासिक वृद्धि: विशाखापट्टनम पोर्ट तक आसान और तेज पहुंच से छत्तीसगढ़ के उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता (कॉम्पिटिटिवनेस) बढ़ेगी। संक्षेप में कहें तो, रायपुर-



विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर महज एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की प्रगति, समृद्धि और आत्मनिर्भरता का नया महामार्ग है। यह छत्तीसगढ़ को देश के एक प्रमुख औद्योगिक और व्यापारिक हब के रूप में स्थापित करने का सामर्थ्य रखता है।

मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ही सशक्त अर्थव्यवस्था की नींव होता

धनंजय राठौर, संयुक्त संचालक

सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक

रायपुर। भारत आज तीव्र गति से आधुनिक बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) और सुदृढ़ आर्थिक नेटवर्क के निर्माण की दिशा में अग्रसर है। सड़क, रेल, बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स



सड़क दुर्घटनाएं नहीं हों, इसके लिए हर जरूरी कदम उठाएं: मुख्य सचिव

रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सभी सम्बन्धित और ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। मुख्य सचिव आज मंत्रालय में सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

ब्लैक स्पॉट सुधारने पर विशेष जोर: मुख्य सचिव ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं के लिए चिन्हित ब्लैक स्पॉट की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और वहां आवश्यक सुधार कार्य तत्काल किए जाएं। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से सड़कों की स्थिति सुधारने के निर्देश दिए ताकि हादसों की आशंका खत्म हो सके।

सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की योजनाओं की समीक्षा: बैठक में राज्य सड़क सुरक्षा कोष, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फलोदी एवं रंगा रेड्डी सड़क दुर्घटना मामलों में दिए गए दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। साथ ही पीएम राहत योजना और पीएम ई-ड्राइव योजना की प्रगति की जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने को कहा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी सड़क दुर्घटना रोकथाम से संबंधित एएसओपी के क्रियान्वयन की भी समीक्षा की गई।

ईवी चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने के निर्देश: मुख्य सचिव ने पीएम ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत ई-वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन की स्थापना में तेजी लाने को कहा। उन्होंने परिवहन विभाग को निर्धारित स्थलों पर तत्काल ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में अब तक 150 स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। इन स्टेशनों पर पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत सब्सिडी भी दी जाती है।

जल जीवन मिशन से बदली जशपुर के ग्राम बेंगटा की तस्वीर

61 परिवारों तक पहुंचा शुद्ध पेयजल, महिलाओं और बच्चों को मिली बड़ी राहत

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में संचालित जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर सुधारने का माध्यम बन रहा है। जशपुर जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर जंगलों से घिरे ग्राम बेंगटा में इस योजना ने पेयजल संकट को दूर कर ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है।

भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा गांव में 10 किलोलिटर क्षमता का उच्च स्तरीय जलागार स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से ग्राम की दोनों बसाहटों के 61 परिवारों को नियमित रूप से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल जीवन मिशन के लक्ष्य होने से पहले ग्रामीणों को पेयजल के लिए नाला और कुओं पर निर्भर रहना पड़ता था। महिलाओं और बच्चों को प्रतिदिन लंबी दूरी तय कर पानी लाना पड़ता था। गर्मी के मौसम में जल संकट गहरा जाता था, वहीं बरसात में मटमैले और असुरक्षित पानी के कारण जलजनित बीमारियों का खतरा बना रहता था। अब हर घर में नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंच रहा है। इससे महिलाओं और बच्चों के समय की बचत हो रही है तथा महिलाएं आजीविका गतिविधियों पर अधिक ध्यान दे पा रही हैं। स्वच्छ पानी मिलने से ग्रामीणों के स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है और जलजनित बीमारियों में कमी आई है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जशपुर द्वारा ग्राम बेंगटा को 'हर घर जल' प्रमाणित किया जा चुका है। ग्रामीणों ने कहा कि जल जीवन मिशन ने गांव में न केवल पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की है, बल्कि जीवन को अधिक सुरक्षित, सरल और बेहतर बनाया है।



सुशासन तिहार बना ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम

रायपुर। किसानों को केसीसी, विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र और हितग्राहियों को मिली राहतमुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन संकल्प को साकार करते हुए जशपुर जिले के ग्राम बड़कौरा में सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत जिला स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आसपास के 15 गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अपनी समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए।

शिविर में कुल 235 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निराकरण किया गया। विभिन्न विभागों द्वारा हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। इस दौरान 08 हितग्राहियों को नए पुरान कार्ड, 03 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के पूर्णता प्रमाण-पत्र, 14 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड तथा 4 किसानों को उर्वरक वितरित किए गए। साथ ही 25 मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम में जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनी भगत ने नवजात शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार एवं गर्भवती महिलाओं की गोदभराई की रस्म पूरी कर उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है और सुशासन तिहार इस दिशा में प्रभावी पहल साबित हो रहा है। शिविर में टेकुल ग्राम के किसान अजीत एका को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया गया। उन्होंने कहा कि अब उन्हें खेती-किसानी के लिए समय पर खाद-बीज उपलब्ध हो सकेगा और सहकारों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।



संघर्ष से आत्मनिर्भरता तक : बीजापुर की मनीषा नायक ने पेश की मिसाल

'जब हैसला मजबूत हों, तो सीमित संसाधन भी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देता है'

रायपुर। यदि सही मार्गदर्शन और दृढ़ इच्छाशक्ति हो, तो कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अनुकूल बनाया जा सकता है। बेरोजगारी और सीमित संसाधनों जैसी चुनौतियों के आगे घुटने टेकने के बजाय, उन्होंने नवाचार का रास्ता चुनकर अपनक भ्रमव्य को संवार सकते हैं। आज छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले की रहने वाली 22 वर्षीय मनीषा नायक ने यह साबित कर दिया है। वे एक सफल राइस मिल संचालिका के रूप में न केवल आत्मनिर्भर जीवन जी रही हैं, बल्कि अन्य ग्रामीण युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत भी बन चुकी हैं।

'संघर्ष और दुविधा का वो शुरुआती दौर': मनीषा नायक का जीवन सफर शुरुआत में काफी संघर्षमय रहा। पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अदद स्थायी रोजगार के लिए उन्होंने लंबे समय तक प्रयास किए, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी रही थी। समय बीतने के साथ भविष्य की चिंता और मानसिक तनाव गहराता गया। एक साधारण आर्थिक घुबधूमि वाले परिवार से आने के कारण उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती स्वयं को



आत्मनिर्भर बनाने और परिवार का संबल बनने की थी। ऐसे नाजुक मोड़ पर मनीषा ने हताश होने के बजाय स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाने का साहसिक निर्णय लिया।

'उम्मीद की एक नई किरण': इसी बीच एक परिचित के माध्यम से मनीषा को जिला

व्यापार एवं उद्योग केंद्र, बीजापुर के बारे में पता चला। वहीं पहुंचने पर विभागीय अधिकारियों ने उन्हें अत्यंत सरल और प्रभावी ढंग से केंद्र सरकार की पीएमएफएमई (PMFME) योजना की बारीकियों से अवगत कराया।

'पीएमएफएमई योजना- आत्मनिर्भरता का नया आधार': प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना विशेष रूप से उन महत्वाकांक्षी युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपना छोटा व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। विभाग से मिले मार्गदर्शन और प्रोत्साहन ने मनीषा के भीतर एक नया आत्मविश्वास भर दिया। उन्हें यह विश्वास हो गया कि वे भी अपने दम पर एक सफल उद्यमी बन सकती हैं।

'बैंक ऋण से शुरू हुआ उद्यम का सफर': जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के सहयोग से मनीषा ने भारतीय स्टेट बैंक की भैरमगढ़ शाखा में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत ऋण के लिए आवेदन किया।

गाँव-गाँव इन दिनों तेंदूपत्ता संग्रहण का चल रहा सिलसिला

तेज धूप और थकान में भी हरा सोना से मिलती है राहत

रायपुर। तेज दोपहरी की धूप हो या गाँव के तालाबों में कम होता पानी, गर्मी का मौसम अपने साथ कई चुनौतियाँ लेकर आता है। लेकिन कोटा जिले के दूरस्थ गाँव लेमरु के परिवारों के लिए यही मौसम खुशियों की सौगात भी लेकर आया है। कारण हैकूतेंदूपत्ता के बड़े हुए दाम, जिसने इस क्षेत्र के सैकड़ों संग्राहक परिवारों की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। गाँव की गलियों में दोपहर का सन्नाटा भले ही छाया रहता हो, पर जंगल की ओर जाने वाली पगडंडियों पर सुबह से शाम तक रौनक देखने को मिलती है। महिलाएँ, युवा, बच्चे और बुजुर्ग तेंदूपत्ता संग्रहण में जुटे हुए हैं। जंगलों से पत्ते तोड़कर लाना, उन्हें गठरी में भरकर घर तक लाना और फिर घर की परछी में बैठकर 50-50 पत्तों के बंडल बनानाकई नए सब कामों के बीच उनके चेहरों पर एक समान चमक दिखाई देती है। सभी के मन में यही खुशी है कि दाम बढ़ने से आमदनी भी बढ़ेगी और जितना अधिक संग्रहण होगा, उतनी ही आमदनी मिलेगी।

लेमरु गाँव के संतोष यादव और उनकी



पती दिव्या यादव हर सुबह सूरज निकलने से पहले लाम पहाड़ के जंगल की ओर निकल जाते हैं। दिव्या बताती हैं कि सुबह से दोपहर तक पत्ते तोड़ते हैं, फिर दोपहर के बाद खाना खाकर घर में बैठकर बंडल बनाना शुरू करते हैं। इस बार वे पिछले साल से कहीं अधिक

बताती हैं कि यह राशि उनके परिवार के लिए बेहद उपयोगी है। तेंदूपत्ता संग्रहण और योजना से मिली सहायता मिलकर अब उनके परिवार के लिए बेहतर भविष्य की राह खोल रहे हैं। वे खुशी से बताती हैं कि अब प्रति मानक बोरा की कीमत 5500 रुपये कर दी गई है, जिससे वे अपने घर के निर्माण का सपना पूरा करना चाहती हैं।

गाँव की ही सोना बाई और सुमित्रा बाई भी सुबह-सुबह जंगल जाती हैं। वे कहती हैं कि जितना ज्यादा पत्ता तोड़ेगे, उतनी ही आय होगी। पहले कीमत 2500 रुपये थी, फिर 4000 हुई और अब 5500 रुपये होने से उनके जीवन में बड़ा बदलाव आया है। तेंदूपत्ता संग्राहक कार्ड के माध्यम से बीमा और बच्चों को छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएँ भी मिल रही हैं, जो वन क्षेत्र के परिवारों के लिए महत्वपूर्ण सहायक बन चुकी हैं।

तेंदूपत्ता के बड़े दामों ने संग्राहकों के चेहरों पर नई रोशनी ला दी है। संग्राहकों ने कीमत वृद्धि पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार जताया है।

गर्मी में राहत और सतत बनी रहे रोशनी

शासन की संवेदनशील पहल से सियाराम मरकाम के घर लौटी बिजली

रायपुर। राज्य शासन की संवेदनशील पहल और दूरस्थ अंचलों तक बिजली सुविधाओं की सतत उपलब्धता सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता ने धमतरी जिले के गंगरेल डुबान क्षेत्र स्थित ग्राम तुमाखुर्द निवासी सियाराम मरकाम के परिवार के जीवन में फिर से रोशनी लौटा दी है। वर्षों पहले स्थापित सोलर होम लाइट सिस्टम के खराब हो जाने से उनका परिवार लंबे समय से परेशान था। भीषण गर्मी के इस मौसम में बिजली और पंखे की सुविधा बंद होने से दैनिक जीवन कठिन हो गया था। राज्य शासन की मंशा के अनुरूप यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में भी बिजली की उपलब्धता बनी रहे तथा गर्मियों के कठिन समय में लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी संवेदनशील



दृष्टिकोण के तहत समस्या की जानकारी मिलते ही क्रेडा के तकनीकी अमले ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सोलर होम लाइट सिस्टम की मरम्मत की और नई बैटरी स्थापित कर उसे पुनः चालू किया। सिस्टम के पुनः कार्यशील होते

ही मरकाम के घर में फिर से उजाला फैल गया। अब उनका घर रात में रोशन रहने लगा है और पंखे की सुविधा बहाल होने से परिवार को गर्मी से राहत मिली है। दूरस्थ डुबान क्षेत्र में रहने वाले इस परिवार के लिए यह सुविधा बड़ी राहत लेकर आई है। श्री सियाराम मरकाम ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय से वे इस समस्या से परेशान थे, लेकिन अब उनके परिवार को बड़ी सुविधा मिल गई है और घर में फिर से सामान्य जीवन लौट आया है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री सहाय बिजली हर घर योजना 'सौभाग्य' सहित विभिन्न विद्युत एवं सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं के माध्यम से राज्य शासन लगातार यह प्रयास कर रहा है कि अंतिम छोर तक रहने वाले परिवारों को भी भरोसेमंद और सतत ऊर्जा सुविधा मिल सके।



डिजिटल अरेस्ट साइबर ठगी का बड़ा खुलासा: 54.40 लाख के लेनदेन वाले खाते के साथ पिता-पुत्र गिरफ्तार

● वरिष्ठ नागरिक महिला से 1.04 करोड़ की ठगी, नेपाल कनेक्शन भी आया सामने

बिलासपुर। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर करोड़ों रुपये की साइबर ठगी करने वाले अंतरराष्ट्रीय गिरोह के खिलाफ रेंज साइबर थाना बिलासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने महाराष्ट्र के भंडारा जिले से पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया है, जिनके बैंक खाते में साइबर ठगी की 54 लाख 40 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर होने का खुलासा हुआ है। आरोपी साइबर अपराधियों को म्यूल् अकाउंट उपलब्ध कराकर कमीशन के बदले ठगी की रकम ट्रांसफर कराने का काम कर रहे थे।



भंडारा जिले के गांधी वार्ड, वरठी थाना क्षेत्र के निवासी बताए गए हैं।

वरिष्ठ नागरिक महिला को बनाया निशाना

पुलिस जांच के अनुसार साइबर ठगों ने एक वरिष्ठ नागरिक महिला को व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो कॉल के माध्यम से संपर्क किया।

आरोपियों ने खुद को केंद्रीय जांच एजेंसियों का अधिकारी बताकर महिला को डरया कि उनका नाम एक आतंकवादी संगठन से जुड़ा हुआ है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ठगों ने महिला को लगातार मानसिक दबाव में रखते हुए तथ्यांकित डिजिटल अरेस्ट में रखा और गिरफ्तारी का भय दिखाकर विभिन्न बैंक खातों में कुल 1

करोड़ 4 लाख 80 हजार रुपये जमा करा लिए। पीड़िता की शिकायत पर रेंज साइबर थाना बिलासपुर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4), 308(6), 3(5) तथा आईटी एक्ट की धारा 66सी और 66ए के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई।

बैंक खाते की जांच से खुला राज

तकनीकी जांच और बैंक खातों के विश्लेषण के दौरान पुलिस को एक आईसीआईसीआई बैंक खाते में साइबर ठगी की 54.40 लाख रुपये की राशि प्राप्त होने की जानकारी मिली। इसी अहम सुरक्षा के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई तेज की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक बिलासपुर रेंज राम गोपाल गर्ग, उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह तथा नगर पुलिस अधीक्षक गगन कुमार के मार्गदर्शन में निरीक्षक कामिल हक के नेतृत्व में विशेष

साइबर टीम गठित कर महाराष्ट्र खाना किया गया।

2 प्रतिशत कमीशन के लालच में दिया बैंक खाता

साइबर पुलिस टीम ने भंडारा जिले के गांधी वार्ड स्थित निवास से आरोपी नेमतउल्लाह मंसूरी को हिरासत में लेकर पकड़ा। पकड़ाई में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने 2 प्रतिशत कमीशन पाने के लालच में अपना बैंक खाता साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराया था। जांच में यह भी सामने आया कि उक्त खाते का उपयोग डिजिटल अरेस्ट, शेयर ट्रेडिंग फ्रॉड तथा अन्य ऑनलाइन साइबर ठगी में किया जा रहा था। आरोपी ने यह भी कबूल किया कि वह नेपाल की राजधानी काठमांडू जाकर अपना बैंक खाता साइबर गिरोह के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराता था।

कलेक्टर-एसएसपी की अध्यक्षता में शान्ति समिति की बैठक

● ईद-उल-जुहा एवं मोहर्रम पर्व सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने का लिया गया निर्णय



स्थिति से निपटने एम्बुलेंस, आपातकालीन चिकित्सकों एवं अन्य सहयोगी कर्मचारियों का दल तैनात रखने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को पूर्व के दौरान निरंतर विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए। इसी प्रकार अन्य विभागों को जिम्मेदारी सौंपते हुए सजग रहने कहा गया। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी, एडीएम शिवकुमार बनर्जी, एडिशनल एसपी शहरी पंकज कुमार पटेल, एसडीएम मनीष साहू, सिटी मजिस्ट्रेट श्रीमती रजनी भागत, शांति समिति के सदस्य हबीब मेमन, सुधीर खंडेलवाल, मनजोत सिंह, चंचल सलुजा, डॉ. बसंत अंचल, प्रेम कलब के अध्यक्ष अनिल मिश्रा, अनिल शुक्ला सहित अन्य सदस्य एवं विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

बिलासपुर मंडल में प्रभावी रूप से जारी है नाका टिकट चेकिंग अभियान

● 487 मामलों में 3.10 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया



दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर मंडल द्वारा यात्रियों को सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं बेहतर यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने तथा वैध टिकट लेकर यात्रा करने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 21 मई से 14 जून 2026 तक विशेष नाका टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा पर प्रभावी निंत्रण स्थापित करने के साथ-साथ रेलवे राजस्व में वृद्धि एवं अधिकृत टिकटधारी यात्रियों को बेहतर यात्रा वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में

ट्रेनों की सघन जांच की गई। जांच के दौरान कुल 487 मामले दर्ज करते हुए कुल 73,10,395 का जुर्माना वसूला गया। जिसमें बिना टिकट यात्रा के 381 मामलों से 2 लाख 57 हजार 625 रुपये, अनियमित टिकट के 99 मामलों से 52 हजार 70 रुपये एवं बिना बुक किए गए लोको के 07 मामलों से 700 रुपये जुर्माने की वसूली किया गया। रेल प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा यह विशेष अभियान बेटिकट यात्रा करने वाले यात्रियों पर प्रभावी अंकुश लगाने में सफल साबित हो रहा है। इससे न केवल रेलवे के राजस्व में वृद्धि हो रही है, बल्कि वैध टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को त्रिफरा स्थित विद्युत मुख्यालय एवं सुविधाजनक यात्रा वातावरण भी उपलब्ध हो रहा है।

अवैध उत्खनन पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई

● 23 वाहन जब्त, 2 जेसीबी, 8 हाइवा और 13 ट्रैक्टर-ट्रॉली पर कार्रवाई



बिलासपुर। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश एवं उप संचालक खनिज किशोर गोलघाटे के मार्गदर्शन में जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर विभिन्न क्षेत्रों में जांच एवं कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान तेंदुआ, कोटा, चौरसही, कछर, लोफंदी, सेंदरी, निरतु, लखराम, गढ़वत, खैरखुंडी, लोखंडी, तुर्कांडीह एवं सकरी क्षेत्र में जांच की गई। जांच में अवैध रूप से खनिज रेत,

मिट्टी, मुरुम तथा गिट्टी डस्ट के उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त कुल 23 वाहनों को जब्त किया गया। कार्रवाई के तहत तेंदुआ एवं कोटा क्षेत्र में खनिज रेत का परिवहन करते हुए 4 हाइवा एवं 3 ट्रैक्टर पकड़े गए। वहीं कोटा क्षेत्र में खनिज मिट्टी का अवैध उत्खनन करते हुए 1 जेसीबी मशीन एवं 1 ट्रैक्टर जब्त किया गया। चौरसही क्षेत्र में मुरुम उत्खनन करते 1 जेसीबी एवं 1 हाइवा वाहन पर कार्रवाई की गई। इसी प्रकार लोखंडी क्षेत्र में रेत परिवहन करते 1 ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गई।

जिले में अवैध बोर खनन का खेल जारी, रात के अंधेरे में हो रहा भूजल दोहन

● बिल्हा, सिसप, नरगोड़ा, पचपेड़ी एवं मस्तुरी के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की अनदेखी का आरोप



बिलासपुर। जिले के सिसप, नरगोड़ा, बिल्हा, बरतौरी, पचपेड़ी और मस्तुरी सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में रात के अंधेरे में अवैध बोर खनन का सिलसिला लगातार जारी है। स्थानीय लोगों और सूत्रों का आरोप है कि कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों और प्रशासनिक नियमों की खुली अवहेलना करते हुए कुछ बोर मशीन संचालक, मालिक और दलाल रात में गुप्त रूप से बोरिंग कार्य करा रहे हैं। स्थानीय निवासियों के अनुसार, देर रात बोर मशीनों की आवाजों

दोहन किया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में भूजल स्तर तेजी से गिर रहा है। जानकारों का कहना है कि जिला प्रशासन और खनिज विभाग द्वारा समय-समय पर जारी चेतावनियों और प्रतिबंधों के बावजूद अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। आरोप है कि रात के समय यह कार्य इसलिए किया जा रहा है ताकि प्रशासनिक निगरानी से बचा जा सके। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने जिला प्रशासन, खनिज विभाग तथा पुलिस से मांग की है कि अवैध बोर खनन में संलिप्त व्यक्तियों की तत्काल पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही रात के समय सख्त गतिविधियों पर नजर रखने के लिए संयुक्त टीम गठित कर त्वरित छापेमारी अभियान चलाया जाए।



जिला देसहा साहू समाज: संतोष साहू निर्विरोध बने केंद्राध्यक्ष

बिलासपुर। सामाजिक संगठन को मजबूत करने और एकजुटता बढ़ाने के उद्देश्य से जिला देसहा साहू समाज द्वारा विगत 12 मई से सभी 10 केंद्रों में गहन बैठकों का दौर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज छत्तीस केंद्र में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वसहमति से पदाधिकारियों का चुनाव कर कार्यकारिणी का गठन किया गया।

प्रतिभाओं को सम्मानित करने की अपील

संभाग अध्यक्ष हरिशंकर साहू ने पूरी चुनाव प्रक्रिया को निर्विरोध संपन्न कराया और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों सौंपी। जिला अध्यक्ष बसंत साहू, जिला सचिव पुत्री राम साहू और जिला कोषाध्यक्ष उमाशंकर साहू ने अपने उद्बोधन में सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी। उन्होंने अपील की कि आगामी वार्षिकोत्सव और सामाजिक स्मारिका के लिए सभी केंद्र अध्यक्ष अपने-अपने क्षेत्रों से प्रतिभावान छात्रों (अच्छे अंक लाने वाले) और विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं के नाम भेजें, ताकि उन्हें सम्मेलन में सम्मानित किया जा सके।

31 मई तक सभी 10 केंद्रों के गठन का लक्ष्य

जिला संगठन द्वारा इस माह के अंत तक सभी 10 केंद्रों का गठन पूरा करने का दिशा-निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में आगामी बैठकों की घोषणा भी की गई। केंद्र क्रमांक 2 (कोडपुरी): 27 मई को साहू भवन में बैठक होगी। इसमें ग्राम सागर, लाखासारा, टाकुरकपा, केकड़ा, काठकोनी और मुरु के हजारों सामाजिक पदाधिकारी व जनसमुदाय शामिल होंगे।

अंधाधुंध बिजली कटौती के विरोध में कांग्रेस का विद्युत मुख्यालय घेराव

● तपती दुपहरी में जंगी प्रदर्शन, बिजली दो और मुख्यमंत्री इस्तीफा दो के लगे नारे



बिलासपुर। शहर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बिजली कटौती से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोमवार को त्रिफरा स्थित विद्युत मुख्यालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। भीषण गर्मी और तपती दुपहरी के बीच बड़ी संख्या में कांग्रेसजन हाथों में तख्तियां लेकर मुख्यालय पहुंचे और बिजली दो, जनता को रहल दो तथा मुख्यमंत्री इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा के मद्देनजर विद्युत मुख्यालय का मुख्य गेट बंद कर दिया गया। इस

बीच छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के बिलासपुर विद्युत क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक ए.के. अम्बस्थ और अधीक्षक अभियंता सुरेश जांगड़े कार्यालय से बाहर निकलकर गेट के समीप पेड़ की छंव में खड़े होकर प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया। आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि बिना

आंधी-तूफान और बारिश के भी शहर में दिन-रात अधोपिचत बिजली कटौती की जा रही है, जिससे आम नागरिकों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी में बिजली गुल होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस

कमेटी-1 के अध्यक्ष संतोष गर्ग ने कहा कि जनता नियमित रूप से टैक्स और बिजली बिल जमा कर रही है, इसके बावजूद उन्हें निर्बाध बिजली आपूर्ति नहीं मिल पा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि विद्युत व्यवस्था पूरी तरह चरमपा गई है और आम जनता परेशान है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्य गेट के सामने धरने पर बैठ गए और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए परिसर के आसपास पुलिस बल भी तैनात रहा। वहीं, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने सफाई देते हुए कहा कि विभाग द्वारा जानबूझकर बिजली कटौती नहीं की जा रही है।

समितियों में खाद-बीज का पर्याप्त भंडारण, किसानों से समय पर उठाव की अपील

● अकाश के दिन भी खुली रहेंगी सहकारी समितियां
● अब तक 5 हजार मीट्रिक टन खाद एवं 1590 किटल बीज वितरित



बिलासपुर। खरीफ वर्ष 2026 की खेती को सुचारू एवं समयबद्ध रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिले की सहकारी समितियों में रासायनिक उर्वरक एवं बीज का पर्याप्त भंडारण कर लिया गया है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी आवश्यकता के अनुसार अभी से खाद एवं बीज का उठाव सुनिश्चित करें, ताकि बोनी के समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। कृषि विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार खरीफ सीजन 2026 के लिए सहकारी क्षेत्र में कुल 44 हजार मीट्रिक टन रासायनिक उर्वरक वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत अब तक विभिन्न उर्वरकों का भंडारण किया गया है। जिसमें यूरिया 13,644 टन, डीएपी 4,065 टन, एनपीके 5,140 टन, एमओपी

781 टन, एसएसपी 1,595 टन शामिल हैं। इस प्रकार कुल 25,225 मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण समितियों में किया जा चुका है। वहीं अब तक किसानों को विभिन्न उर्वरकों का वितरण भी किया जा चुका है, जिसमें यूरिया 2,919 टन, डीएपी 798 टन, एनपीके 786 टन, एमओपी 91 टन, एसएसपी 194 टन वितरित किया जा चुका है। इस प्रकार कुल मिलाकर अब तक 4,788 मीट्रिक टन उर्वरकों का वितरण किसानों को किया जा चुका है तथा वितरण कार्य लगातार जारी है।

पूजा-अर्चना के साथ हुआ शुभारंभ

कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा और भक्त माता कर्मा के तैलचित्र पर पूजा-अर्चना और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। बैठक में जिला पदाधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति के बीच छत्तीस केंद्र के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के स्वजातीय वरिष्ठजन और युवा साथी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

संतोष साहू, उपाध्यक्ष: रमेश साहू, सचिव: अर्जुन साहू, कोषाध्यक्ष: चैतराम साहू, उपकोषाध्यक्ष: कौशल साहू, संयोजक: बलदाज साहू। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का समाज के वरिष्ठों द्वारा फूल-माला पहनाकर स्वागत और सम्मान किया गया। इस अवसर पर पूर्व जनपद सदस्य अशोक साहू ने कहा, यह आयोजन कई वर्षों के बाद पहली बार हुआ है, जिसके लिए केंद्र के सभी पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं।

सुशासन तिहार के समाधान शिविर में मिली योजनाओं की सौगात

● जनप्रतिनिधियों ने हितग्राहियों को किया लाभान्वित



बिलासपुर। सुशासन तिहार के तहत आज मंगला स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित समाधान शिविर में तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह एवं बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला शामिल हुए। उन्होंने शिविर में लगाए गए विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र हितग्राही तक प्रार्थमिकता से पहुंचे तथा किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को योजनाओं से वंचित न रहना पड़े। इस अवसर पर महापौर पूजा विधानी, नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे, जोन कमिश्नर रंजना अग्रवाल, पार्षद रमेश पटेल, हेमन्त मरकाम सहित अन्य

कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित अनेक जरूरी सेवाओं का लाभ लोगों को सरलता से मिल रहा है, जिससे आमजन को काफी सुविधा हो रही है। बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि शासन की योजनाएं समाज के अतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंगला क्षेत्र के दो वार्डों में लगभग 150 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिससे जरूरतमंद परिवारों को पक्के आवास का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 5 लाख रुपये तक के निःशुल्क उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से प्रतिमाह सहायता राशि प्रदान की जा रही है। महापौर पूजा विधानी ने कहा कि भीषण गर्मी के बावजूद शासन

स्वयं जनता के द्वार पहुंचकर समस्याओं का समाधान कर रहा है। समाधान शिविरों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग अब तक किसी योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए हैं, वे शिविरों में पहुंचकर जानकारी एवं लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शिविर में महिलाओं की गोदभर्राई, शिशुओं का अन्नप्राशन एवं श्रम विभाग द्वारा सहायता राशि वितरण जैसी विविधियां भी आयोजित की जा रही हैं, जिससे आमजन में उत्साह का वातावरण है। उन्होंने लोगों से शिविरों का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। नगर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने कहा कि समाधान शिविर के माध्यम से लोगों को योजनाओं का सीधे लाभ मिल रहा है।

छात्रावास अधीक्षकों ने खोला मोर्चा, बोले-अब नहीं दबेंगी मांगें



● संगठन विस्तार से आंदोलन तक की बनी रणनीति

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष उदेश सिंह तोमर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में संघ के पदाधिकारियों और अधीक्षकों ने छात्रावासों की बदहाल व्यवस्थाओं, सीमित बजट, बढ़ते क्वॉरंटर और लॉबित पदोन्नति मामलों पर नाराजगी जताई। अधीक्षकों ने कहा कि छात्रावासों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन सुविधाओं और संसाधनों में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही। इससे व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं और अधीक्षकों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता जा रहा है।

बैठक में सेवा शर्तों के निर्धारण, क्रमोन्नति-पदोन्नति, छात्रावास अनुरक्षण मद के लिए पर्याप्त बजट, विद्यार्थियों की शिथिलता राशि में वृद्धि तथा विभागीय समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। कई वक्ताओं ने कहा कि वर्षों से लॉबित मांगों पर केवल आश्वासन मिलते रहे हैं, जबकि जमीनी स्तर पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। संगठन को मजबूत करने के लिए संभाग स्तर पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जैसे नए पद सृजित करने पर सहमति बनी। साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी में विस्तार कर अधिक सक्रिय सदस्यों को जिम्मेदारी देने तथा जिला स्तर तक संगठनात्मक ढांचे को सशक्त बनाने का निर्णय लिया गया।

13 लाख की स्वीकृत सरपंच पति की लापरवाही के कारण शासन के पैसों की बर्बादी आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण में भ्रष्टाचार

बिलासपुर/मस्तूरी। मस्तूरी जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत बहतरा में 13 लाख की लागत से आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप सरपंच पति द्वारा कराया जा रहा है। किंतु मजदूरी मनरेगा के तहत है लेकिन काम करने वाले मजदूरों का उनके मेहनत राशि को सरपंच पति द्वारा अपने परिवारों के नाम पर मजदूरी चढ़ाकर शासन का रूपए राशि का आह्वान किया गया। जिसमें ग्रामीणों द्वारा मस्तूरी जनपद सीईओ एसडीओ एवं मनरेगा विस्तार अधिकारी से जांच कर सरपंच पति पर उचित कार्यवाही करने की मांग की गई है। आंगनबाड़ी केंद्र की नींव में गुणवत्ताहीन आंगनबाड़ी भवन में जो बीम डाला गया है वह दराय हो गई है। सामानों का उपयोग कर बिना मापदण्ड के बना दिया गया। जो आज तक नींव में लगाए गए कॉलम को जोड़ जोड़ कर बनाया जा रहा है। बहतरा पंचायत में सरपंच पति के रिस्तेदार पचायत सचिव भी हैं। उन्होंने अपनी ऊंचे पहुंच दिखाकर की लापरवाही के कारण शासकीय पैसों की बर्बादी ही हो रही है।

पंचायत द्वारा सरकारी पैसों की बर्बादी आंगनबाड़ी भवन निर्माण



की गुणवत्ताहीन को देखते हुए कई बार ग्रामीणों द्वारा सरपंच पति को कार्य को अच्छे से गुणवत्ता मजबूत बनाने की बात कही गई थी। लेकिन सरपंच पति ने अपने मनमानी करते हुए आंगनबाड़ी भवन को गुणवत्ताहीन बनाया जा रहा है। पंचायत द्वारा सरकारी पैसों की बर्बादी की जा रही

है। इस प्रकार बर्बादी करना और गुणवत्ताहीन पर क्या पंचायत सरपंच पति के ऊपर कार्यवाही होगी?

ग्रामीणों का कहना है की कुछ दिनों में पंचायत चुनाव होने वाला है और सरपंच को बार-बार बोलने ना गांव में

आते हैं और ना कार्य पूर्ण कवा रहे है। की ऐसे ही बहुत सारे कार्य में सरपंच सचिवों द्वारा लापरवाही कर शासन के पैसों का बंदबांट किया जा चुका है। आंगनबाड़ी निर्माण में भी धांधली का संदेह ग्रामीणों ने जताया। अब देखा है कि शासन इस पर किया कार्यवाही करते है।

भीषण गर्मी का असर : सिम्स में उल्टी दस्त के मरीज बढ़े

बिलासपुर। शहर में लगातार 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहे तापमान का असर अब लोगों की सेहत पर भी गंभीर रूप से दिखाई देने लगा है। भीषण गर्मी के चलते सिम्स और जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। खासकर मेडिसिन, शिशु रोग, नेत्र और त्वचा रोग विभाग में सबसे अधिक भीड़ देखी जा रही है।

सिम्स के मेडिसिन विभाग में रोजाना करीब 300 मरीज पहुंच रहे हैं। इनमें 20 से 25 मरीज डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉस्टशन, कमजोरी, चक्कर और लो ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं से पीड़ित हैं। डॉक्टरों के अनुसार तेज धूप में काम करने वाले मजदूर, बुजुर्ग और लंबे समय तक बाहर रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। कई मरीजों को गंभीर हालत में सलाइन चढ़ानी पड़ रही है।

शिशु रोग विभाग में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यहां प्रतिदिन लगभग 200 बच्चों की ओपीडी हो रही है, जिनमें 15 से 20 बच्चे उल्टी-दस्त, बुखार और पानी की कमी की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। चिकित्सकों ने बच्चों को बाहर का खाना और दूषित पानी से बचाने की सलाह दी है।

तेज धूप और धूल का असर आंखों पर भी देखने को मिल रहा है। नेत्र रोग विभाग में रोज



100 से अधिक मरीज इलाज कराने पहुंच रहे हैं। इनमें करीब 30 मरीज कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित पाए जा रहे हैं।

वहीं त्वचा रोग विभाग में घमौरी, खुजली, फंगल इन्फेक्शन और एलर्जी के मामलों में भी वृद्धि दर्ज की गई है। विभाग में रोजाना 100 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं, जबकि 5 से 10 मरीज गंभीर त्वचा संक्रमण की शिकायत लेकर आ रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अत्यधिक पसीना और उमस इसके प्रमुख कारण हैं।

सिम्स के एमएस ने बताया कि अत्यधिक तापमान और लंबे समय तक धूप में रहने से डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉस्टशन और फ्लूड-इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। शरीर से अत्यधिक पसीना निकलने पर सोडियम और पोटेशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिससे मरीजों में लो ब्लड प्रेशर, मसल क्रैम्प, कमजोरी, टैकोकार्डिया और चक्कर आने जैसी शिकायतें बढ़ रही हैं।

उन्होंने बताया कि कई मरीज पेट दर्द, मतली, उल्टी और दस्त जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं के साथ भी अस्पताल पहुंच रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों में डिहाइड्रेशन तेजी से गंभीर स्थिति ले सकता है। ऐसे में पर्याप्त पानी, ओआरएस और इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन जरूरी है। डॉक्टरों ने लोगों को दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने की सलाह दी है।

नकली नोट पकड़ने गई पुलिस और खुला मर्डर केस

बिलासपुर। मार्च 2023 में बिलासपुर पुलिस की एंटी क्राइम यूनिट को सूचना मिली थी कि उस्लापुर की गीताजलि कॉलोनी में नकली नोट छपाने का काम चल रहा है। जब पुलिस आरोपी पवन सिंह ठाकुर के किराए के मकान पर छापा मारने पहुंची, तो वहां से जाली नोट और नोट छपाने की मशीन बरामद हुई। टंकी से बदनू तलाशी के दौरान पुलिस को मकान के पोर्च/बाथरूम हिस्से में रखी एक पानी की टंकी से भयंकर बदनू आई। जब टंकी को खोला गया, तो उसमें प्लास्टिक और टेप में लिपटे हुए एक महिला के शव के 5 टुकड़े बरामद हुए। वह शव आरोपी की पत्नी सती साहू का था। चरित्र पर शक के कारण की थी।

आरोपी पवन सिंह ठाकुर अपनी 23 वर्षीय पत्नी सती साहू के चरित्र पर शक करता था। जनवरी 2023 में उसने गला घोटकर पत्नी की हत्या कर दी थी। लाश को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी ने बाजार से एक ग्राइंडर कटर मशीन और पानी की टंकी खरीदी। उसने शव के हाथ-पैर और धड़ काटकर अलग किए



और टंकी में छुपा दिए। दो महीने तक छुपाया राज: आरोपी हत्या करने के बाद करीब दो महीने तक उसी घर में रह रहा था। उसने आसपास के लोगों और रिस्तेदारों से झूठ बोला कि उसकी पत्नी किसी के साथ भाग गई है। वह खुद भी पुलिस के सामने पत्नी की गुमशुदगी का नाटक कर रहा था।

बिजली गुल... गुस्से में जनता! तिफरा काले सोने में बड़ा खेल... उच्च गुणवत्ता वाले कोयले को बिजली दफ्तर घेरने उतरेंगे लोग: विजय किया हल्का, प्लांट लेआउट ही खुला सिंडिकेट का राज

● कांग्रेस ने दी आर-पार आंदोलन की चेतावनी

बिलासपुर। भीषण गर्मी, उमस और बार-बार हो रही अघोषित बिजली कटौती ने अब लोगों का सब तोड़ दिया है। बेलतरा विधानसभा सहित पूरे बिलासपुर जिले में घंटों बिजली गुल रहने से परेशान जनता का गुस्सा अब खुलकर सामने आने लगा है। लगातार बिगड़ती बिजली व्यवस्था और विभागीय लापरवाही के विरोध में 25 मई को तिफरा स्थित मुख्य विद्युत कार्यालय का घेराव किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने इसे जनता बनाम लापरवाह बिजली विभाग की लड़ाई बताते हुए बड़े जनआंदोलन का ऐलान किया है।

पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष और बेलतरा विधायक प्रत्याशी विजय केशरवानी ने साफ कहा है कि बिजली विभाग की कुंभकरणीय नींद अब आंदोलन से ही टूटेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी सिर्फ बैठकों और



दावों तक सीमित हैं, जबकि जमीनी हकीकत यह है कि शहर से लेकर गांव तक लोग अंधेरे और गर्मी में रात काटने को मजबूर हैं। दावे बड़े... लेकिन हकीकत में अंधेरा कुछ दिन पहले बेलतरा विधायक द्वारा बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक

लेकर क्षेत्र में निर्बाध बिजली आपूर्ति का दावा किया गया था। कहा गया था कि कटौती पर नियंत्रण होगा और लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन हल्लात उल्टे और बदतर होते चले गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दिन हो या रात, बिना किसी सूचना के बिजली काट दी जाती है। कई इलाकों में घंटों सप्लाई बंद रहने से पानी की समस्या भी गहवने लगी है। इनवर्टर जवाब दे रहे हैं, छोटे कारोबारी परेशान हैं और छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे।

सवालों के घेरे में बिजली विभाग

लगातार कटौती के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बार-बार सुधार के दावों के बावजूद व्यवस्था पटरी पर क्यों नहीं लौट पा रही? क्या बिजली संकट के लिए तकनीकी खामियां जिम्मेदार हैं या फिर विभागीय लापरवाही? फिलहाल इतना तय है कि गर्मी और अंधेरे से परेशान जनता का गुस्सा अब खुलकर सड़कों पर उतरने वाला है।

● हिरी पुलिस की रेड में डिपो मालिक गिरफ्तार

बिलासपुर। जिले में कोयले के कारोबार के भीतर चल रहे कथित मिलावट सिंडिकेट पर हिरी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कोलडिपो मालिक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उच्च गुणवत्ता वाले कोयले में निम्न स्तर का कोयला मिलाकर सप्लाई की जा रही थी। मामला सामने आते ही उद्योग जगत और कोयला कारोबार से जुड़े नेटवर्क में सनसनी फैल गई। ब्रज आयरन एंड स्टील लिमिटेड, डिघोरा प्लांट में जैसे ही कोयले की लैब टेस्ट रिपोर्ट सामने आई, पूरे मामले का भंडाफोड़ हो गया। जिस कोयले को उच्च गुणवत्ता वाला बताकर भेजा गया था, उसकी गुणवत्ता जांच में भारी गिरावट पाई गई। इसके बाद हिरी पुलिस ने ताबडतोड़ कार्रवाई करते हुए कोलडिपो मालिक राम कुमार आर्य को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया।



SECL से निकला हाई ग्रेड कोयला रास्ते में बदल गया खेल!

मामले की शुरुआत तब हुई जब कोयला परिवहन और लिफ्टिंग का काम करने वाले आशीष केशरी ने पुलिस को लिखित शिकायत दी। शिकायत में बताया गया कि एसईसीएल रामपुर खदान से दो ट्रेलरों में जी-6 ग्रेड का उच्च गुणवत्ता वाला कोयला लोड कराया गया था। यह कोयला डीओ नंबर 3330081502 के जरिए ब्रज आयरन

एंड स्टील लिमिटेड, डिघोरा भेजा गया। दस्तावेजों में कोयले की गुणवत्ता 5500-5800 जीसीबी दर्ज थी, लेकिन प्लांट पहुंचने के बाद जब केमिस्ट ने परीक्षण कराया तो रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। जांच में कोयले की गुणवत्ता घटकर 4203 और 4220जीसीबी निकली। इसके बाद पूरे सप्लाई सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए।

पुलिस की एंटी और खुलने लगा पूरा खेल

मामले की गंभीरता को देखते हुए हिरी पुलिस तुरंत एक्टिव हुई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण मधुलिका सिंह और नाद पुलिस अधीक्षक डी.आर. टंडन के निर्देशन में पुलिस टीम ने घटनास्थल पहुंचकर जांच शुरू की।

उद्योगों तक पहुंच रहा था मिक्सिंग वाला कोयला?

पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही

उठ रहा है कि क्या यह सिर्फ एक खेप तक सीमित मामला था या फिर लंबे समय से उच्च गुणवत्ता वाले कोयले में निम्न गुणवत्ता का कोयला मिलाकर सप्लाई की जा रही थी। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं यह पूरा नेटवर्क सुनियोजित तरीके से औद्योगिक इकाइयों को नुकसान पहुंचाकर अवैध मुनाफाखोरी का जरिया तो नहीं बना हुआ था।

हिरी पुलिस की कार्रवाई से कोयला कारोबार में हलचल

कोयले की गुणवत्ता में हेराफेरी जैसे गंभीर मामले में हुई इस कार्रवाई के बाद जिले के कोलडिपो और परिवहन नेटवर्क में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 316(3), 317(2), 317(4) और 3(5) बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर कार्रवाई की है। हिरी पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं, संभावित सहयोगियों और सप्लाई चेन की भी गहन जांच में जुटी हुई है।

पुनरुद्धार के बाद भी बदहाल शहर के बिलासपुर के 117 ऐतिहासिक जलाशय आज अस्तित्व के संकट में

बिलासपुर। कभी शहर की पहचान, जल संरक्षण का प्रमुख आधार और सांस्कृतिक धरोहर माने जाने वाले बिलासपुर के ऐतिहासिक तालाब आज उपेक्षा, अतिक्रमण और प्रशासनिक उदासीनता के कारण अस्तित्व के संकट से जूझ रहे हैं। विडंबना यह है कि पिछले 10 वर्षों में तालाबों के सौंदर्यकरण, संरक्षण और विकास के नाम पर 25 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं। अधिकांश तालाब बदहाल हैं और कई जलाशय तो बेहिसाब गंदगी तथा जलकुंभी की चपेट में आ चुके हैं। शहर में लगभग 147 तालाबों का उल्लेख मिलता है, किंतु इनमें से 117 तालाब ही वर्तमान में दर्ज हैं। विशेषज्ञों और पर्यावरण प्रेमियों का मानना है कि लगातार बढ़ते अतिक्रमण, अनियोजित शहरीकरण और रखरखाव की कमी के कारण अनेक तालाब या तो पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं अथवा सिकुड़ते जा रहे हैं।



करोड़ों खर्च, फिर भी नहीं बदली तस्वीर

नगर निगम और प्रशासन द्वारा समय-समय पर तालाबों के संरक्षण के बड़े दावे किए गए। वर्ष 2007-08 से लेकर अब तक करोड़ों रुपये खर्च कर कॉंक्रीट घाट, पुल, फाउंटेन, लाइटिंग और सौंदर्यकरण जैसे कार्य कराए गए। लेकिन अधिकांश योजनाएं केवल निर्माण कार्यों तक सीमित

रह गईं। नियमित सफाई, जल संरक्षण और प्राकृतिक स्वरूप बचाने की दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं हुए। डीपूरा तालाब इस्का बड़ा उदाहरण बनकर सामने आया है। करोड़ों रुपये खर्च होने के बाद भी तालाब आज गंदगी, जलकुंभी और बदहाल व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि तालाबों की वास्तविक जरूरत संरक्षण और सफाई है, न कि केवल दिखावटी निर्माण।

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर पर संकट

गंगानगर, चांदमारी, कोतवाली, गांधी चौक और जूना बिलासपुर क्षेत्र के कई तालाब कभी शहर की जीवन्तरेखा माने जाते थे। ये जलस्रोत न केवल पेयजल और भूजल संरक्षण का आधार थे, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र भी रहे हैं। आज इन तालाबों पर अतिक्रमण, गंदगी और सीवेज का दबाव लगातार बढ़ रहा है। पर्यावरणविदों का

कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले वर्षों में शहर को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। तालाब केवल सौंदर्य का विषय नहीं, बल्कि भविष्य की जल सुरक्षा का आधार है।

प्रशासन व जनता दोनों की जिम्मेदारी

विशेषज्ञ मानते हैं कि तालाबों को बचाने के लिए केवल सरकारी योजनाएं पर्याप्त नहीं होंगी। इसके लिए जनभागीदारी, नियमित निगरानी और कठोर कार्रवाई की आवश्यकता है। अतिक्रमण हटाने, सीवेज प्रवाह रोकने, जलकुंभी सफाई और वर्षा जल संरक्षण जैसे कार्यों को प्राथमिकता देनी होंगी। बिलासपुर नगर की पहचान रहे थे। ये ऐतिहासिक तालाब आज मदद की पुकार कर रहे हैं। करोड़ों खर्च होने के बावजूद यदि जलाशय नहीं बच पाए, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता ही नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भूके साथ गंभीर लापरवाही भी होगी।

झारखंड से बुलाकर पति की गला रेतकर हत्या पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी खौफनाक साजिश

बिलासपुर। शहर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कल्याणी पत्नी ने अपने अवैध संबंधों के रास्ते से पति को हटाने के लिए खौफनाक साजिश रच डाली। महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर झारखंड से अपने पति को बिलासपुर बुलाया और फिर गला रेतकर उसकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने शव को सिरिगुट्टी क्षेत्र में रेलवे ट्रैक के किनारे कीचड़ में फेंक दिया और फरार हो गए। पुलिस ने इस अंधे कल्ल की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपियों को शिकंजे में ले लिया है। पैसों का लालच देकर बिलासपुर बुलाया की रिपोर्ट के अनुसार, सिरिगुट्टी थाना प्रभारी अभय सिंह बैसन ने बताया कि मृतक को पहचान विनोद लोंगा के रूप में हुई है, जो झारखंड का रहने वाला था। विनोद की पत्नी का झारखंड में ही किसी अन्य युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी और उसके व्वायफेंड ने एक सोची-समझी रणनीति



तैयार की। प्रेमी ने विनोद को झांसा दिया कि उसे बिलासपुर में किसी से मोटी रकम लेनी है, और इसी बहाने से 19 मई को पति-पत्नी को बिलासपुर बुला लिया गया। वारदात के बाद पत्नी अकेले लौटी घर बिलासपुर पहुंचने के बाद पत्नी, उसके प्रेमी और दो अन्य साथियों ने मिलकर सूनी जगह पर विनोद की गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद साक्ष्य छुपाने

के उद्देश्य से शव को रेलवे ट्रैक के पास कीचड़ और झाड़ियों में दबा दिया गया। वारदात को अंजाम देकर पत्नी चुपचाप अकेले झारखंड वापस लौट गईं। जब परिवार वालों ने विनोद के बारे में पूछा, तो उसने झूठ बोला कि विनोद बिलासपुर में ही काम पर लग गया है और वह एक महीने बाद बात करेगा। तकनीकी जांच और पुछताछ में खुला राज पत्नी के बयानों पर परिरजनों को गहरा संदेह हुआ, जिसके बाद उन्होंने झारखंड के स्थानीय थाने में विनोद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। झारखंड पुलिस की जांच और तकनीकी सर्विलांस के जरिए यह साफ हुआ कि महिला का व्वायफेंड भी उसी दौरान बिलासपुर में मौजूद था। संदेह के आधार पर जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तो पूरी साजिश का पर्दाफाश हो गया। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर सिरिगुट्टी थाना क्षेत्र से प्रेमी और दो अन्य साथियों ने मिलकर मृतक विनोद का शव-विश्रत शव बरामद कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

एचएससीएल के मंच पर यात्रा वृत्तांत एवं लघुकथा लेखन प्रतियोगिता के विजेता सम्मानित

जनधारा समाचार
भिलाई। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भिलाई-दुर्ग (नराकास) के तत्वावधान में एच.एस.सी.एल., भिलाई द्वारा आयोजित 'यात्रा वृत्तांत' एवं श्रमिक जीवन पर आधारित 'लघुकथा लेखन' प्रतियोगिता का पुरस्कार वितरण समारोह एच.एस.सी.एल. भिलाई के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भिलाई इस्पात संयंत्र के महाप्रबंधक (मानव संसाधन-आईआर एवं सीएलसी) तथा सचिव, नराकास भिलाई-दुर्ग राजीव कुमार थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता एच.एस.सी.एल. के उप महाप्रबंधक निशीथ कांति दास ने की।



इस अवसर पर तकनीकी सलाहकार (एच.एस.सी.एल.) वी. के. शाह, प्रतियोगिता के निर्णायक भिलाई इस्पात संयंत्र के उप प्रबंधक (संपर्क एवं प्रशासन-राजभाषा), जितेंद्र दास मानिकपुरी तथा भारतीय डाक विभाग, दुर्ग के सहायक अधीक्षक नितिन गोस्वामी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।

मुख्य अतिथि राजीव कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्रकार के साहित्यिक एवं राजभाषा संबंधी आयोजन प्रतिभागियों को नई ऊर्जा एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति का मंच प्रदान करते हैं। उन्होंने नराकास, भिलाई-दुर्ग के सक्रिय सदस्य संस्थान के रूप में एच.एस.सी.एल. द्वारा निरंतर प्रतियोगिताओं के आयोजन की सराहना करते हुए प्रतिभागियों से सतत सृजनशीलता एवं सक्रिय सहभागिता बनाए रखने का आह्वान किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए निशीथ कांति दास ने हिंदी के प्रति संस्थान की

प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि एच.एस.सी.एल. में कार्यालयीन कार्य हिंदी में किए जाते हैं तथा नराकास स्तर पर प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस प्रकार के आयोजन नियमित रूप से जारी रहें।

तकनीकी सलाहकार वी. के. शाह ने कहा कि हिंदी में कार्य करने से कार्यों में सरलता

एवं शीघ्रता दोनों आती हैं तथा नराकास स्तरीय आयोजन विभिन्न संस्थानों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने में सहायक सिद्ध होते हैं। उप प्रबंधक (संपर्क एवं प्रशासन-राजभाषा) जितेंद्र दास मानिकपुरी ने प्रतियोगिताओं के विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए प्रतिभागियों को उपयोगी सुझाव दिए। वहीं भारतीय डाक विभाग के सहायक अधीक्षक नितिन गोस्वामी ने प्रतिभागियों के उत्साह, लगन एवं रचनात्मक प्रयासों की सराहना की।

लघुकथा लेखन प्रतियोगिता में बीएसपी के शत्रुंजय तिवारी ने प्रथम, सहायक महाप्रबंधक विमल कुमार गोडम ने द्वितीय तथा उप महाप्रबंधक सुश्री अमृता गंगराडे ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वालों में भिलाई इस्पात संयंत्र के अनुभाग अधिकारी सुश्री ग्लोरी एस. पारकर, उप महाप्रबंधक आनंद, जूनियर इंजीनियरिंग एसोसिएट, सुश्री अनीशा कुमारी, टेक्नीशियन एस.आर.यू. अमितेश पुरोहित एवं इंजीनियरिंग एसोसिएट युवराज पैकरा शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन एच.एस.सी.एल. की राजभाषा अधिकारी सुश्री वंदना चौधरी द्वारा किया गया।

सड़क दुर्घटना में एक पैर गवां चुके मजदूर को सुशासन में मिला सहारा

● 20 वार्डों के 763 लोगों ने दिया आवेदन

जनधारा समाचार

रिसाली। नगर पालिक निगम रिसाली के सुशासन शिविर में सड़क दुर्घटना में एक पैर गवां चुके पुराने के दिनेश साहू को सहारा मिला। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्रकर ने बैटरी चलित ट्राई सायकल प्रदान किया। दिनेश साहू एक वर्ष से ट्राई सायकल लेने कार्यालय का चक्कर लगा रहा था। सोमवार को 20 वार्डों के लिए लगाए शिविर में कुल 763 आवेदन प्राप्त हुए।

दरअसल दिहाड़ी श्रमिक दिनेश हताश होकर पुराने के शिविर में पहुंचा था। वहां उसने दिव्यांगता का हवाला देते हुए अपनी पीड़ा क्षेत्रीय विधायक ललित चंद्रकर व कलेक्टर अभिजीत सिंह के समक्ष रखा था। दिनेश साहू का कहना था कि वह लगभग एक साल पहले सुबह-सुबह मजदूरी करने घर से निकला था। इसी बीच सिरसा रोड के निकट उसे हाड़वा ने अपने चपेट में ले लिया। जब उसकी आंख खुली तो वह अस्पताल में था और दाहिना पैर गायब था। पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठाने वाला दिनेश टूट चुका था। जैसे तैसे जपपुर में निर्मित पैर लगाने के बाद वह हिममत से चलना शुरू किया। उसकी इच्छा थी कि अगर बैटरी चलित ट्राई सायकल की मदद से वह फिर से कुछ कर सकता है, किन्तु दस्तावेजों के अभाव की वजह से ट्राई सायकल उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। कलेक्टर अभिजीत ने पीडित को गुहार सुनने के बाद उसे शीघ्र बैटरी चलित ट्राई सायकल दिलाने का आश्वासन दिया था। सोमवार के शिविर में दिनेश को दुर्ग



ग्रामीण विधायक ललित चंद्रकर ने ट्राई सायकल भेंट किया। शिविर का अवलोकन महापौर शशि सिन्हा, सभापति केशव बंधेरे, नेता प्रतिपक्ष शैलेन्द्र साहू ने किया। इस अवसर पर एचआईसी सदस्य सनीरा साहू, ममता यादव, जमुना ठाकुर, जहीर अब्बास समेत पार्षद शीला नारखेड़े, सविता डवस, रमा साहू, धमेन्द्र भागत, मनीष यादव, माया यादव, डॉ. सीमा साहू, विलास राव बोकर, विनय नेताम, परमेश्वर आदि उपस्थित थे।

विधायक ने समूह को सौंपा चेक: दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्रकर ने सुशासन शिविर में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने संचालित छत्तीसगढ़ महिला कोष से एक लाख का ऋण ममतलक साहयता समूह को उपलब्ध कराया। वहीं विधायक, महापौर शशि सिन्हा, सभापति केशव बंधेरे ने महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना के तहत ज्योति रावते, दीपा ठाकुर, कौशल्या कुर्से की गोद भराई रयत की।

आयुर्वेद प्राथमिक अस्पताल खोलने पहल: दुर्ग ग्रामीण विधायक ने नागरिकों को आश्वासन दिया कि रिसाली क्षेत्र में आयुर्वेदिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने वे पहल करेंगे।

यूनिवर्सल रेल मिल ने 3,867 टन उत्पादन कर बनाया नया सर्वश्रेष्ठ दैनिक उत्पादन कीर्तिमान

जनधारा समाचार
भिलाई। इस्पात संयंत्र के यूनिवर्सल रेल मिल (यूआरएम) ने रेल उत्पादन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए नया सर्वश्रेष्ठ दैनिक उत्पादन कीर्तिमान स्थापित किया है। 260 मीटर लंबे रेल पैनल का निर्माण करने वाले यूनिवर्सल रेल मिल ने 22 मई 2026 को आर 260-60ई 1 रेल प्रोफाइल में 462 ब्लूम्स के साथ कुल 3,867 टन रेल उत्पादन कर नया डे रिकॉर्ड बनाया। इस उपलब्धि के साथ मिल ने 12 मार्च 2025 को स्थापित 3,852 टन एवं 455 ब्लूम्स के पूर्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।



उपलब्धि में सहयोगी विभागों एसएमएस-2 एवं एसएमएस-3, ट्रेफिक, पीपीसी, आरसीएल, इंटरमैटेशन, ए एंड डी, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल, सेंट्रल मैकेनिकल टीमें तथा तृतीय पक्ष निरीक्षण एजेंसी राइट्स के महत्वपूर्ण सहयोग की भी सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यूनिवर्सल रेल मिल आने वाले समय में भी अनेक नई उपलब्धियां हासिल करेगा।

उल्लेखनीय है कि यूनिवर्सल रेल मिल का प्रमुख ग्राहक भारतीय रेलवे है तथा मिल द्वारा उत्पादित गुणवत्ता एवं समयबद्ध उत्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शत-प्रतिशत ग्राहक संतुष्टि सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्य किया जा रहा है। बीएसपी के यूनिवर्सल रेल मिल में निर्मित 260 मीटर लंबे रेल पैनल देश में रेलवे अवसंरचना के विस्तार एवं समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

दुर्ग टाउन जोन में लगा सुशासन शिविर

● पीएम सूर्यधर योजना की मिली जानकारी, 12 उपभोक्ताओं ने कराया रजिस्ट्रेशन



दुर्ग। छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दुर्ग क्षेत्र के अंतर्गत दुर्ग टाउन जोन के पुराना गंज मंडी प्रांगण दुर्ग में सुशासन तिहार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान केंद्र एवं राज्य शासन की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना पीएम सूर्य धर मुफ्त बिजली योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया। उपस्थित अधिकारियों द्वारा आम नागरिकों को सौर ऊर्जा अपनाने के फायदे और योजना से मिलने वाली सब्सिडी व लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई, साथ ही जगरूकता बढ़ाने के लिए पैम्पलेट भी वितरित किए गए। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत पावर कंपनी द्वारा मई 2026 को सौर माह (01 मई से

31 मई 2026 तक) के रूप में मनाया जा रहा है। शिविर में स्थानीय उपभोक्ताओं ने भारी उत्साह दिखाया और लगभग 35 उपभोक्ताओं ने योजना की बारीकियों को समझा व अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने की इच्छा जताई। अधिकारियों की मौजूदगी में ऑन-स्पॉट कार्रवाई करते हुए 12 उपभोक्ताओं का वेंडर के माध्यम से योजना के अंतर्गत सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। पावर कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि इस सौर माह का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को पीएम सूर्य धर मुफ्त बिजली योजना योजना से जोड़कर उनके बिजली बिल को शून्य करना और पर्यावरण संरक्षण में उनका भागीदार बनना है।

सड़क हादसे के मृतक की बेटियों की पढ़ाई का

भिलाई। अंचल की समाजसेवी मुस्लिम महिलाओं के संगठन अल मदद एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी ने सड़क हादसे के मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता दी और उनके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा लिया। सोसाइटी के पदाधिकारी हाल ही में चंद्रा-मौर्या टॉकीज के पास सड़क हादसे में जान गंवाने वाले सेक्टर-2 निवासी सलीम खान के सेक्टर-2, स्ट्रीट-16 कांस्ट्रक्टर नंबर 64 स्थित निवास पहुंचे। दुख की इस घड़ी में सोसाइटी की ओर से मृतक की पत्नी सलमा खातून को 15,000 की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया, जिससे उनके घर में राशन-पानी और दूसरी जरूरतें पूरी हो सकें। सोसाइटी की प्रेसिडेंट अंजुम अली ने बताया कि महकूम सलीम खान की तीन बेटियां हैं। सोसाइटी की ओर से इन तीनों बेटियों की स्कूली शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी उठाई है। जब तक बच्चियां पढ़ाई करेंगी, उनकी शिक्षा का पूरा खर्च सोसाइटी द्वारा वहन किया जाएगा।

सिद्धांत और गिडियन ने फतह किया 13,800 फीट ऊंचा सारपास

जनधारा समाचार

भिलाई। हिमालय की बर्फाली वादियों और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों के बीच भिलाई के दो ट्रेक्स के 'सार पास 2026' ट्रेक अभियान सफलतापूर्वक पूरा कर शहर का नाम रोशन किया है। यूथ हॉस्टल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (वाईएचआई) द्वारा आयोजित यह राष्ट्रीय स्तर का ट्रेकिंग कार्यक्रम 13 मई से 19 मई तक हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत पार्वती घाटी में आयोजित किया गया।



इस रोमांचक अभियान में देशभर के विभिन्न राज्यों और शहरों से लगभग 47 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। ट्रेक की शुरूआत सिवनीबाग स्थित बेस कैम्प से हुई, जहां से दल ने ग्रहान गांव, मिन-थाच, नारु कैम्पसाइट और बिस्केरी कैम्पसाइट जैसे दुर्गम पड़वालों को पार करते हुए करीब 13,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित सार पास तक का सफर तय किया।

अभियान के दौरान के. एस. सिद्धांत ने डिटी ट्रेक लीडर की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई। कठिन पहाड़ी मार्गों, बर्फाले त्रेक और बदलते मौसम के बीच उन्होंने प्रतिभागियों का मार्गदर्शन करने के साथ टीम समन्वय में भी अहम भूमिका निभाई। वहीं 59 वर्षीय बीएसपी कर्मचारी गिडियन सपाटे ने

अपने उत्साह, साहस और मजबूत इच्छाशक्ति से सभी को प्रभावित किया। उनकी ऊर्जा और सकारात्मकता युवा प्रतिभागियों के लिए भी प्रेरणा का केंद्र बनी रही। सार पास ट्रेक हिमालय के सबसे लोकप्रिय और चुनौतीपूर्ण ट्रेक्स में गिना जाता है।

घने जंगल, बर्फ से ढकी ढलानें, ऊंची चढ़ाईयां और मनमोहक प्राकृतिक दृश्य इस ट्रेक को बेहद खास बनाते हैं। पूरे अभियान के दौरान प्रतिभागियों ने कठिन मौसम परिस्थितियों का सामना करते हुए साहस और धैर्य का परिचय दिया। भिलाई लौटने पर सिद्धांत और सपाटे को मित्रों, ट्रेकिंग प्रेमियों एवं शुभचिंतकों द्वारा बधाइयां दी जा रही हैं। दोनों की इस उपलब्धि को युवाओं के लिए साहस, फिटनेस भूमिका निभाई। वहीं 59 वर्षीय बीएसपी कर्मचारी गिडियन सपाटे ने

जुआ खेल रहे पांच आरोपी गिरफ्तार

जनधारा समाचार
भिलाई। खुर्सीपार थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ताश-पती के जरिए जुआ खेल रहे पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से नगदी रकम, कार, मोबाइल फोन सहित करीब 16 लाख 70 हजार 615 रुपए का मशरूका जप्त किया गया है। कार्रवाई जुआ प्रतिषेध अधिनियम एवं बीएसपी की धाराओं के तहत की गई।



खुर्सीपार थाना प्रभारी आनंद शुक्ला ने बताया कि अनुसूच मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि जिन-1 सड़क-2, सेक्टर-11 स्थित एक मकान में कुछ लोग 52 पती ताश के जरिए रुपए-पैसों का दांव लगाकर जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर दृष्टादी दी। कार्रवाई के दौरान पांच आरोपियों को पकड़ा गया।

मौके से नगदी और वाहन जप्त: पुलिस ने आरोपियों के पास से 92 हजार 615 रुपए नगद, 4 मोबाइल फोन, 2 कार एवं अन्य सामान बरामद किया। जप्त वाहनों की कीमत करीब 15 लाख 75 हजार रुपए बताई जा रही है। वहीं मकान मालिक के कब्जे से प्लास्टिक की टेबल, कुर्सियां और

25 मई 2013 का दिन एक काले अध्याय के रूप में दर्ज : बदरुद्दीन भिलाई

भिलाई। छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्य मंत्री बदरुद्दीन कुरेशी ने, छत्तीसगढ़ के इतिहास में 25 मई 2013 का दिन एक काले अध्याय के रूप में दर्ज है। बस्तर क्षेत्र की झीरम घाटी में नक्सली हमले में प्रदेश के कई वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, कांग्रेस नेता तथा सुरक्षा बलों के जवान शहीद हो गए थे। इस भीषण हमले में वरिष्ठ नेता विद्या चरण शुक्ल, नंदकुमार पटेल, महेंद्र शर्मा, मोहम्मद अल्लाहनूर, उदय मुदलियार, गोपी माधवन, दिनेश पटेल, योगेंद्र शर्मा, अभिषेक गोलछ, गणपत नाथ, सदासिंह नाग, भार्गोशी नाग, मनोज जोशी, राजकुमार श्रीवास्तव, शहीद चंद्रहास ध्रुव के साथ कई जवानों सहित अनेक लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। यह घटना लोकतंत्र और मानवता पर एक बड़ा हमला माना जाता है।

झीरम घाटी शहदत दिवस पर प्रदेश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है तथा उनके बलिदान को स्मरण किया जाता है। यह दिवस हमें शांति, लोकतंत्र और जन सेवा के मूल्यों को मजबूत करने की प्रेरणा देता है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रति वर्ष 25 मई को झीरम श्रद्धांजलि दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां शहीदों की स्मृति में मौन रखकर उन्हें नमन किया जाता है।

कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जनदर्शन में सुनी आम लोगों की समस्याएं

● आवेदकों के मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देश



बालोद। संयुक्त जिला कार्यालय सभाकक्ष में आज आयोजित कलेक्टर जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न स्थानों से अपने मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु पहुंचे आम नागरिकों के लिए राहत भरा साबित हुआ। इस दौरान कलेक्टर श्रीमती मिश्रा ने जिले के विभिन्न स्थानों से पहुंचे लोगों से आत्मीय बातचीत कर उनकी मांगों एवं समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को तलब कर आवेदकों के मांगों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। जनदर्शन में बालोद विकासखण्ड के ग्राम खपरी के बिन्दु कुमार ने शिक्षा ऋण दिलाने, नंगटोला के लोहरराम ने कृषि भूमि का बंटवारा कराने,

बखसपुर निवासी तुलेश्वरी ने नया राशन कार्ड बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किए। इसी तरह बालोद विकासखण्ड के ग्राम जमरुवा सुखराम ने फसल क्षति का मुआवजा दिलाने, बोहारडीह के जमुना बाई ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, भंवर्मरा के सरपंच ने नहर नाली का सीमेंटीकरण कराने, रूप्पटोला के ग्रामीणों ने पक्की सड़क का निर्माण कराने एवं उसरीटोला के ग्रामीणों ने मुक्तिधाम में शेड निर्माण के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किए।

जनदर्शन में आज जिले के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में लोग कलेक्टर से मुलाकात करने पहुंचे थे।

आईटीआई मैदान के पास चिट्टा बेचते युवक गिरफ्तार

● दुर्ग पुलिस की नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई, आरोपी से चिट्टा और मोबाइल जप्त



जनधारा समाचार
भिलाई। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खुर्शीपार थाना पुलिस ने आईटीआई मैदान क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ चिट्टा बेचते एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से चिट्टा एवं मोबाइल फोन जप्त किया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना खुर्शीपार क्षेत्र अंतर्गत आईटीआई मैदान के पास एक व्यक्ति द्वारा चिट्टा बिक्री किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदेही युवक को पकड़ा।

तलाशी में मिला चिट्टा: पुलिस द्वारा पूछताछ एवं तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 05 ग्राम 650 मिलीग्राम अवैध मादक पदार्थ चिट्टा बरामद किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त विवो कंपनी का मोबाइल फोन भी जप्त किया गया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम आयान कुरेशी (19 वर्ष) निवासी उत्तम टॉकीज के पीछे, छवनी भिलाई बताया। आरोपी ने अवैध मादक पदार्थ अपने कब्जे में रखना स्वीकार किया।

मनरेगा से दुर्ग जिले में 68 हजार से अधिक श्रमिकों को मिल रहा रोजगार

● 3923 निर्माण कार्यों से गांवों में बढ़ा रोजगार, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास को मिली नई गति



जनधारा समाचार
दुर्ग। जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के माध्यम से ग्रामीण श्रमिकों को लगातार रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिले की ग्राम पंचायतों में संचालित निर्माण कार्यों से हजारों परिवारों को आजीविका का सहारा मिल रहा है, वहीं जल संरक्षण का ग्रामीण अधोसंरचना विकास को भी मजबूती मिल रही है।

वर्तमान में जिले में प्रतिदिन 68 हजार 641 श्रमिक मनरेगा कार्यों में रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। जिले की ग्राम पंचायतों में 3923 निर्माण कार्य संचालित हैं तथा मांग के आधार पर प्रतिदिन नए श्रमिकों को कार्य उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद पंचायतवार देखें तो जनपद पंचायत दुर्ग अंतर्गत 1048 गांवों में 15 हजार 227 श्रमिक कार्यरत हैं। इसी प्रकार

जनपद पंचायत धमधा अंतर्गत 1687 कार्यों में 29 हजार 695 श्रमिक तथा जनपद पंचायत पाटन अंतर्गत 1188 कार्यों में 23 हजार 719 श्रमिक रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। कुल 24 करोड़ 12 लाख 53 हजार रुपये की मजदूरी राशि जनपद पंचायतों एवं क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से भुगतानी का चुकी है। इसके अंतर्गत जनपद पंचायत दुर्ग में 8 करोड़ 99 लाख 78 हजार रुपये, जनपद पंचायत धमधा में 6 करोड़ 69 लाख 48 हजार रुपये तथा जनपद पंचायत पाटन में 6 करोड़ 28 लाख 98 हजार रुपये की राशि संबंधित श्रमिकों के खातों में जमा की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य क्रियान्वयन एजेंसियों के माध्यम से 2 करोड़ 14 लाख 29 हजार रुपये की मजदूरी राशि का भी भुगतान किया जा चुका है।



वार्डों में विशेष अभियान चलाया जा रहा
भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर में मौसमी बीमारियों को रोकथाम एवं नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रतिदिन अलग-अलग जोनों के वार्डों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। निगम की स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा डेंगू, मलेरिया एवं अन्य मच्छर जनित बीमारियों को रोकथाम हेतु लगातार कार्य किया जा रहा है। निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम क्षेत्र की नालियों, कुल्लरों, बाथरूमों एवं अन्य जलभराव वाले स्थानों पर पहुंचकर मच्छर उन्मूलन कार्य कर रही है। अभियान के तहत मैलाथियान, रेमिफास एवं जला ऑयल का छिड़काव कराया जा रहा है, ताकि मच्छरों के लार्वा को नष्ट किया जा सके और बीमारियां का फैलाव रोका जा सके। निगम प्रशासन द्वारा नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे अपने घरों एवं आसपास पानी जमा न होने दें, कुल्लरों की नियमित सफाई करें तथा स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें। निगम की टीम लगातार वार्डों में निगरानी करते हुए आवश्यक कार्रवाई कर रही है, जिससे शहर में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर बनी रहे।

GST रजिस्ट्रेशन नम्बर बनवाएं मात्र 3 दिन में

5 साल पुरानी ITR फाइल बनवाएं मात्र 5000/- में (ट्वाइसएप पर बनवाएं) www.onlytds.com

GST-Return प्रोजेक्ट रिपोर्ट TDS रिफंड CMA DATA MSME रजिस्ट्रेशन Food लाइसेंस

संपर्क - शेखर गुप्ता 9300755544, 8878655544

कार्यालय नगर पालिका परिषद बेमेतरा जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

क्र./638/न.पा./लो.नि.वि./2026-27 बेमेतरा दिनांक 25/05/2026

// मैन्युअल निविदा सूचना //

एल्ट द्वारा नगर पालिका परिषद बेमेतरा क्षेत्रांतर्गत निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों को मैन्युअल निविदा प्रपत्र 'अ' में आमंत्रित की जाती है। निविदा दर खोलने की तिथि 16.06.2026 को 4.30 बजे शाम तक।

कार्य का नाम	लागत राशि (लाख में)
वार्ड क्र. 16 में टिकेन्द्र साहू के घर से धनी टेंट वाले के घर तक	1.70 लाख

आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।

टिप :- उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि विस्तृत निविदा विवरण निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी विभागीय वेबसाइट http://uad.cg.gov.in पर डाउनलोड की जा सकती है एवं शाखा से कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है। निविदा आमंत्रण से संबंधित किसी भी प्रकार का संशोधन सूचना विभाग के वेबसाइट में प्रसारित की जावेगी, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद, बेमेतरा

बदलता बस्तर : भय से विश्वास और विकास तक

संपादकीय

क

भी गोलियों की आवाज, बारूदी सुरंगों और लाल आतंक से कांपने वाला बस्तर आज एक नए मोड़ पर खड़ा दिखाई देता है। जंगलों की खामोशी में अब विकास की हलचल सुनाई देने लगी है। सड़कें बन रही हैं, स्कूल खुल रहे हैं, पर्यटन की संभावनाएं आकार ले रही हैं और सबसे बड़ी बात यह कि लोगों के भीतर धीरे-धीरे भय की जगह विश्वास लौट रहा है।

लेकिन यह बदलाव केवल नेताओं के भाषणों और सरकारी दावों तक सीमित नहीं रह सकता। बस्तर का असली परिवर्तन तब माना जाएगा जब बरसात के दिनों में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और अबडूमाइ के वे गांव देश से कटना बंद होंगे, जहाँ आज भी बारिश आते ही सड़कें बंद जाती हैं और लोग हथकों तक अलग-थलग पड़ जाते हैं।

आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ कोई भीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल तक पहुँचाने के लिए खटिया, मोटरसाइकिल या कंधों का सहारा लेना पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को घंटों पैदल चलना पड़ता है। कई गाँव ऐसे हैं जहाँ एम्बुलेंस पहुँच ही नहीं सकती। इसलिए बस्तर में विकास का सबसे बड़ा पैमाना यही होगा कि क्या वहाँ के लोगों तक सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और संसार वास्तव में पहुँच पाया या नहीं।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रस्तुत 'बस्तर 2.0' विजन डॉक्यूमेंट

उम्मीद जरूर जगता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया यह विजन केवल एक योजना नहीं, बल्कि दशकों के संघर्ष के बाद उभरती नई उम्मीद का दर्शावेज माना जा रहा है। इसमें सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सिंचाई और निवेश जैसे कई बड़े लक्ष्य शामिल हैं।

दरअसल, बस्तर की कहानी केवल नक्सलवाद की कहानी नहीं रही। यह उस ऐतिहासिक उपेक्षा की कहानी भी है जिसमें शासन और विकास की पहुँच जंगलों के भीतर बसे आदिवासी समाज तक कभी पूरी तरह नहीं पहुँच पाई। इसी खालीपन का फायदा माओवादी संगठनों ने उठाया। गरीबी, बेरोजगारी और प्रशासनिक दूरी ने नक्सलवाद को जमीन दी। परिणाम यह हुआ कि बस्तर दशकों तक देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बना रहा। हालांकि अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। सुरक्षा बलों के लगातार अभियानों, नए कैम्पों, सड़क और मोबाइल नेटवर्क के विस्तार तथा आत्मसमर्पण नीति ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर किया है। बस्तर के लोगों के भीतर भी अब यह भरोसा पैदा होने लगा है कि नक्सलवाद का प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। लोगों के मन में एक तरह का सुकून लौटा है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है—क्या नक्सलमुक्त बस्तर वास्तव में विकसित बस्तर बन पाएगा? क्यों कि केवल सुरक्षा

अभियान स्थायी समाधान नहीं होते। विकास तभी दिखाई देता है जब आम आदमी की जिंदगी बदलती है। जब गांव तक सड़क पहुँचती है, जब बच्चे नियमित स्कूल जा पाते हैं, जब अस्पतालों में डॉक्टर मौजूद रहते हैं, जब लोगों को साफ पानी मिलता है और जब युवाओं को रोजगार के अवसर मिलते हैं। आज भी बस्तर के कई हिस्सों में यह बुनियादी बदलाव अचूरा है। यही वजह है कि सरकारी दावों के बीच जमीनी सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाल ही में बैलाडीला क्षेत्र से दो ट्रकों में लौह अयस्क की कथित तस्करी पकड़े जाने की खबर यह भी दिखाती है कि बस्तर केवल विकास की कहानी नहीं, बल्कि संसाधनों की लड़ाई का क्षेत्र भी बना हुआ है। खनिज संपदा से समृद्ध यह इलाका लंबे समय से बाहरी हितों और स्थानीय जरूरतों के बीच संघर्ष का केंद्र रहा है।

बस्तर का मूल स्वभाव हमेशा शांत, सामुदायिक और प्रकृति से जुड़ा रहा है। नक्सलवाद ने इस सामाजिक संरचना को गहरे स्तर पर प्रभावित किया। अब जब हिंसा कम हो रही है तो यह अवसर है कि बस्तर अपनी मूल पहचान को फिर से हासिल करे। लेकिन इसके लिए केवल खनन और बड़े निवेश पर्याप्त नहीं होंगे। जरूरी यह है कि विकास का केंद्र वहाँ का आदिवासी समाज बने। जल, जंगल और जमीन पर उनका अधिकार सुरक्षित रहे। स्थानीय लोगों को केवल दर्शक नहीं, बल्कि विकास प्रक्रिया का भागीदार

बनाया जाए। क्योंकि इतिहास गवाह है कि संवाद और संवेदनशीलता के बिना थोपा गया विकास नए असंतोष को जन्म देता है। पर्यटन, कृषि, वन उत्पाद, हस्तशिल्प और स्थानीय संस्कृति बस्तर की सबसे बड़ी ताकत हैं। चित्रकोट, तीर्थगढ़, कांगेर घाटी और अबडूमाइ जैसे क्षेत्र देश-दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर बड़ी पहचान बना सकते हैं। यदि बुनियादी ढांचा मजबूत होता है तो यह इलाका इको-टूरिज्म और सांस्कृतिक पर्यटन का बड़ा केंद्र बन सकता है। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पलायन कम होगा।

आज बस्तर एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है। बंदूक की आवाज धीमी पड़ी है, लेकिन विकास की असली परीक्षा अभी बाकी है। सड़क बनाना आसान है, भरोसा बनाना कठिन। पुल-पुलिया खड़ी करना संभव है, लेकिन लोगों के मन में राज्य के प्रति विश्वास पैदा करना सबसे बड़ी चुनौती है। यदि सरकार सुरक्षा, विकास और संवेदनशीलता इन तीनों के संतुलन को बनाए रखती है, तो आने वाले वर्षों में बस्तर सचमुच देश के सबसे विकसित और संभावनाशील संभागों में शामिल हो सकता है। तब 'बदलता बस्तर' केवल एक सरकारी नारा नहीं रहेगा, बल्कि भारत के लोकतांत्रिक विकास मॉडल की एक सफल मिसाल बन जाएगा।

हो. वे. शेषाद्रि : जीवन, मूल्य और संघ की दायित्व-परंपरा

-कैलाश चन्द्र

(जन्म-जयन्ती 26 मई के उपलक्ष्य में विशेष लेख)

हो.. वे.. शेषाद्रि जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उस धारा के तेजस्वी प्रवाह हैं, जिसमें व्यक्तिगत पद नहीं-कर्तव्य और उत्तरदायित्व ही प्रधान होते हैं। उनका जीवन सतत तप, अध्ययन, संगठनशीलता और राष्ट्रनिर्माण के संकल्प से ओतप्रोत रहा। 26 मई की उनकी जन्म-जयन्ती हमें याद दिलाती है कि संस्कृति, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण कैसा होता है।

मूलतः कर्नाटक के निवासी शेषाद्रि जी का प्रारंभिक जीवन सादगी, अध्ययन और तेजस्वी बुद्धि के लिए जाना जाता है। वे प्रारम्भ में ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के संपर्क में आये और विद्यार्थी जीवन में ही संघ प्रचारक बनने का निर्णय लिया। संघ की शाखा उनके लिए केवल वैचारिक प्रशिक्षण का स्थल नहीं, बल्कि व्यक्तित्व-निर्माण की प्रयोगशाला बन गई।

एक प्रचारक के रूप में उन्होंने दक्षिण भारत में संगठन के विस्तार, कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन और समाजजीवन में समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे 1960-70 के दशक का संगठनात्मक संघर्ष हो या 1975 के आपातकाल का दौर, उन्होंने अद्भुत धैर्य, अनुशासन और सूक्ष्म दृष्टि से कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया।

संघ में 'पद नहीं, दायित्व' की परंपरा और शेषाद्रि जी का आदर्श: संघ की परंपरा में पद का आग्रह नहीं, दायित्व का निर्वाह ही मूल विषय रहा है। शेषाद्रि जी इसका जीवंत उदाहरण थे। दायित्व स्वीकारने में विनम्रता और संघीय परंपरा का अनुपम प्रसंग 1990 के दशक के अन्त में, जब चौथे सरसंगचालक: प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह (रज्जु भैया जी) स्वास्थ्यगत कारणों से अवकाश चाहते थे, तब अनेक कार्यकर्ताओं का मत था कि शेषाद्रि जी को यह सर्वोच्च दायित्व दिया जाए। परन्तु शेषाद्रि जी ने विनम्रता और आत्मावलोकन के स्वर में कहा

'स्वास्थ्य ऐसा नहीं कि यह दायित्व निभा सकूँ। युवा कार्यकर्ता को अवसर मिलना चाहिए।' यह मात्र विनम्रता नहीं थी, बल्कि उस गहन परंपरा का विस्तार था, जिसमें व्यक्ति नहीं, संगठन की आवश्यकता प्रधान होती है। अंततः सर्वोच्च दायित्व सुदर्शन जी को दिया गया, और शेषाद्रि जी ने सह-संस्थापक एवं प्रचारक प्रमुख के रूप में पूर्ण निष्ठा से उनके साथ सहयोग के नाते कार्य किया।

संघ परंपरा का ऐतिहासिक अनुकरण: यह परंपरा संघ के प्रारम्भ से ही प्रवाहित है। पहले सरसंगचालक केशव बलिराम हेडगेवार ने स्वयं कहा था 'मुझे अधिक योग्य कार्यकर्ता मिलते ही यह दायित्व उसे सौंप दूँगा।' द्वितीय सरसंगचालक एम एस गोलवरकर (श्री गुरुजी) को भी नियुक्ति के पश्चात ज्ञात हुआ; उन्होंने कहा 'यह दायित्व मेरा व्यक्तिगत नहीं, संगठन का है।' तृतीय सरसंगचालक बाला साहब देवरस ने स्वास्थ्य कारणों से स्वयं दायित्व त्यागने का आग्रह किया।

शेषाद्रि जी दायित्व की गरिमा के संरक्षक:



शेषाद्रि जी के जीवन में यह परंपरा कई बार प्रकट हुई। एक महत्वपूर्ण प्रसंग 'दोनों ओर 'वरिष्ठ-कनिष्ठ' नहीं, केवल 'कार्यकर्ता' ही दिखता था।

प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जु भैया) जब सरकारीवाह थे तब शेषाद्रि जी क्षेत्र प्रचारक थे। कुछ ही वर्षों में शेषाद्रि जी मात्र सरकारीवाह बने तो रज्जु भैया सह सरकारीवाह रहे। उसके 7-8 वर्ष पश्चात रज्जु भैया संघ के सरसंगचालक बने और शेषाद्रि जी ने उनके नेतृत्व में पूर्ण निष्ठा से कार्य किया।

इस लेख के लेखक के कथनानुसार :-मैंने स्वयं देखा है कि शेषाद्रि जी ने सरसंगचालक रज्जु भैया जी का कर्तव्य स्वयं तुरपाई कर पहना।-क्षय केवल शारीरिक सेवा नहीं थी। यह आत्मीयता, सौहार्द, अहंकार-शून्यता और कर्तव्यनिष्ठा की पराकाष्ठा है। संघ की जइं इसी भावभूमि में गहरी है।

संघ के पाँच महान दायित्व-पुरुष: पद की नहीं, कर्तव्य की परंपरा नीचे संघ के पाँच शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं का 'दायित्व-दर्शन'

डॉ. हेडगेवार: संगठन का दायित्व सर्वोपरि- डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का जीवन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संघ का मूल आधार पद की प्रतिष्ठा नहीं कर्तव्य की पूर्णता है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक ऐसे संगठन के निर्माण में लगाया जिसमें 'व्यक्ति' नहीं, 'व्यवस्था' प्रमुख हो।

उनकी दृष्टि स्पष्ट थी। दायित्व उसी को मिले जो सक्षम, समर्पित और परिस्थिति के अनुकूल हो। दायित्व छोड़ना भी उनका ही पवित्र है जितना दायित्व स्वीकारना।

इसलिए वे बार-बार कहते थे- 'संघ व्यक्ति पर नहीं,

संघ-व्यवस्था पर चलता है।'

श्री गुरुजी : दायित्व को तप में रूपांतरित करने वाले माधवराव सदाशिव राव गोलवलकर (श्री गुरुजी) को दायित्व ग्रहण करने की सूचना डॉ हेडगेवार जी के निधन पश्चात पत्र के माध्यम से मिली है। यह बताते समय वे भावुक हो उठे- 'यदि संघ को यही अपेक्षित है, तो मैं अपना स्वत्व निष्कार करता हूँ।' उनका पूरा जीवन तप, विचार-गहराई, संगठन की सुगंध और कर्तव्य की पूर्णता का प्रतीक रहा।

बाला साहब देवरस: दायित्व में प्रयोगशीलता और व्यावहारिक दृष्टि बाला साहब देवरस ने दायित्व को निरंतर गतिमान रखा-

सामाजिक समरसता, अस्पृश्यता-उन्मूलन, राष्ट्रीय स्तर पर संगठन विस्तार में उनका योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा 'संगठन की शक्ति सेवा से बढ़ती है, पद से नहीं।'

रज्जु भैया : सरलता, सहजता और दायित्व की पवित्रता: प्रो. राजेन्द्र सिंह (रज्जु भैया) जैसे विद्वान, वैज्ञानिक दृष्टि वाले और अत्यंत सरल व्यक्तित्व में 'दायित्व' स्वभाव की तरह था, पद की तरह नहीं। उन्होंने बार-बार कहा- 'दायित्व मेरा नहीं-संघ का है।' स्वास्थ्य बिगड़ने पर उन्होंने स्वयं दायित्व छोड़ने का आग्रह किया-यह संगठन-केंद्रित सोच का सर्वोच्च उदाहरण है।

सुदर्शन जी : अनुशासन, परिश्रम और दायित्व की श्रेष्ठता

सुदर्शन जी का जीवन कठोर अनुशासन, बौद्धिक ताजगी और निरंतर संगठन-प्रयास का प्रतीक था। वे स्पष्ट कहते थे- 'दायित्व कभी हल्का नहीं होता, परंतु स्वयंसेवक उसे आनंद से निभाता है।' उन्हें जब सर्वोच्च दायित्व मिला तो वे भी उतने ही विनम्र थे जितने कि प्रचारक अवस्था में।

हो. वे. शेषाद्रि और रज्जु भैया एक-दूसरे के लिए आदर्श सहयोगी एक ओर रज्जु भैया का सौम्य नेतृत्व, दूसरी ओर शेषाद्रि जी की बौद्धिक शक्ति-दोनों ने मिलकर दक्षिण और उत्तर भारत के बीच संगठनात्मक सेतु बनाया।

रज्जु भैया कहते थे- 'शेषाद्रि जी संगठन की सर्वोत्तम स्मृति और बुद्धि हैं।' शेषाद्रि जी कहते थे- 'रज्जु भैया सरलता की प्रतिमूर्ति हैं-जो सीखा, उनसे ही सीखा।- दोनों संबंधों में स्पष्ट नहीं, केवल सहयोग था। यह संघ-परंपरा का अद्भुत उदाहरण है।

शेषाद्रि जी के ग्रंथ-विचार, नीति और युग-चिंतन की निधि

शेषाद्रि जी केवल संघ के शीर्ष संगठनकर्ता ही नहीं, बल्कि अत्यंत गहन विचारक, इतिहास-विश्लेषक और लेखन-कुशल अध्येता थे। उन्होंने समाज, इतिहास, राष्ट्रीय अस्मिता और संगठन पर अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे।

उनके लेखन की तीन विशेषताएँ खड़ी होती हैं-सुस्पष्ट विश्लेषण, सरल भाषा, तथ्यों पर आधारित दृष्टि।

'राष्ट्र निर्माण की दिशा'

इस महत्वपूर्ण विषय को अनेकों कृति में उन्होंने बताया कि भारत का राष्ट्र-निर्माण केवल राजनीतिक क्रिया न होकर एक संस्कृति-आधारित प्रक्रिया है। उन्होंने शिक्षा, समाज-संगठन, सेवा, समरसता और संस्कारों को राष्ट्र निर्माण के पाँच आधार-स्तंभ बताया।

'भारत की राष्ट्रीय पहचान'

यह पुस्तक भारतीय राष्ट्र की आध्यात्मिक-ऐतिहासिक यात्रा को समझने के लिए अमूल्य है। इसमें उन्होंने सिद्ध किया कि-

भारत केवल भौगोलिक इकाई नहीं; बल्कि संस्कृति-समृद्ध, मूल्य-संपन्न सभ्यता और निरंतरता का चमत्कार है। उनकी विश्लेषण शैली अकादमिक होते हुए भी सरल है-यह उनकी सबसे बड़ी लेखन शक्ति है।

'संघ : एक परिचय'

संघ के उद्देश्य, कार्यपद्धति, संगठनात्मक रूप, शाखा-जीवन और राष्ट्र-चिंतन का सरलतम रूप में परिचय देने वाली यह पुस्तक सदैव लोकप्रिय रही है। ये पुस्तक उन जिज्ञासुओं के लिए बने विशाल सेतु का कार्य करती है जो संघ के बारे में निष्पक्ष, स्पष्ट और विश्वसनीय जानकारी चाहते हैं।

इस ग्रंथ में शेषाद्रि जी ने हिंदू समाज के पुनर्जागरण की वैश्विक प्रक्रिया का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि 'हिंदू पुनर्जागरण' केवल धार्मिक जागरण नहीं-बल्कि सांस्कृतिक स्वामिभवन, सामाजिक समरसता, राजनीतिक आत्मविश्वास का समेकित स्वरूप है।

निबंध-संग्रह और व्याख्यान-समाहार

उनके विभिन्न व्याख्यान-आपातकाल, भारतीय

राजनीति, समाज-संगठन, शिक्षा और राष्ट्र-चिंतन पर केंद्रित रहे। इन संग्रहों में वाक्य-शक्ति, तथ्य-निष्ठा और विश्लेषण-गहराई अद्वितीय है। पूजनीय श्री गुरुजी के मार्गदर्शन पर कृतिरूप संघ दर्शन और विचार नवनीत का अनेखा संयोजन एवं संकलन भी अनुपम कृतियों में से है।

संक्षेप में शेषाद्रि जी की कृतियाँ विचार-जगत की निधि और राष्ट्र-चिंतन के विश्वसनीय दस्तावेज हैं।

जहाँ कार्य ही पूजा है-वहाँ दायित्व ही गौरव है

शेषाद्रि जी, रज्जु भैया, सुदर्शन जी, श्री गुरुजी, देवरस जी और डॉ. हेडगेवार इन सभी व्यक्तियों ने हमें एक बात सिखाई है। संगठन का कार्य पद से बढ़ा है। पद का त्याग भी उनका ही पवित्र है जितना पद का स्वीकार। स्वयंसेवक का गौरव उसकी विनम्रता से बढ़ता है, अधिकार से नहीं। राष्ट्र-जीवन के इस विराट यज्ञ में इन महापुरुषों का अविनाशक इतिहास का विषय नहीं। यह वर्तमान और भविष्य दोनों की दिशा है। शेषाद्रि जी की जन्म-जयन्ती पर यही संकल्प जगता है कि हम पद के पीछे नहीं-कर्तव्य के पीछे चलें। पद नहीं, दायित्व ही हमारा स्वभाव बने। कार्य ही हमारी पूजा बने।

व्याप्य

दुमदार जी की दुम

सुशांत सुप्रिय

आज मैं आपको एक विश्व-प्रसिद्ध दुम की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी किसी ऐसे-ऐसे व्यक्ति की नहीं है। यह कहानी दुमदार जी की है। दुमदार जी का असली नाम कोई नहीं जानता। बचपन से ही दुमदार जी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। चमचागिरी, चापलूरी, चाटुकारिता और मखन लगाने में उनका कोई सानी नहीं थी। हेराना की बात यह है कि उनके पिता बेहद ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ स्कूल-मास्टर थे जो दुम हिलाने का पाम समझते थे। ऐसे परिवार में पैदा हो कर भी दुमदार जी ने हिम्मत नहीं हारी। दुम हिलाने की कला उन्हें विरासत में नहीं मिली थी। यह कला उनकी 'जीन्स' में नहीं थी। उनकी आनुवंशिकी इससे वंचित थी। लेकिन उन्होंने इस अड़चन को अपनी सफलता की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। अपने परिवेश और समाज से निरंतर शिक्षा ग्रहण करते हुए अंत में वे इतने बड़े दुमबाज बन गए कि लोगों ने उनका नाम ही दुमदार जी रख दिया। इस लिहाज से दुमबाजी में वे एक 'सेफल-मेड' व्यक्ति थे।

दुमदार जी प्रागैतिहासिक काल में पूर्वजों के पास पाई जाने वाली विलुप्त पूँछ हिलाने में माहिर थे। दुम हिलाने की फूहड़ सड़क-छापने के टुकड़े स्तर से उठा कर उसे ललित-कला के स्तर तक पहुँचाने में श्री दुमदार जी का अद्भुत योगदान भुलाया नहीं जा सकता। अखिल भारतीय दुमदार महासभा के पहले अधिवेशन में उनका ऐतिहासिक भाषण मील का पत्थर साबित हुआ। 'दुनिया के दुमबाजों, एक हो जाओ' और 'दुम नहीं तो दम नहीं' जैसी उनकी उक्तियाँ लोकप्रिय उद्गरण बन गए। 'सफलतापूर्वक दुम कैसे हिलाएँ' शीर्षक दुमबाजों की बीच हिलती पूँछ-सी फैली। इसे कुदरत का कौशल्या और भगवान का वरदान माना गया। इस महान दुम के दर्शन के लिए अपार जन-सेलाब उमड़ पड़ा। लोगों को आपस में यह कहते हुए सुना गया - 'जरूर दुमदार जी ने पूर्व-जन्म में दुमबाजी के अर्थे कर्म किए होंगे। इसीलिए भगवान दुमश्री महाराज ने उन्हें यह फल दिया है।' इस तरह देखते-ही-देखते दुमदार जी जग-प्रसिद्ध हो गए। शोहरत के साथ सम्मान और धन भी आया। दुमदार जी के दिन फिर गए।

इतिहास में कहीं ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता जब किसी आदमी की दुम निकल आई हो। लिहाजा अरबों में एक होने की जगह से दुमदार जी राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति-प्राप्त हो गए। उनकी महान दुम को 'राष्ट्रीय धरोहर' की संज्ञा दी गई। उन्हें अनेक सम्मानों से अलंकृत किया गया। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में दुमदार जी को 'दुम-विभूषण' की उपाधि देने की घोषणा की। विपक्ष के नेता भला क्यों पीछे रहते। उन्होंने भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में दुमदार जी को 'दुम केसरी' की उपाधि से नवाजा। राष्ट्रपति जी ने भी राष्ट्रपति-सर्वे के प्रांगण में आयोजित एक भव्य समारोह में महाप्रतिम दुमदार जी को देश के सर्वोच्च सम्मान 'दुम-रत्न' से अलंकृत किया। 'दुम-रत्न दुमदार जी, अमर रहे', 'अमर रहे' के नारों से आकाश गूँज उठा।

दुमदार जी की हिलती दुम की ख्याति दिन-दोनी, रात-चौनी बढने लगी। सरकारी खर्च पर करोड़ों रुपयों में दुमकी दुम का बीमा कराया गया। उनकी दुम की सुरक्षा के लिए 'नेशनल सेक्युरिटी गार्ड' के जॉबाज कमांडो नियुक्त किए गए। यूनिसेफ ने उन्हें अपना 'गुडविल अंबेसेडर' बना लिया। दुमदार जी की दुम को दुनिया का आदर्श आश्चर्य माना गया। विदेशी शासनाध्यक्षों के भारत आगमन पर दुमदार जी से मिलना उनके कार्यक्रम का अभिन्न भाग बन गया। हालाँकि कुछ लोग जरूर दबी जुबान से दुमदार जी की दुम को 'ईश्वर का दंड' या 'दैवी प्रकोप' बताते थे। पर ऐसे लोग केवल मुट्ठी भर थे। इन्हें विदेशी एजेंट या राष्ट्र-द्रोही कहा जाता था।

एक बार दुमदार जी की महान दुम को चोट लग गई। पूरा राष्ट्र हतप्रभ रह गया। लोग रसब और शोकाकुल थे। इसे दुमदार जी के विरोधियों का षडयंत्र माना गया। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजा-घरों में दुमदार जी की दुम की सलामती के लिए विशेष प्रार्थना-सभाएँ आयोजित की गई तथा नमाज पढ़ी गई।

कविता संसार

बेटियों के जल्लादों का हिसाब कब?



संजय एम तराणेकर

बेटियों के जल्लादों का हिसाब कब होगा, ये सोई हुई व्यवस्था का जवाब कब होगा। हर रोज़ कहीं मासूमियत कुचली जाती है, इसाफ़ की चौखट पर क्यों चुपी छती है।

यू आँखों में आँसू लिए माँ पूछ रही है अब, इन दरिंदों पर कानून का प्रहार होगा कब। क्या? टवीशा, क्या? दीपिका एवं अब अनु, इन देश के लोभियों को कहीं-कहीं पे गिनु।

नारे तो बहुत गूँजते रहते चौक-चौराहों पर, लेकिन क्यों? सत्राटा है सत्ता की राहों पर। कब जागेगी मानवता, यू शर्मिदा होगा मन, बेटियों के जल्लादों को नसीब न हो कफ़न।

बेटी तो घर की रौशनी, जीवन का सम्मान, उससे ही तो महकता है हर आँगन-जहान। जो हाथ उठे बेटियों पे, वो हाथ झुकेंगे अब, इन अत्याचारों का आखिर अंत होगा कब?

क्या गाय को 'राष्ट्रीय पशु' घोषित करने में कोई समस्या है?

-महेन्द्र तिवारी



भारत में गाय केवल एक पशु नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक चेतना

और ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा मानी जाती है। भारतीय समाज में सदियों से गाय को माता का दर्जा दिया जाता रहा है। अनेक धार्मिक ग्रंथों, लोक परंपराओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाय का विशेष महत्व रहा है। यही कारण है कि समय समय पर गाय को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठती रही है। कई धार्मिक संगठनों, सामाजिक समूहों और कुछ राजनीतिक दलों ने यह मांग सार्वजनिक रूप से रखी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी एक मामले की सुनवाई के दौरान गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की आवश्यकता पर टिप्पणी की थी। इसके बावजूद भारत सरकार ने अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। इसके पीछे केवल राजनीतिक कारण नहीं बल्कि सामाजिक, संवैधानिक, आर्थिक और प्रशासनिक जटिलताएँ भी हैं।

भारत का वर्तमान राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। इसे 1973 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संरक्षण का प्रतीक बनाया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार देश में बाघ संरक्षण के लिए विशेष कानूनी और पर्यावरणीय ढांचा तैयार किया गया। आज भारत विश्व के लगभग 70 प्रतिशत बाघों का घर माना जाता

है और देश में 50 से अधिक टाइगर रिजर्व स्थापित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ केवल शक्ति और साहस का प्रतीक नहीं है बल्कि वह भारत की जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण नीति का केंद्र भी है। ऐसे में गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने का प्रश्न केवल भावनात्मक नहीं बल्कि नीतिगत बहस का विषय बन जाता है।

भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अनेक आदिवासी समुदाय रहते हैं। हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना जाता है, लेकिन सभी समुदायों की मान्यताएँ समान नहीं हैं। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों, केरल और गोवा जैसे क्षेत्रों में गोमांस भोजन का हिस्सा रहा है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति और भोजन की स्वतंत्रता देता है। ऐसे में यदि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है तो कई लोग इसे एक धर्म विशेष की मान्यताओं को सरकारी पहचान देने के रूप में देख सकते हैं। आलोचकों का तर्क है कि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी धार्मिक प्रतीक को राष्ट्रीय पहचान बनाना संवैधानिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है।

हालांकि दूसरी ओर यह भी सच है कि भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्यों को गोवंश संरक्षण और नस्ल सुधार के लिए प्रयास करने के लिए विशेष कानूनी और पर्यावरणीय ढांचा तैयार किया गया। आज भारत विश्व के लगभग 70 प्रतिशत बाघों का घर माना जाता



पशुपालन और डेयरी विभाग भी गोवंश संरक्षण और पशुधन विकास के लिए कई योजनाएँ चला रहा है। राष्ट्रीय गोदुग्ध मिशन जैसी योजनाओं का उद्देश्य नस्लों को संरक्षण और दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है। इससे स्पष्ट होता है कि गाय को पहले से ही विशेष सरकारी संरक्षण प्राप्त है। इसलिए सभ्यताओं का कहना है कि राष्ट्रीय पशु का दर्जा केवल उस सम्मान को औपचारिक रूप देने जैसा होगा जो भारतीय समाज में गाय को पहले से प्राप्त है। लेकिन वास्तविक समस्या केवल सम्मान तक सीमित नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में देश के अनेक राज्यों में आवावा पशुओं की समस्या गंभीर रूप ले चुकी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में किसान खुले धूमरे पशुओं से परेशान हैं। जब गाय दूध देना बंद कर देती है या बूढ़ी हो जाती है तो गरीब किसान उसका पालन जारी नहीं रख पाते। परिणामस्वरूप उन्हें सड़कों या खेतों में छोड़ दिया जाता है। ये पशु किसानों की

फसलों को नुकसान पहुँचाते हैं और सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। अनेक ग्रामीण किसानों की मजबूरी बन गया है। यदि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है और कानून और कठोर हो जाते हैं तो यह संकेत और बंदूक तो रोजगार और व्यापार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आर्थिक विशेषज्ञ इस विषय को केवल धार्मिक दृष्टि से देखने के बजाय रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी देखते हैं।

भारत की कृषि व्यवस्था अभी भी छोटे और सीमांत किसानों पर आधारित है। अधिकांश किसान सीमित आय और बढ़ती लागत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। एक बूढ़ी या अनुत्पादक गाय का पालन करना उनके लिए भारी आर्थिक बोझ बन जाता है। चारा, दवा और देखभाल पर लगातार खर्च होता है। जबकि उससे कोई आय नहीं होती। यदि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करती है तो संभव है कि पशुधन प्रबंधन से जुड़े नियम और कड़े हो जाएँ। इससे किसानों की आर्थिक कठिनाईयाँ और बढ़ सकती हैं। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले पशु आश्रय, चारे की व्यवस्था और किसानों के लिए आर्थिक सहायता की मजबूत नीति आवश्यक है।

गाय से जुड़ा एक बड़ा आर्थिक पक्ष चमड़ा और मांस उद्योग भी है। भारत दुनिया के प्रमुख चमड़ा उत्पादक देशों में शामिल रहा है। इस उद्योग से लाखों लोगों का रोजगार जुड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर और हाशिए पर रहने वाले समुदाय शामिल हैं। भारत में मांस निर्यात का बड़ा हिस्सा भैंस के मांस से जुड़ा होता है, लेकिन कठोर सामाजिक माहौल का प्रभाव पूरे उद्योग पर पड़ता है। यदि राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलने के बाद कानून और सामाजिक दबाव बढ़ते हैं तो रोजगार और व्यापार दोनों प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए आर्थिक विशेषज्ञ इस विषय को केवल धार्मिक दृष्टि से देखने के बजाय रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी देखते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में गाय के नाम पर हिंसा और भौंड द्वारा हमले की घटनाएँ भी सामने आई हैं। कई मामलों में गौ रक्षा के नाम पर लोगों को पीटा गया, अपमानित किया गया या उनकी हत्या तक कर दी गई। ऐसे मामलों ने देश की कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द को गंभीर प्रश्न खड़े किए। समाजशास्त्रियों का मानना है कि यदि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाता है तो कुछ कट्टर समूह इसे अपने सामाजिक अधिकार के रूप में देख सकते हैं।

महंगाई की मार: आर्थिक संकट से जूझ रहे नगरवासी

थाली से दाल-सब्जी गायब, बजट हुआ फेल

निम्न वर्ग के सामने रोजी-रोटी का संकट।

बाजारों में रौनक गायब, दुकानदारों की बिक्री में भी आई भारी गिरावट

गड्डे पंडरिया। बढ़ती महंगाई और आर्थिक मंदी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। गांव, शहर के निवासियों इन दिनों दोहर संकट से गुजर रहे हैं। एक तरफ जहां लोगों की आमदनी घट रही है या स्थिर है, वहीं दूसरी तरफ रोजमर्रा की जरूरी चीजों जैसे सलेंडर, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। स्थिति यह हो गई है कि मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए घर चलाना एक चुनौती बन गया है।

रसोई का बजट बिगड़ा, थाली से पोषण गायब

बाजार में हरी सब्जियों, दालों और खाद्य तेलों की कीमतों पिछले कुछ दिनों में बढ़ोतरी हो चुकी है। स्थानीय निवासी कार्तिक यादव ने बताया, पहले गैस सलेंडर की कीमत भी कम था अभी वर्तमान में गैस का सलेंडर का भी रेट बढ़ गया है, जिसके कारण हम कई महीने तक तो गैस सलेंडर ही नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि गैस सलेंडर पहले की अपेक्षा बहुत



महंगी हो चुकी है, जिसे खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता है, वैसे ही पेट्रोल डीजल का रेट भी बढ़ गया है जिसके कारण गाड़ी में आना जाना भी मुश्किल हो रहा है। महंगाई इतनी चरम सीमा तक बढ़ गई है कि सब्जी, दाल, शकर जैसे आवश्यक सामग्री को भी लेने के लिए सोचना पड़ता है। पहले जो घर खर्च 8,000 रुपये में चल जाता था, आज वह 15,000 रुपये पर कर रहा है। बच्चों की स्कूल फीस, बिजली का बिल, गैस

सलेंडर, पेट्रोल और ऊपर से यह महंगाई-समझ नहीं आता कि कैसे कहां से लाएं। अब तो थाली से दाल और हरी सब्जियां भी गायब होने लगी हैं।

आर्थिक संकट से व्यापार भी ठप

इस आर्थिक मंदी का असर सिर्फ खरीदारों पर ही नहीं, बल्कि स्थानीय व्यापारियों पर भी पड़ रहा है। गांव, शहर के मुख्य बाजार के किराना और कपड़ा व्यापारियों का कहना है कि लोगों के पास

पैसे न होने के कारण बाजारों से रौनक गायब है। लोग सिर्फ बहुत जरूरी चीजें ही खरीद रहे हैं। दुकानदारों की बिक्री में 40 से 50 फीसदी तक की गिरावट आई है, जिससे उनके सामने भी दुकान का किराया और स्टाफ की सैलरी निकालने का संकट खड़ा हो गया है।

लोन और कर्ज के जाल में फंस रहे लोग

आर्थिक तंगी के कारण नगरवासियों में मानसिक तनाव भी बढ़ रहा है। अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए कई लोग व्यक्तिकत ऋण या स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेने पर मजबूर हैं। आम जनता का मानना है कि यदि प्रशासन और सरकार ने बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाए, तो स्थिति और भी चिंताजनक हो सकती है।

नगरवासियों की मांग:

स्थानीय नागरिकों ने शासन प्रशासन से निवेदन किये हैं कि महंगाई व आर्थिक संकट को रोकें, ताकि आम आदमी को थोड़ी राहत मिल सके।

रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के आसमान छूने दामों से आज आम आदमी और किसान त्रस्त हैं। डीजल महंगा होने से खेती की लागत बढ़ गई है और मालभाड़ा बढ़ने से हर चीज महंगी हो गई है। सरकार से मांग है कि टैक्स कम कर तुरंत जनता को राहत दे, वरना किसान कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी

- राजजीत सिंह चन्देल
उपाध्यक्ष, प्रदेश किसान कांग्रेस छत्तीसगढ़ एवं पूर्व अध्यक्ष, सरपंच संघ

इशू विक्रम ने बताया कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाने के कारण हम गाड़ी में भी पेट्रोल डलवाने के लिए बार बार सोचते हैं क्योंकि जितना हम कमाते नहीं उससे ज्यादा पेट्रोल, बिजली बिल में खर्च हो जाता है इसलिए शासन से मांग है कि पेट्रोल, बिल के दाम को कम करे

3 वार्ड नंबर 07 पार्श्व राकेश निषाद ने बताया कि वर्तमान में गैस, पेट्रोल के रेट बढ़ने से निम्न वर्ग के लोग गैस नहीं खरीद पा रहे हैं, और घरों में चूल्हा से खाना बना रहे हैं शासन को इस और ध्यान देना चाहिए।



लक्ष्य शिक्षण संस्थान का शानदार प्रदर्शन

25 छात्र नवोदय व 23 सैनिक स्कूल में चयनित

जनप्रतिनिधियों के हाथों मेडल पहनाकर सफल विद्यार्थियों का किया गया भव्य सम्मान

अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद भगत ने मेडल एवं माल्यार्पण कर सम्मानित किया। सैनिक स्कूल में चयनित हिमाचल भगत को पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अमिताभ सिंह देव ने मेडल पहनाकर सम्मानित किया।

मुख्य अतिथि प्रियंवदा सिंह देव ने अपने संबोधन में कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों को हसबसह सहयोग दिया जाए तथा उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं एवं सेना भर्ती की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की समर्थनाएं भी सुनीं और आवश्यक सहयोग का भरपूर साह्य दिया।

पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अमिताभ सिंह देव ने लक्ष्य शिक्षण संस्थान की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्थान शंकरगढ़ क्षेत्र के विद्यार्थियों को नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। उन्होंने संस्थान के संचालक सुदर्शन यादव को सम्मानित करते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

नगर पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद भगत ने कहा कि बड़े शहरों की कोचिंग संस्थाओं की तुलना में वनांचल क्षेत्र में स्थित लक्ष्य शिक्षण संस्थान का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि संस्थान को हसबसह सहयोग दिया जाए।

संस्थान संचालक सुदर्शन यादव ने बताया कि इस वर्ष संस्थान का 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम भी शान-प्रतिशत रहा। 10वीं में सर्वाधिक 97.33 प्रतिशत एवं 12वीं में 93.80 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं। साथ ही एक जून से शुरू होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग दी जा रही है। उन्होंने बताया कि भूषण गामी को देखते हुए विद्यार्थियों की सुविधा हेतु पूर्व जनपद उपाध्यक्ष अमिताभ सिंह देव द्वारा पिछले वर्ष कुलए एवं पंखे उपलब्ध कराए गए थे।

कलेक्टर परिसर में वाटर फिल्टर की मांग जनदर्शन में उठी

सूरजपुर। कलेक्टर परिसर में पानी की किल्लत को देखते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कलेक्टर सूरजपुर को पत्र लिखकर परिसर में पानी की व्यवस्था की मांग की है। पानी की इस समस्या को लेकर आज आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सीधे कलेक्टर के नाम एक शिकायती पत्र सौंपकर व्यवस्था सुधारने की मांग की है।

कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे पुनीत दुबे जिला संयुक्त महासचिव और रवि जायसवाल जिला अध्यक्ष, आप सहित अन्य नागरिकों ने बताया कि पानी की किल्लत को देखते हुए पानी की भारी समस्या हो रही है। परिसर में पीने योग्य शुद्ध जल की सुविधा और वाटर फिल्टर सुनिश्चित कराया जाना बेहद जरूरी है। नेताओं ने कहा कि यदि जिला मुख्यालय में ही मूलभूत सुविधाएं गायब रहेंगी, तो प्रशासन के सुशासन के दावों पर सवाल उठाना लाजिमी है।



कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त हुए 98 आवेदन

“आम जनता की समस्याओं का संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के साथ समाधान सुनिश्चित करें” - कलेक्टर

सूरजपुर। संयुक्त जिला कार्यालय में आज आयोजित जनदर्शन में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आमजन ने कलेक्टर श्रीमती रेना जमील के समक्ष अपनी समस्याओं, मांगों एवं शिकायतों से जुड़े आवेदन प्रस्तुत किए। जनदर्शन में कुल 98 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें राजस्व प्रकरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, बिजली-पानी, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा व्यक्तिगत समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रमुख रूप से शामिल रहे। कलेक्टर ने एक-एक आवेदक से शांतिपूर्वक उनकी समस्या सुनी तथा उनकी कठिनाइयों को गंभीरता से समझते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।



कलेक्टर श्रीमती रेना जमील ने जनदर्शन में प्राप्त समस्त आवेदनों की गंभीरता से समीक्षा करते हुए संबंधित

विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक आवेदन का परीक्षण कर निराकरण योग्य प्रकरणों का शीघ्रतः निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम जनता की समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता के आधार पर किया जाए तथा किसी भी आवेदक को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शी, समयबद्ध एवं जवाबदेह व्यवस्था के तहत प्रत्येक पात्र हितग्राही को उनका

हक एवं सरकारी योजनाओं का लाभ अवश्य मिले, यह सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों का प्रथम दायित्व है।

कलेक्टर ने यह भी निर्देशित किया कि जन आवेदनों के निराकरण में अधिक समय लगने की संभावना है, उनकी समयसिमा निर्धारित कर निराकरण की वस्तुस्थिति से आवेदकों को निरंतर अवगत कराया जाए, ताकि उन्हें अपने प्रकरण की प्रगति की जानकारी समय पर मिलती रहे। साथ ही कलेक्टर ने जन आवेदनों को निराकरण की माॉनट्रिंग पोर्टल पर नियमित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निपटारा जाए। जनदर्शन में प्राप्त समस्त आवेदनों को संबंधित विभागों को प्राथमिकता के साथ निराकरण हेतु प्रेषित कर दिया गया है।

कांग्रेस जनों ने झीरम घाटी में शहीद दिवंगत नेताओं को दी श्रद्धांजलि

बलौदा बाजार। जिला कार्यालय बलौदाबाजार में झीरम घाटी की घटना को याद करते इस घटना में दिवंगत नेताओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर उनका शहादत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेसजनों ने शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा लोकतंत्र, संविधान एवं जनसेवा के प्रति उनके योगदान को याद किया। कार्यक्रम में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि झीरम घाटी के शहीद नेताओं का बलिदान सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। उनके संघर्ष, समर्पण एवं कांग्रेस विचारधारा के प्रति प्रतिबद्धता को कभी भुलाया नहीं जा सकता। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष मुहम्मद युदु जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष दिनेश युदु, नगर पालिका की छाया अध्यक्ष सुरेंद्र जायसवाल, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक साहू, पूर्व ब्लाक अध्यक्ष संतोष तिवारी, जिला महामंत्री लखेश साहू, शहर महामंत्री नीरज बांधे, मोहन साहू, दिगंबर साहू, सुखदेव साहू, अजय थारती, पावन मानिकपुरी शहर उपाध्यक्ष भोरीश्री रविंद्र नामदेव, यशवंत वर्मा, खिलवान जायसवाल महामंत्री जितेंद्र नवरत मंडल अध्यक्ष गोल्डी मारंड्या नेता प्रतिपक्ष सलमान शेख जय बाचमर शैलेंद्र ध्वज सा सुर्यवंत वर्मा जय नायक, हेमंत ठाकुर सहित समस्त कांग्रेस जन उपस्थित रहे

के अध्यक्ष दीपक साहू, प्रमोण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक साहू, पूर्व ब्लाक अध्यक्ष संतोष तिवारी, जिला महामंत्री लखेश साहू, शहर महामंत्री नीरज बांधे, मोहन साहू, दिगंबर साहू, सुखदेव साहू, अजय थारती, पावन मानिकपुरी शहर उपाध्यक्ष भोरीश्री रविंद्र नामदेव, यशवंत वर्मा, खिलवान जायसवाल महामंत्री जितेंद्र नवरत मंडल अध्यक्ष गोल्डी मारंड्या नेता प्रतिपक्ष सलमान शेख जय बाचमर शैलेंद्र ध्वज सा सुर्यवंत वर्मा जय नायक, हेमंत ठाकुर सहित समस्त कांग्रेस जन उपस्थित रहे

झीरम घाटी के अमर शहीदों को चारामा ब्लॉक कांग्रेस ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कार्यकर्ता नक्सली हमले की बरसी पर आज चारामा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय विधायक निवास में शहादत दिवस का आयोजन किया गया। इस भावुक और गरिमायुी कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारियों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने देश और प्रदेश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर द्वारा वृद्धाश्रम एवं सखी वन स्टॉप सेन्टर का अचौक निरीक्षण

सूरजपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर की सचिव व व्यवहार न्यायाधीया वरिष्ठ सुश्री पायल टोपनों द्वारा क्षेत्र के सामाजिक और कल्याणकारी केन्द्रों का अचौक निरीक्षण किया गया। इस अचौक निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जमीनी स्तर पर विधिक सहायता की उपलब्धता सुनिश्चित करना और संस्थाओं में सह रहे नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना था।

सखे सम्बल वृद्धाश्रम तिलसियों का विस्तृत निरीक्षण-सचिव सुश्री पायल टोपनों सबसे पहले तिलसियों स्थित सखे सम्बल वृद्धाश्रम पहुंची निरीक्षण के दौरान उन्होंने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य और समीक्षा की। वृद्धजनों से आत्मीय संवाद औपचारिकताओं से परे हृदय, सचिव ने आश्रम में समाजपूर्वक जीने, भरण-पोषण और मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।



न्यायालय तहसीलदार बसना जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

ईशतहार

क्रमांक/175/का-1/तह./2026
दिनांक 12.05.2026

एतद् द्वारा सर्वसम्पन्न के लिए सूचनाएं प्रकाशन कराया जाता है कि आवेदक हेमसागर पटेल पिता शोभम पटेल निवासी ग्राम/नगर जगत तहसील बसना द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आवेदक/आवेदिका अपने माता धनकुंवर का दिनांक 09.03.2009 को स्थान जगत में मृत्यु हुई है।

उक्त जन्म/मृत्यु का पंजीयन नहीं हो पाने के कारण उक्त लिखित में माता धनकुंवर के मृत्यु की घटना पंजीकृत किये जाने हेतु इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त संबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को किसी भी प्रकार का आक्षेप/दावा हो अथवा आवेदन पत्र प्रस्तुत करना हो तो वे स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 26.05.2026 को उपस्थित होकर पेश कर सकते हैं। बाद में प्राप्त दावा आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 12.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के पदसुदा से जारी किया गया।

तहसीलदार बसना

नायब तहसीलदार मुंगेली (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार एवं कार्यपालिका दण्डाधिकारी मुंगेली (छ.ग.)

ईशतहार

रा.प्र.क्र./.../बी-121/2025-26
ग्राम झुलना खुर्द प.ह.नं. 11

एतद् द्वारा ग्राम झुलना खुर्द के आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक गेंडराम सुंदरके आ. तीजऊ राम जाति गोंड निवासी झुलना खुर्द तहसील व जिला मुंगेली द्वारा ग्राम झुलनाखुर्द हल्का नं. ... तहसील व जिला मुंगेली निवासी अपने मां जानाबाई आ. पति तितजउराम की मृत्यु दिनांक 16/05/2003 को होने एवं सचिव ग्राम पंचायत खुजनाह के पंजी में दर्ज कराने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त संबंध में जिस किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह स्वयं या अभिभाषक या प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 03/06/2026 समय 11:00 बजे दिन को तहसील कार्यालय मुंगेली में दावा/आपत्ति पेश कर सकते हैं। निर्धारित तिथि को पेशचात प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 04/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुद्रा से जारी किया गया।

कार्यपालिक दण्डाधिकारी मुंगेली



कोरिया की धरती पर जश्ने जबां जैसे आयोजन गढ़ रहे मील का पत्थर: नरेश प्रसाद

कोरिया जिले की सो से अधिक प्रतिभाओं ने जश्ने जबां के मंच से दिखाया अपना हुनर



अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में एकाग्र शर्मा, हीरामणि ने श्रोताओं को किया लोटपोट

बैकुण्ठपुर। कोरिया जिला मुख्यालय में दो दिनों तक चले जश्ने जबां कार्यक्रम में साहित्य, संस्कृति और लोक कला के प्रस्तुतियों ने हजारों दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यहां झुमका ओपन थियेटर में सो से ज्यादा स्थानीय कलाकारों ने मंच से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। देश प्रदेश से आए लगभग 60 कलाकारों ने अलग अलग विधाओं में अपना प्रदर्शन कर दर्शकों और साहित्य प्रेमियों में नई उर्जा का संचार किया। साईनाथ फाउंडेशन के तत्वाधान में निरंतर सात वर्षों से आयोजित हो रहे जश्ने जबां कार्यक्रम का कोरियावासियों ने जमकर आनंद उठाया। बीती शाम इस दो दिवसीय आयोजन का समापन समारोह झुमका ओपन एयर थियेटर में दक्षिण पूर्व कोयला प्रखेत्र के बैकुण्ठपुर महाप्रबंधक नरेश प्रसाद की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रमों का महाप्रबंधक श्रवण कुमार, जिला पंचायत सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुरेशा चैबे ने कार्यक्रम की सफलता पर अपने विचार व्यक्त किए और आयोजन में शामिल प्रत्येक प्रतिभागियों और विशिष्ट कलाकारों को मंच पर सम्मानित किया और सभी के उज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

जश्ने जबां जैसे आयोजन गढ़ रहे मील का पत्थर

समापन समारोह में मुख्य अतिथि की आसदी से संबोधित करते हुए महाप्रबंधक नरेश प्रसाद ने कहा कि इतनी विविधताओं के साथ एक आयोजन पूरे क्षेत्र के लिए उपलब्धि

की तरह है। उन्होंने आयोजन समिति के सभी सदस्यों और शामिल देश प्रदेश तथा कोरिया के समस्त प्रतिभाओं का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि प्रत्येक आयोजन में मंच से हुनर का प्रदर्शन आपकी कला को निखारता है। ऐसे आयोजनों में शामिल होना ही गौरव का विषय होता है। कोरिया की उर्वरा धरती पर आयोजन को मील का पत्थर कहते हुए उन्होंने आश्चर्य किया कि यहां होने वाले प्रत्येक साहित्यिक, सांस्कृतिक और लोक कला के आयोजनों में एएसडीएल हमेशा सहयोग के लिए तैयार है। उन्होंने लोककलाकारों का उत्साहवर्धन करते हुए अपनी शुभकामनाएं दीं।

जश्ने जबां से लोककला और संस्कृति की महक का विस्तार

विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित आपरेशन जोएम श्रवण कुमार ने कार्यक्रम की प्रशंसा करते हुए निरंतर इस तरह के आयोजन कराए जाने हेतु सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुरेशा चैबे ने भी प्रतिभागियों के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा कि कोरिया में जश्ने जबां जैसे आयोजनों से एक अलग माहौल तैयार होता है। देश प्रदेश से आए हुए कलाकार और साहित्यधर्मियों से कोरिया को हमेशा कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। ऐसे में स्थानीय प्रतिभाएं और निखर कर सामने आती हैं।

दूसरे दिन कथक, गोंड़ी, कवि सम्मेलन ने जमाया माहौल

जश्ने जबां के दूसरे दिवस के आयोजन में ओपन माइक सत्र में स्थानीय और प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए 30 से अधिक कलाकारों ने नृत्य, काव्यपाठ, गायन में

अपना जोहर दिखाया। इसके बाद खैरागढ़ से आए खगेश पैकरा ने गोंड़ी लोकनृत्य का दर्शनीय प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बालगृह के बच्चों ने शानदार योग का प्रदर्शन किया। बनारस घराने के संगीतज्ञों ने पूरे आयोजन में एक अलग माहौल बनाया। कथक नृत्य से डा मिश्रा ने प्रभु राम के चरित्र का अनूठा प्रदर्शन किया। इसके साथ ही लोक कलाकारों की प्रस्तुति हुई। अंत में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में मुंबई के एकाग्र शर्मा, समस्तीपुर से आए अक्सर, इंदौर से आए गौरव साक्षी, गोपालगंज की सान्या राय और कोरबा के हीरामणि ने देर रात तक सुनकर भावविभोर कर दिया।

उपन्यास यक्षिणी पर हुई पुस्तक चर्चा

दूसरे दिन के आयोजन में जिला पंचायत सीईओ डॉ आशुतोष चतुर्वेदी की प्रथम उपन्यास यक्षिणी पर चर्चा का सत्र भी संपादित किया गया। इस दौरान साहित्यधर्मी आशीष राज सिंहानिया ने लेखक डॉ आशुतोष से उपन्यास की रचना पर और उसके विषय पर अनेक प्रश्न रखे और इस पर डॉ आशुतोष ने अपने विचार व्यक्त किए। चर्चा के दौरान लेखक डॉ आशुतोष ने बताया कि यक्षिणी के अगले क्रम में भी वह नई उपन्यास के लिए लेखन कार्य प्रारंभ कर चुके हैं। उन्होंने चर्चा के अंत में मां पर एक अत्यंत मार्मिक कविता पढ़कर व्यक्ति के जीवन में मां की ममता और उसके आशीर्वाद के महत्व को और गहराई प्रदान की।

युवा गायक आयुष के गीत रूबरू का पोस्टर लांच

जश्ने जबां के दूसरे दिन अंतिम सत्र में अतिथियों के द्वारा क्षेत्र के उभरते युवा गायक आयुष नामदेव के नए गीत रूबरू का पोस्टर

लांच किया गया। सियाधेश म्यूजिक के बैनर तले आ रहे इस गीत को आयुष नामदेव ने स्वयं दिया है। वहीं इसकी कम्पोजिशन सावन आर मुंबई के द्वारा की गई है। आयुष ने बताया कि यह गीत एचएस फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा ऋषि त्रिपाठी द्वारा निर्देशित किया गया है और इसकी संगीत रिकार्डिंग इवोएस स्टूडियो में की गई है। जल्द ही यह गीत आमजन के बीच होगा। अतिथियों ने आयुष को अपनी शुभकामनाएं प्रदान कीं।

जश्ने जबां के दूसरे दिन अतिथियों की दीर्घा में वरिष्ठ साहित्यकार वरिंद्र श्रीवास्तव, डा अंकार साहू, गौरव अग्रवाल, श्रीमती अनु चक्रवर्ती, योगेश गुप्ता, आंचल पांडे सुनील शर्मा, आयुष नामदेव, संवर्त कुमार, सुरी अलीशा शेख, श्रीमती तारा पांडे, सुश्री रेणुका, भावेश देशमुख, हर्षपाल सिंह, अभिषेक पाण्डेय, जिला खेल अधिकारी जितेंद्र गुप्ता, अखिलेश राजवाड़े, राजीव गुप्ता, सतीश गुप्ता, अरुण जैन, शेख खलील, प्रखर सिंह सहित अनेक विधाओं के परंपरागत कलाकार, रचनाधर्मी और युवा प्रतिभाएं उपस्थित रहे। अंत में योगेश गुप्ता ने उपस्थित अतिथियों, कलाकारों, और अन्य व्यवस्थाओं से जुड़े महत्वपूर्ण साधियों के प्रति आभार प्रदर्शन किया।



पिथौरा को मिली विकास कार्यों की सौगात, 2.50 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन

पिथौरा। सुशासन दिवस के अवसर पर नगर पंचायत पिथौरा में सोमवार को लगभग 2.50 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं नगरवासी उपस्थित रहे। विकास कार्यों के शुभारंभ को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला।



कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पंचायत अध्यक्ष देवेश निपाद थे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत उपाध्यक्ष वरिंद्र तिवारी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद प्रतिनिधि मनमोदी छाबड़ा, वरिष्ठ पार्षद मन्मूलाल ठाकुर, पार्षद राम कुंवर सिन्हा, पार्षद पुष्पकान्त पटेल, पार्षद कौशल मानिकपुरी, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष नरेश सिंघल, विक्की सलूजा तथा स्काउट के उपायुक्त लक्ष्मीकांत सोनी, किशोर पटेल, दीपक सिन्हा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में एसडीएम, तहसीलदार एवं नगर पंचायत सीएमओ भी मंचासीन रहे।

भूमिपूजन कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने कहा कि नगर में लगातार विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। सड़क, नाली, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों के पूर्ण होने से नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा नगर का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित होगा। वक्ताओं ने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से कार्य किए जा रहे हैं और सुशासन दिवस इसी संकल्प को मजबूत करने का अवसर है। कार्यक्रम में अतिथियों ने विकास

कार्यों के लिए नगर पंचायत की पहल की सराहना करते हुए कहा कि जनसहभागिता के माध्यम से नगर को स्वच्छ, सुंदर एवं सुविधायुक्त बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी रहे। इस दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने नागरिकों से विकास कार्यों में सहयोग की अपील भी की। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, पार्षदगण, समाजसेवी, भाजपा कार्यकर्ता एवं नगर पंचायत के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। भूमिपूजन के पश्चात अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान भी किया गया।

चिन्हित 17 गांवों में धरती आबा का लाभ देने प्रतिबद्ध : कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू

परसापाली में हुआ धरती आबा शिविर का सफल आयोजन

संरंगढ़ बिलाईगढ़। धरती आबा का शिविर बिलाईगढ़ ब्लॉक के परसापाली में आयोजित किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू, विधायक कविता लहरे, पूर्व विधायक सनम जांगड़े, सत्ताधारी दल के सुभाष जालान, सहायक आयुक्त आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास बद्रिश सुखदेवे सहित जिला अधिकारी, बिहान समूह की महिला सदस्य एवं ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। धरती आबा के इस कार्यक्रम में कलेक्टर सहित सभी अतिथियों के आगमन पर पारंपरिक ढोल नगाड़े और सामूहिक नृत्य से स्वागत किया गया और उनके माथे में साफा बांधा गया। अतिथियों के साथ कलेक्टर ने चटई में बैठकर ग्रामीणों के आवेदन



लिए। कलेक्टर ने आदिवासी बाहुल्य गांव परसापाली के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि, धरती आबा भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिससे आदिवासी समाज के लोगों को सारे बुनियादी सुविधा मुहैया कराने के लिए केंद्र, राज् एवं जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी है। हम लोग हमारे जिले के सभी चिन्हित 17 गांवों में राशन कार्ड, पेंशन, पेयजल, महतारी वंदन, आयुष्मान केंद्र, पीएम आवास, वन अधिकार पत्र, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, राजस्व कार्य फौती नामांतरण, किसान पुस्तिका, सीमांकन, भूमिहीन अनुदान, आदि योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को शत प्रतिशत प्रदान करेंगे।



जिला युवा कांग्रेस ने झीरम घाटी के शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि

सारंगढ़। कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शहीद नंदकुमार पटेल एवं शहीद दिनेश पटेल के साथ झीरम के शहीदों के शहादत दिवस पर उनकी याद में जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष शुभम बाजपेयी के नेतृत्व में बस स्टैंड स्थित कांग्रेस कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित कर शासकीय अस्पताल में वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं एवं एनएसयूआई युवा कांग्रेस के साधियों के साथ फल वितरण कर शहादत दिवस मनाया गया। उक्त मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी उपलब्ध, पीएम आवास, वन अधिकार पत्र, जाति, निवास, आय प्रमाण पत्र, राजस्व कार्य फौती नामांतरण, किसान पुस्तिका, सीमांकन, भूमिहीन अनुदान, आदि योजनाओं का लाभ सभी पात्र हितग्राहियों को शत प्रतिशत प्रदान करेंगे।

38 लाख रुपये के गबन का आरोपी बिलासपुर से गिरफ्तार, भेजा गया जेल

26 माह तक कंपनी की रकम हड़पता रहा एरिया सेल्स ऑफिसर, मकान निर्माण में खर्च किए रुपए

दुर्ग। जेवरा सिरसा चौकी पुलिस ने 38 लाख रुपये के गबन के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी एरिया सेल्स ऑफिसर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी ने कंपनी के व्यापारियों से वसूली गई रकम को कंपनी खाते में जमा करने के बजाय निजी उपयोग में खर्च कर दिया था।

गोयल ट्रेडर्स जेवरा सिरसा में एरिया सेल्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत राजेश जायसवाल ने वर्ष 2020 से 2022 के बीच लगभग 26 माह तक कंपनी की राशि का गबन किया। आरोपी चाय पत्ती, सेवई, वाशिंग पाउडर एवं अन्य पैकेजिंग सामग्री की बिक्री से प्राप्त रकम व्यापारियों से वसूलता था, लेकिन उसे कंपनी खाते में जमा नहीं करता था।

मकान निर्माण और निजी कार्यों में खर्च की रकम

: जांच में सामने आया कि आरोपी ने गबन की गई करीब 38 लाख रुपये की राशि को निजी मकान निर्माण एवं अन्य व्यक्तिगत कार्यों में खर्च कर दिया। प्रार्थी की



शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। बिलासपुर से हुई गिरफ्तारी : मामले की जांच के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी राजेश जायसवाल की तलाश कर उसे बिलासपुर से गिरफ्तार किया। पृष्ठजाह एवं मेमोरेण्डम कथन में आरोपी ने रकम का निजी उपयोग करना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 409 एवं 420 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

हज केवल एक इबादत नहीं बल्कि इंसान की रूहानी तरबियत



राजनांदगांव। मुस्लिम समाज जामा मस्जिद के सदर एवं सामाजिक चिंतक रईस अहमद शकील ने कहा कि हज केवल एक इबादत नहीं, बल्कि इंसान की रूहानी तरबियत, अखलाकी इस्लाह और इंसानियत की खिदमत का सबसे बड़ा जरिया है। इस्लामी हज का महीना इस्लामी हिजरी कैलेंडर का 12वां और अंतिम महीना जुल-हिज्जा कहलाता है, इस महीने को हज का महीना इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वार्षिक हज तीर्थयात्रा 8वीं से 12वीं तारीख तक इसी दौरान होती है, इसलिए जुल-हिज्जा इसे हज तीर्थयात्रा का महीना भी कहा जाता है।

मुस्लिम समाज जामा मस्जिद के सदर एवं सामाजिक चिंतक रईस अहमद शकील ने कहा कि हज केवल एक इबादत नहीं, बल्कि इंसान की रूहानी तरबियत, अखलाकी इस्लाह और इंसानियत की खिदमत का सबसे बड़ा जरिया है। इस्लामी हज का महीना इस्लामी हिजरी कैलेंडर का 12वां और अंतिम महीना जुल-हिज्जा कहलाता है, इस महीने को हज का महीना इसलिए कहा जाता है, क्योंकि वार्षिक हज तीर्थयात्रा 8वीं से 12वीं तारीख तक इसी दौरान होती है, इसलिए जुल-हिज्जा इसे हज तीर्थयात्रा का महीना भी कहा जाता है।

वेदांता बालको में दिग्विजय कॉलेज की छात्राओं का परचयन

राजनांदगांव। दिग्विजय महाविद्यालय की 9 छात्राओं का प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्था वेदांता बालको में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी पद पर अंतिम रूप से चयन हुआ है। चयनित छात्राओं को प्रारंभिक वार्षिक पैकेज 5.50 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉ. सुचित्रा गुप्ता के दिशा-निर्देशन तथा कॉलेज के रोजगार एवं मार्गदर्शन प्रकोष्ठ एवं रसायन शास्त्र विभाग के अथक प्रयासों से यह महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है।



यूनस रज़ा बेग को दिया। उन्होंने बताया कि प्रो. बेग एवं उनकी टीम ने नियमित प्रयासों के अतिरिक्त समय निकालकर छात्राओं को साक्षात्कार की विशेष तैयारी कराई, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया।

डॉ. टिस्के ने जानकारी दी कि वेदांता बालको वर्ष 2007 से दिग्विजय महाविद्यालय के प्रतिभावान विद्यार्थियों का चयन अपनी कंपनी के लिए करता आ रहा है। अब तक 200 से 300 विद्यार्थी वेदांता बालको द्वारा आयोजित कैम्पस चयन प्रक्रिया का लाभ उठाकर कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

खैरागढ़ बीईओ कार्यालय शराब खोरी वायरल वीडियो मामला : जिला शिक्षा अधिकारी ने की बड़ी कार्रवाई,

शराब खोरी में लिप्त 2 कर्मचारी निलंबित

शिक्षा विभाग को बड़ी कार्रवाई करनी ही पड़ी। आखिरकार अब जिला शिक्षा विभाग ने दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। केसीजी जिला शिक्षा अधिकारी मुकुल केपी साव द्वारा जारी आदेश के अनुसार बीईओ कार्यालय खैरागढ़ में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 रविन्द्र सिंह गहरवार व वायरल वीडियो मामले में कई दिनों तक इस मामले को दबाने की जबरदस्त कोशिश हुई पर आखिरकार मीडिया के दबाव में और केसीजी कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल के संज्ञान में ये मामला आते ही जिला शिक्षा विभाग पूरी तरह हरकत में आया और जिला शिक्षा अधिकारी ने कथित शराब खोरी वीडियो वायरल काण्ड के दोषी दो कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। खास बात ये है कि इस पूरे मामले को दबाने, संभालने और लुपती साने की लगातार कोशिशें होती रही। लेकिन सोशल मीडिया में लगातार वायरल हो रहे वीडियो और मीडिया में लगातार खबरें प्रकाशित होने के बाद उठ रहे बड़े सवाल के बाद

गई है और दोनों ही कर्मचारियों के खिलाफ जांच भी प्रस्तावित है। शराब खोरी का वीडियो वायरल होने के बाद भी कई माह तक जिले के जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहे और पहले इस मामले के उठे होने का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन जब सोशल मीडिया में सरकारी संस्थान में शराब खोरी का ये वीडियो लगातार वायरल होते रहा और मीडिया ने भी जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी पर बड़े सवाल उठाने शुरू कर दिये तो अंततः शिक्षा विभाग हरकत में आया और दोनों कर्मचारियों पर गलत कर्म करने पर बड़ी गाज गिरी। इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब उम्मीद है कि सरकारी दफ्तरों पर ऐसी घटिया हरकत करने वाले अन्य कर्मचारियों के हाथ पांव भी अब कांपेंगे और वो ऐसी गुस्ताखी करने से बचेंगे।

पाठको बता दें कि शराब खोरी का वीडियो वायरल होने के बाद भी कई माह तक जिले के जिम्मेदार अधिकारी पूरे मामले पर चुप्पी साधे रहे और पहले इस मामले के उठे होने का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन जब सोशल मीडिया में सरकारी संस्थान में शराब खोरी का ये वीडियो लगातार वायरल होते रहा और मीडिया ने भी जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी पर बड़े सवाल उठाने शुरू कर दिये तो अंततः शिक्षा विभाग हरकत में आया और दोनों कर्मचारियों पर गलत कर्म करने पर बड़ी गाज गिरी। इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब उम्मीद है कि सरकारी दफ्तरों पर ऐसी घटिया हरकत करने वाले अन्य कर्मचारियों के हाथ पांव भी अब कांपेंगे और वो ऐसी गुस्ताखी करने से बचेंगे।



कर्मचारियों द्वारा की गई घटिया हरकत

गौरतलब है कि जिस कार्यालय से ब्लॉक की पूरी शिक्षा व्यवस्था संचालित होती है वहीं के सरकारी दफ्तर के कर्मचारियों द्वारा की गई। इस घटिया हरकत पर बड़े सवाल खड़े होने लगे थे और अब आदेश के मुताबिक निलंबन अवधि में दोनों कर्मचारियों का महाखालय बीईओ कार्यालय छुड़खंदान निर्धारित किया गया है। बहरहाल इस बड़ी कार्रवाई के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंधा की स्थिति बनी हुई है। सरकारी संस्थान में इस शराब खोरी के मामले की चर्चा पूरे जिलेभर में हो रही है। इस मामले के अलावा भी हमें पूर्व में बहुत से कर्मचारियों के नशे में अपनी झूठी निभाने की शिकायतें पालकों और उनके बच्चों से मिलती रही हैं। उम्मीद है कि भविष्य में जल्द ही दूसरे नशाखोरी के मामले और बड़े सामने आयेंगे या फिर इस मामले में कार्रवाई होने के बाद नशे में शिक्षा के मंदिर जाने वाले कर्मचारी अब सुधरेंगे।

तिरछी नजर से

रियल एस्टेट: सपने
बेचने का धंधा

प्रभात दत्त झा

जहाँ Flat Ready है - बस थोड़ा और इंतजार चाहिए, जैसे पिछले सात साल से है

दुनिया में तीन महान कल्पनाशील प्राणी हैं। पहले - कवि, जो चाँद-तारों में प्रेमिका देखते हैं। दूसरे - नेता, जो पाँच साल में सब ठीक करने का वादा करते हैं। तीसरे - रियल एस्टेट बिल्डर, जो जंगल में 'खड़े होकर कहते हैं: 'यह रहा आपका प्राइम लोकेशन।'

'Brochure देखकर फ्लैट बुक मत करिए' - यह हिंदी का सबसे उपयोगी वाक्य है जो आज तक किसी पाठ्यपुस्तक में नहीं आया। Brochure में जो तस्वीर होती है - हरे-भरे पेड़, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, बच्चों का पार्क - वह सब उस बिल्डर के बेटे की शायी में भी नहीं दिखती जो वह Brochure छपाता है। बिल्डर ने कहा: पंजेशन (Possession) छह महीने में। ग्राहक ने पूछा: कौन से छह महीने? Builder बोला: आने वाले। ग्राहक ने पूछा: यही तो आप 2019 से कह रहे हैं। Builder बोला: और हम झूठ नहीं बोलें - छह महीने आने वाले ही हैं, बस अभी तक आए नहीं।

RERA आया। बिल्डरों पर लगाम लगाने के लिए। बिल्डरों ने RERA पढ़ा। कुछ ने RERA का पंजीकरण कराया - बड़ी खुशी से। फिर जब डेडलाइन निकली तो RERA को ही Petition दी: कोविड था, बारिश थी,

सीमेंट महंगा था, मजदूर नहीं मिले। RERA ने Extension दिया। ग्राहक घर में बैठकर किराया भरता रहा। RERA ने सोचा: हमने तो काम किया। ग्राहक ने सोचा: कौन से RERA की बात हो रही है?

एमेनिटीज (Amenities) की बात करें। ब्रोशर में लिखा था: जिम मिला - एक कमरे में दो ट्रेडमिल (Treadmill) जिम में से एक चलती है। ब्रोशर में था: स्विमिंग पूल (Swimming Pool)। मिला - एक छोटा-सा हैज जिसमें अगर पाँच लोग एक साथ उतरें तो पानी बाहर आ जाए। Brochure में था: 24x7 Security। मिला - एक बुजुर्ग Guard जो रात को सोते हैं - जो खुद की सिन्क्रोपैट्री के लिए जरूरी है।

सबसे मनोरंजक प्राणी होता है - प्रॉपर्टी कंसल्टेंट (Property Consultant)। वह कहता है: यह Property अभी लो, कल दाम बढ़ जाएँगे। दाम वाकई बढ़ते हैं - लेकिन Possession नहीं आती। तब वह कहता है: देखो, इनवेस्टमेंट (Investment) अच्छी रही। आप सोचते क्या फायदा? वह कहता है: बेच दो। आप पूछते हैं: किसे? वह कहता है: किसी और को जो अभी जहाँ आप थे, वहाँ है।

भारतीय मध्यवर्ग का सबसे बड़ा सपना है: अपना घर। बिल्डर जानता है। इसीलिए वह सपने बेचता है - पहले जमीन पर, फिर नक्शे पर, फिर Brochure पर। घर बनाना तो बाद की बात है।

रियल एस्टेट वह उद्योग है जहाँ ग्राहक पैसे देता है, सपने खरीदता है और Possession की तारीख का इंतजार करते हुए बड़ा हो जाता है।

हैंसिए - क्योंकि रोने से EMI नहीं घटती, Smart City नहीं बनती, और Flat का Possession नहीं आता। देवेन्द्रनगर, बिलासपुर (छ.ग.)

1.8 लाख स्टार्टअप, 120 यूनिफॉर्म -
पर नींव कितनी मज़बूत?

सपनों की इमारत और ज़मीन की दरारें - एक जरूरी पड़ताल

- प्रभात दत्त झा

एक दृश्य कल्पना करें। बंगलुरु का कोई चमकदार को-वर्किंग स्पेस - काँच की दीवारें, बोन-बैंग, फ्री कॉफी, दीवार पर लिखा है: 'Disrupt or Die.' भीतर एक उत्साही युवा लैपटॉप पर झुका हुआ है - उसकी आँखों में ऑक्टोबर में लॉन्च, दिसंबर में फंडिंग और अगले साल यूनिफॉर्म का सपना है। अब उसी दृश्य को जूम आउट कीजिए। उसी बंगलुरु में, कुछ किलोमीटर दूर, एक और युवा है जिसके स्टार्टअप की फंडिंग तीन महीने पहले बंद हो गई, निवेशक मुँह फेर चुके हैं और वह अब फिर से नौकरी ढूँढ रहा है। यही भारतीय स्टार्टअप जगत की दो असली तस्वीरें हैं - और दोनों सच हैं।

आँकड़े जो गर्व कराते हैं

भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) के पास पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या 1.8 लाख के पार जा चुकी है। 120 से अधिक यूनिफॉर्म - यानी एक अरब डॉलर से अधिक के मूल्यांकन वाली कंपनियाँ। 2016 में जब स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत हुई थी, तब ये संख्या महज चार सौ के आसपास थी। यह छल्ला किसी उत्सव से कम नहीं।

डेटा बॉक्स

पंजीकृत स्टार्टअप (2026) - 1.80 लाख से अधिक
यूनिफॉर्म की संख्या - 120+
स्टार्टअप इंडिया लॉन्च वर्ष - 2016
वैश्विक रैंकिंग - तीसरा स्थान
2021-22 में फंडिंग शिखर - 25 बिलियन
2023 में फंडिंग - 25 बिलियन 2023 में फंडिंग - 7 बिलियन (गिरावट दर्ज, शिखर से लगभग 72% कम)
सफलता दर (5 वर्ष बाद) - 10% से कम



वह सवाल जो कोई नहीं पूछना चाहता

पहली बात: इन 1.8 लाख स्टार्टअप में से 90% से अधिक पाँच साल के भीतर बंद हो जाते हैं। वैश्विक औसत भी यही है - लेकिन जब इन स्टार्टअप में युवाओं की बचत लगी हो, परिवार की उम्मीदें जुड़ी हों और बैंक से लिए कर्ज का बोझ हो, तो यह महज एक आँकड़ा नहीं रहता।

दूसरी बात: भारत की फंडिंग 2021-22 के शिखर 25 बिलियन से गिरकर 2023 में 25 बिलियन से गिरकर 2023 में 7 बिलियन रह गई। EdTech की दुनिया को देखें - बायजू, जो एक समय दुनिया का सबसे मूल्यवान EdTech यूनिफॉर्म था (मूल्यांकन 22 बिलियन), 2024-25 में ऐसे संकट में फँसा कि उसकी दास्तान हर बिजनेस स्कूल में केस स्टडी बन गई। लगभग 4,000 से अधिक कर्मचारियों की नौकरी गई, अधिभावकों की फीस पर मुकदमे हुए, और कंपनी का मूल्यांकन 95% से अधिक गिर गया। एक विशाल ब्रांड - सब कुछ एक झटके में।

तीसरी बात: भारतीय स्टार्टअप जगत का

भूगोल अत्यंत असंतुलित है। बंगलुरु, दिल्ली-NCR, मुंबई, हैदराबाद और पुणे - यही पाँच शहर 80% से अधिक फंडिंग और लगभग सभी यूनिफॉर्म के जन्मदाता हैं।

नींव की असली परीक्षा

पहला खंभा: प्रतिभा। IIT, IIM और NIT से निकले युवाओं ने स्टार्टअप को ग्लैमर दिया। लेकिन उद्यमिता शिक्षा अभी भी महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में हाशिए पर है।

दूसरा खंभा: फंडिंग। भारत में Venture Capital का पैसा अभी भी सुरक्षित दौंव पर लगता है। Deep Tech, Manufacturing, AgriTech जैसे क्षेत्रों में फंडिंग की भारी कमी है।

तीसरा खंभा: बाजार और ग्राहक। असली भारत - उसके 65 करोड़ ग्रामीण नागरिक - अभी भी इस स्टार्टअप क्रांति के लाभार्थी कम, दर्शक अधिक हैं।

छ्तीसगढ़ का कोण - और देश की ज़रूरत

अच्छी खबर यह है कि कुछ उदाहरण उम्मीद जगाते हैं - और रास्ता दिखाते हैं। छ्तीसगढ़ के रायपुर स्थित स्टार्टअप 'किसान साथी' ने स्थानीय सब्जी उत्पादकों को डिजिटल मंच से जोड़ा और अब 5,000 से अधिक किसान इससे जुड़े हैं। बिलासपुर के 'कोसा सिल्क टेक' ने पारंपरिक कोसा रेशम को ऑनलाइन ब्रांडिंग देकर दिल्ली-मुंबई बाजार में पहचान बनाई है। सरकारी योजनाओं में मध्य प्रदेश का 'स्टार्टअप इंदौर' मॉडल और छ्तीसगढ़ की 'इन्क्यूबेशन सेंटर स्कीम' (2024) कुछ प्रयास हैं।

जश्न भी, जाँच भी

120 यूनिफॉर्म निश्चित रूप से उत्सव के विषय हैं। लेकिन एक परिपक्व राष्ट्र अपनी उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए अपनी कमजोरियों को भी इमानदारी से देखता है। इजरायल - एक छोटा-सा देश - स्टार्टअप नेशन इसलिए नहीं बना कि उसके पास अधिक यूनिफॉर्म थे, बल्कि इसलिए बना कि उसकी पूरी शिक्षा और संस्कृति में जोखिम लेने, असफल होने और फिर उठने का स्वभाव था।

भारत ने क्या कदम उठाए हैं - और क्या उठाने चाहिए? नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स (10,000 करोड़ रूपए), और सरकारी खरीद में स्टार्टअप को छूट। लेकिन इजरायल के 'योजमा' कार्यक्रम की तरह वैसी संस्थागत मानसिकता भारत में अभी नदारद है। हमें चाहिए: हर विश्वविद्यालय में अनिवार्य 'उद्यमिता प्रयोगशाला', बैंकों के साथ 'असफल उद्यम माफ़ी योजना', और एक राष्ट्रीय 'दूसरा मौका कोष'।

1.8 लाख स्टार्टअप एक संख्या है। लेकिन उनके पीछे 1.8 लाख सपने हैं, लाखों परिवारों की आशाएँ हैं, और एक देश की उद्यमशीलता की भूख है।

'सबसे मजबूत इमारत वह होती है जिसकी नींव सबसे गहरी हो - सबसे ऊँची नहीं।'

कार लोन लेने से पहले यह तीन अंक समझ लीजिए: 20-4-10

एक गलत लोन आपकी ड्रीम कार को बोझ में बदल सकता है। एक अनुभवी बैंकर की नज़र से समझिए - कब, कितना और कैसे लें।



गीतांजलि शर्मा

20% की अवधि, 410% डाउन पेमेंट, सा ल मासिक आय सीमा मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं - 'सर, कौन सी कार लूँ?' मैं हमेशा पलटकर पूछता हूँ - 'पहले बताइए, आपकी मासिक आय कितनी है?' क्योंकि सच यह है कि कार का चुनाव शोरूम में नहीं, आपकी बैंक स्टेटमेंट में

होना चाहिए। बरसों की बैंकिंग में मैंने देखा है कि लोग कार की EMI तो संभाल लेते हैं, पर टायर बदलवाने के पैसे नहीं होते। यहीं से शुरू होती है असली परेशानी।

1 - 20% डाउन पेमेंट: ईएमआई का असली दुश्मन कम डाउन पेमेंट है

मान लीजिए आपने 10 लाख रूपए की कार खरीदी और केवल 50,000 रूपए डाउन पेमेंट दी। अब 9.50 लाख रूपए का लोन 7 साल के लिए 9% ब्याज पर लिया। आप हर महीने 15,200 रूपए देगे और कुल ब्याज चुकाएगे 3.81 लाख रूपए - यानी कार की असली कीमत हो गई 13.81 लाख रूपए।

अब वही कार, 20% यानी 2 लाख रूपए डाउन पेमेंट के साथ। लोन होगा 8 लाख रूपए, EMI घटकर आएगी 12,800 रूपए और कुल ब्याज होगा केवल 55,760 रूपए। सिर्फ 1.50 लाख रूपए ज्यादा डाउन पेमेंट देने से आपने 74,000 रूपए से अधिक ब्याज बचाए। यही तर्क है 20% के पीछे।

उदाहरण - 10 लाख रूपए की कार, 9% ब्याज, 4 साल कार की कीमत (ऑन-रोड) 10,00,000 रूपए
20% डाउन पेमेंट 2,00,000 रूपए
लोन राशि 8,00,000 रूपए
मासिक EMI (4 वर्ष) 19,920 रूपए
कुल ब्याज भुगतान 55,760 रूपए

कार की वास्तविक लागत 10,55,760 रूपए

2 - 4 साल की अवधि: लंबी अवधि सस्ती नहीं, महंगी होती है

बैंक आपको 7 साल तक का कार लोन देने को तैयार हैं - और यही उनका फायदा है, आपका नुकसान। 8 लाख रूपए का लोन अगर 7 साल के लिए लें तो EMI घटकर 12,850 रूपए आएगी, जो सुनने में राहत देती है। पर 7 साल में कुल ब्याज होगा 2.79 लाख रूपए - जबकि 4 साल में ब्याज होगा केवल 55,760 रूपए। सिर्फ अवधि बढ़ाने से आपने अतिरिक्त 2.23 लाख रूपए ब्याज चुकाए।

इसके अलावा एक और जोखिम है - कार की बाजार कीमत। 4 साल बाद कार की रिसेल वैल्यू लगभग 40-50% रह जाती है, पर आपका लोन अभी भी बड़ा होगा। इसे वित्तीय भाषा में 'negative equity' कहते हैं - यानी कार की कीमत से ज्यादा लोन बाकी है।

लोन की अवधि बढ़ाना EMI कम करता है, पर आपकी जेब से निकलने वाला कुल पैसा बड़ा देता है।

3 - 10% आय सीमा: सिर्फ EMI नहीं, पूरा कार-खर्च जोड़े

यह नियम का सबसे अनदेखा हिस्सा है। लोग केवल EMI देखते हैं, बाकी खर्च भूल जाते हैं। अगर आपकी मासिक आय 60,000 रूपए है, तो कार पर कुल खर्च 6,000 रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए।

मासिक कार खर्च का पूरा हिसाब

EMI	4,200 रूपए
ईंधन (पेट्रोल/डीजल)	1,500 रूपए
बीमा (मासिक औसत)	700 रूपए
रखरखाव / सर्विस	400 रूपए
कुल मासिक खर्च	6,800 रूपए

ध्यान दें

6,800 रूपए अगर आपकी आय का 10% से अधिक है, तो या तो आय कम है, या कार बड़ी है। यह संकेत है कि लोन की शर्तें या कार की

पसंद - दोनों में से कुछ बदलना होगा।

4 - वार्षिक आय की 50% से अधिक कीमत की कार मत लीजिए

यह नियम का वह हिस्सा है जो लोग सबसे पहले तोड़ते हैं। 6 लाख रूपए सालाना कमाने वाला व्यक्ति 8 लाख रूपए की कार नहीं लेनी चाहिए। इससे ऊपर जाते ही पूरा 20-4-10 फॉर्मूला टूट जाता है - या तो EMI असहनीय होगी, या अवधि खिंचेगी, या मासिक बजट चरमराएगा।

आय के अनुसार अधिकतम कार बजट

वार्षिक आय	कार = 2.5 लाख रूपए
वार्षिक आय 10 लाख रूपए	कार = 5 लाख रूपए
वार्षिक आय 20 लाख रूपए	कार = 10 लाख रूपए
वार्षिक आय 30 लाख रूपए	कार = 15 लाख रूपए

5 - जब बजट कम पड़े तो ये चार रास्ते अपनाइए

निचला वेरिएंट चुनें
पसंदीदा कार का बेस या मिड वेरिएंट लें। फ्रीचर थोड़े कम होंगे, जेब पर बोझ बहुत कम।

ऋडिट स्कोर सुधारे

750+ स्कोर पर बैंक 0.5-1% कम ब्याज देते हैं - 8 लाख रूपए लोन पर यह 30,000 रूपए की बचत है।

20-4-10 नियम कोई कठोर बेड़ी नहीं है - यह एक दर्पण है जो आपको आपकी असली वित्तीय स्थिति दिखाता है। अगर इस फॉर्मूले में कार फिट नहीं होती, तो समझिए कि कार बड़ी है या समय अभी नहीं आया। गाड़ी बाद में भी मिलेगी - पर एक बार कर्ज के जाल में फँसे, तो निकलना मुश्किल होता है।

आलेख: गीतांजलि शर्मा, बिस्व, बिलासपुर, छ्तीसगढ़ क यहाँ दिए गए आंकड़े औसत बाजार दरों पर आधारित हैं और केवल मार्गदर्शन हेतु हैं। निवेश या लोन से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।

एक युवा बैंकर के उपयोगी टिप्स

चेक बाउंस होने पर क्या करें?

परिवार की सबसे जरूरी वित्तीय सुरक्षा



शाशांका झा

यह भारत में दंडनीय अपराध है-धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) के तहत। समय सीमा - इसे याद रखें (सबसे जरूरी!)

चेक बाउंस

30 दिन में - नोटिस भेजें
15 दिन - इंतज़ार करें
30 दिन में - कोर्ट में केस
एक भी दिन की देर हुई तो आपका केस अदालत खारिज कर सकती है!

तीन जरूरी कदम - Step by Step

1 बाउंस मेमो लें और संपर्क करें (पहले 30 दिन)
बैंक से Dishonour Memo (बाउंस मेमो) लेकर सुरक्षित रखें-यही आपका सबसे पहला सबूत है। चेक देने वाले से पहले मौखिक बात करें। अक्सर गलती या देरी से मामला सुलझ जाता है। अगर वह नया चेक दे तो उसे तुरंत बैंक में जमा करें।

2 लीगल नोटिस भेजें-30 दिन के अंदर

चेक बाउंस की तारीख से 30 दिनों के अंदर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से नोटिस भेजें। लिखें: 'आपका चेक बाउंस हो गया। 15 दिनों में पूरी रकम दें, वरना धारा 138 के तहत कोर्ट में केस करूँगा।' नोटिस की कॉपी और डाक रसीद संभाल कर रखें।

3 मजिस्ट्रेट कोर्ट में परिवाद दर्ज करें-अगले 30 दिन में

15 दिन बाद भी पैसे न मिलें तो अगले 30 दिनों में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में शिकायत करें। साथ लगाएँ: बाउंस मेमो, चेक की फोटोकॉपी, नोटिस और डाक रसीद। दोषी को 2 साल तक की कैद और/या जुर्माना हो सकता है।

कानूनी आधार

धारा 138 - परक्राम्य लिखत अधिनियम (Negotiable Instruments Act)

चेक बाउंस क्या होता है?

जब बैंक चेक को वापस कर दे क्योंकि: खाते में पर्याप्त पैसे नहीं हैं, सिग्नेचर मिसमैच है

कोई तकनीकी कारण है

यह भारत में दंडनीय अपराध है-धारा 138, परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) के तहत। समय सीमा - इसे याद रखें (सबसे जरूरी!)

कोई न्यूनतम राशि की सीमा नहीं-रु.100 का चेक भी हो तो केस हो सकता है

दोषी को 2 साल तक की कैद, जुर्माना, या दोनों

केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में दर्ज होता है शिकायतकर्ता को अपना कोर्ट चुनने का अधिकार है

विशेषज्ञ की खास सलाह

समय सीमा ही सबसे बड़ा हथियार है 30 ---> 15 ---> 30 दिन की लिमिट कैलेंडर में लिख लें। एक दिन की देरी भी केस खारिज करा सकती है। इसे अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाएँ।

हमेशा रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट करें

साधारण डाक, WhatsApp या ईमेल पर भेजा नोटिस कोर्ट में मान्य नहीं होता। रजिस्टर्ड पोस्ट की रसीद आपका अनिवार्य दस्तावेज़ है।

WhatsApp-SMS- कॉल रिकॉर्ड सुरक्षित रखें

बाउंस के बाद की हर बातचीत के स्क्रीनशॉट लें। ये सबूत के रूप में कोर्ट में सहायक हो सकते हैं-हैलॉकिंग कानूनी नोटिस का विकल्प नहीं है।

लोक अदालत-तेज़ और सस्ता विकल्प

अगर दूसरा पक्ष समझौते को तैयार हो तो लोक अदालत जाएँ। यहाँ जल्दी निर्णय होता है, खर्च कम होता है और दोनों का समय बचता है।

शुरूआत खुद, आगे वकील जरूरी

नोटिस खुद भेज सकते हैं, पर कोर्ट में परिववाद दर्ज करने के लिए अनुभवी वकील लेना बेहतर है-खासकर बड़ी राशि के मामले में।

एक से ज्यादा बार बाउंस हर बार अलग केस

अगर चेक बार-बार बाउंस हुए तो हर बाउंस के लिए अलग केस हो सकता है। हर बार की प्रक्रिया और समय सीमा अलग-अलग होती है।

चेक दे रहे हैं? खाते में पैसे सुनिश्चित करें

जानबूझकर चेक बाउंस कराना गंभीर अपराध है। हमेशा सुनिश्चित करें कि चेक देते समय खाते में पर्याप्त राशि हो।

लेखक: शाशांका झा, असिस्टेंट मैनेजर, इंडियन बैंक - बैंकिंग विशेषज्ञ एवं कानूनी सलाहकार

[यह जानकारी केवल जागरूकता के लिए है। विधिक राय के लिए अपने वकील से अवश्य मिलें।]

एक टिप्पणी, लाखों कारकोच - भारत के युवाओं का डिजिटल विद्रोह



सुभाष दत्त झा

कभी-कभी इतिहास एक शब्द से बदलता है। 'कारकोच' - यह वह शब्द था जो 15 मई 2026 को देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री सुर्यकांत जो के मुँह से निकला और बरोजगार, हाता, व्यवस्था से टूटे हुए लाखों युवाओं के दिलों में उतर गया। लेकिन यह शब्द उन्हें तोड़ नहीं सका - बल्कि उन्होंने इसे अपना पहचान बना लिया। 'कारकोच जनता पार्टी' का जन्म हुआ और तीन दिनों में 20 लाख सदस्य और 50 लाख इंटरग्राम फॉलोअर - यह किसी फिल्मी सुपरस्टार की उपलब्धि नहीं, वह भारत के युवाओं के संचित आक्रोश का

विस्फोट है। 65% जनसंख्या, शून्य हिस्सेदारी? भारत के 65 प्रतिशत नागरिक 35 वर्ष से कम उम्र के हैं। यह जनसांख्यिकीय लाभांश एक दुर्लभ ऐतिहासिक अवसर है - लेकिन यह अक्सर तभी फलीभूत होता जब युवाओं को आर्थिक प्रणाली में वास्तविक हिस्सेदारी मिले। आज की स्थिति यह है कि स्नातक युवा सरकारी नौकरी की कतारों में वर्षों गँवाते हैं, परीक्षाएँ लीक होती हैं, अतिरिक्त रह होती हैं। निजी क्षेत्र में वेतन कम है और असुरक्षा अधिक। महिला युवाओं की श्रम भागीदारी दर 20 प्रतिशत से भी नीचे है। CJP की सदस्यता में '11 घंटे ऑनलाइन रहने' की अनिवार्यता दरअसल उस युवा का दर्द है जिसके पास समय तो है, काम नहीं।

व्यंग्य से विद्रोह तक - एक डिजिटल पीढ़ी की भाषा Gen Z की भाषा व्यंग्य है। वे सड़क पर नारे नहीं लगाते, मीम बनाते हैं। वे जुलूस नहीं निकालते, ट्रेंड बनाते हैं। लेकिन इस व्यंग्य के पीछे जो बेचैनी है, वह बिल्कुल वास्तविक है। CJP ने BJP को सोशल मीडिया फॉलोइंग में पीछे छोड़ दिया - यह कोई संयोग नहीं है। यह उस पीढ़ी का संदेश है जो अपनी शर्तों पर राजनीति को देखना चाहती है। जिस पार्टी का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होने लगे, वह केवल मजाक नहीं रहती।

आगे की राह - सुनिष्ट, समझिए, सुधारिए कारकोच जनता पार्टी एक चेतावनी है - अगर इसे समझा गया तो यह एक रचनात्मक आंदोलन बन सकता है, अगर नजरअंदाज किया गया तो यह गुस्से में बदल सकता है। जरूरत है कि भर्ती प्रक्रियाएँ पारदर्शी बनें, शिक्षा और रोजगार के बीच का अंतर पाटा जाए, और संस्थाएँ - चाहे

वे न्यायपालिका हों, सरकार हों या उद्योग - युवाओं को सम्मान से सुनें। वर्ना कारकोच की यह फौज एक दिन वोटबुध पर भी उसी ऊर्जा के साथ उतरेगी - और उस दिन का हिस्सा बहुत बड़ा होगा। इतिहास में जब-जब सत्ता ने युवाओं को अपमानित किया, तब-तब युवाओं ने सत्ता की परिभाषा बदल दी। भारत के कारकोच जाग चुके हैं। अब सवाल यह नहीं है कि उन्हें कैसे रोका जाए - सवाल यह है कि उनकी ऊर्जा को देश के निर्माण में कैसे लगाया जाए। 50 लाख कारकोच और बढ़ रहे हैं। ये वे युवा हैं जो भारत का भविष्य हैं। इन्हें 'कारकोच' कहना इतिहास की सबसे महँगी भूल साबित हो सकती है - या फिर यही क्षण बह मोड़ बन सकता है जब व्यवस्था ने युवाओं की बात सुनी और एक नया भारत बना।

सेवानिवृत्त प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय मनेन्द्रगढ़ अयोध्या नगर, बिलासपुर, छ्तीसगढ़ (आज की जनधारा, बिलासपुर)



'गंगरैल गेस्ट हाउस से इंदौर तक' हनी ट्रैप के जाल में कौन-कौन ?

गंगरैल की रंगीनियों से बढ़ी धड़कन, हनी ट्रैप जांच में नए नामों की चर्चा

कृष्ण कुमार सिंकर

जनधारा समाचार
रायपुर। मध्य प्रदेश के बहुचर्चित हनी ट्रैप कांड की दूसरी कड़ी अब छत्तीसगढ़ तक सियासी और प्रशासनिक हलकों में हलचल पैदा कर रही है। रायपुर और धमदारी के गंगरैल गेस्ट हाउस में हुई कथित हाईप्रोफाइल महफिलों के बाद अब जिस नाम की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वह है रेशू उर्फ अभिलाषा। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि गंगरैल गेस्ट हाउस की कथित रंगीन पार्टियों में उसकी मौजूदगी थी या नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों, प्रशासनिक अफसरों और कारोबारियों के बीच इस बात को लेकर बेचैनी बढ़ गई है कि कहीं वे भी इस पूरे जाल की जड़ में तो नहीं आने वाले। फिलहाल कई प्रभावशाली लोग 'वेट एंड वॉच' की रणनीति अपनाए हुए हैं, मगर उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी हैं।



पहचाना जा रहा था, उसका वास्तविक नाम रेशू चौधरी... उसके भाई अभिलाषा चौधरी से जुड़ा है, जो वर्तमान में बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक 'अभिलाषा' नाम पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर पदस्थ है। रेशू के पिता

- शादी: 10 दिसंबर 2018
- मस्कट प्रवास: मार्च-जून 2019
- देहज प्रताड़ना केस: अगस्त 2019
- भाई: अभिलाषा चौधरी (सिपाही)
- पिता: पुलिसकर्मी (निधन)

भी पुलिस विभाग में थे और उनके निधन के बाद भाई को अनुकरणीय नियोक्ति मिली थी। चर्चा है कि इसी पुलिस बैकग्राउंड और प्रभाव का इस्तेमाल रेशू ने अपने व्यक्तिगत विवादों और संबंधों में भी किया।

रेशू चौधरी की शादी 10 दिसंबर 2018 को रायपुर के शिवाजी पार्क मैरिज गार्डन में महेंद्र चौधरी के साथ हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद मार्च 2019 में वह अपने पति के साथ ओमान की राजधानी मस्कट चली गई थी। बताया जाता है कि वहीं से दोनों के रिश्तों में तनाव शुरू हुआ। हाईप्रोफाइल लाइफस्टाइल और आपसी विवादों के चलते महज तीन महीने बाद जून 2019 में रेशू भारत लौट आईं। इसके बाद अगस्त 2019 में उसने सागर के महिला थाने में पति महेंद्र चौधरी, ससुर प्यारेलाल अहिखार और सास गीता देवी के खिलाफ देहज प्रताड़ना और धरलू हिंसा का मामला दर्ज कराया।

शिकायत में रेशू ने पति पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उसने दवा किया था कि मस्कट में रहने के दौरान उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया, शराब पीने के लिए मजबूर किया गया और उसे कमरे में बंद रखकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसने जान से

मारने की धमकी देने तक के आरोप लगाए थे। दूसरी ओर ससुराल पक्ष ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए कहा था कि रेशू की लाइफस्टाइल और व्यवहार के कारण वैवाहिक संबंध टूटे। उनका आरोप था कि वह मस्कट से नकदी और जेवर लेकर बिना बताए लौट आई थी।

इन विवाद के बाद रेशू सागर में राजनीतिक रूप से सक्रिय हो गईं और भाजपा के एससी मोर्चा से जुड़कर खुद को युवा नेत्री के रूप में स्थापित करने की कोशिश करने लगीं। इसी दौरान उसका नेटवर्क तेजी से बढ़ा और अब उसका नाम कथित हनी ट्रैप नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। उधर, इंदौर ब्रांच की स्पेशल टीम पूरे मामले की जांच बेहद गोपनीय तरीके से कर रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस के पास साक्ष्य जुटाने के लिए सीमित समय है और जांच एजेंसियां इलेक्ट्रॉनिक सबूतों से लेकर वित्तीय लेन-देन तक की पड़ताल में जुटी हुई हैं। अब तक इस मामले में सात लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई अन्य नाम भी जांच एजेंसियों के रडार पर बताए जा रहे हैं। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैैसे-वैसे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में बेचैनी भी बढ़ती जा रही है।

सरगुजा क्षेत्र में सड़क हादसों में 6 मौतें

चलती ट्रैक्टर में घुसी बाइक, 4 मजदूरों की मौत, कार ने 2 ग्रामीणों को कुचला

बलरामपुर। सरगुजा संभाग में सड़क हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना बलरामपुर जिले के ग्राम पीपरपान की है, जहां रविवार शाम बाइक सवार मजदूरों की तेज रफ्तार बाइक चलती ट्रैक्टर में जा घुसी। हादसे में चारों की मौत हो गई। मामला सनावल थाना क्षेत्र का है। ट्रैक्टर ड्राइवर ने हादसे के बाद गाड़ी नहीं रोकी बल्कि घायलों को 100 मीटर तक घसीटकर ले गया, वहीं उन्हें तड़पता छोड़ भाग निकला। मृतकों में सभी चचेरे भाई हैं, एक ही परिवार के हैं। वे मजदूरी करते थे और राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं।

दूसरी घटना नरेश्वर-130 (ऑबिकापुर-बिलासपुर मुख्य मार्ग) पर हुई। जजगा के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 ग्रामीणों को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दोनों युवक उड़कर सड़क पर गिर गए और कई मीटर तक घिसटते चले गए। मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। दोनों ग्रामीण मेहमानी की मंगला



बाद न एम्बुलेंस को सूचना दी गई, न घायलों के इलाज के लिए कोई मदद की गई।

अस्पताल पहुंचने से पहले चारों की मौत: स्थानीय राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक चारों की मौत हो चुकी थी। परिजनों का कहना है कि समय पर इलाज मिल जाता तो युवकों की जान बच सकती थी।

ट्रैक्टर छिपाने का भी आरोप: परिजनों ने आरोप लगाया कि, अशोक यादव ट्रैक्टर का इंजन छिपाने के लिए ग्राम बापरा स्थित अपने ससुराल ले गया। वहीं रामनारायण यादव पर दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर को छिपाने और साक्ष्य मिटाने में सहयोग करने का आरोप लगाया गया है।

आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग: मृतक पंडो जनजाति के थे। समाज के अध्यक्ष उदय कुमार पंडो ने आरोपों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

बाद न एम्बुलेंस को सूचना दी गई, न घायलों के इलाज के लिए कोई मदद की गई।

अस्पताल पहुंचने से पहले चारों की मौत: स्थानीय राहगीरों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन तब तक चारों की मौत हो चुकी थी। परिजनों का कहना है कि समय पर इलाज मिल जाता तो युवकों की जान बच सकती थी।

ट्रैक्टर छिपाने का भी आरोप: परिजनों ने आरोप लगाया कि, अशोक यादव ट्रैक्टर का इंजन छिपाने के लिए ग्राम बापरा स्थित अपने ससुराल ले गया। वहीं रामनारायण यादव पर दुर्घटना में शामिल ट्रैक्टर को छिपाने और साक्ष्य मिटाने में सहयोग करने का आरोप लगाया गया है।

आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग: मृतक पंडो जनजाति के थे। समाज के अध्यक्ष उदय कुमार पंडो ने आरोपों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी के बदले केक काटें

अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने की अपील

रायपुर। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ. दिनेश मिश्र ने कहा है कि ईदुज्जुहा (बकरीद) पर जीवित जानवरों की कुर्बानी देने के बजाय लोग चाहे तो केक काटकर भी धार्मिक रस्म निभा सकते हैं।



उन्होंने बताया कि कुछ राज्यों में पहले ही नियम बनाए गए हैं, जहां ऊंट या अन्य जानवरों की कुर्बानी पर रोक है और कानून तोड़ने पर कार्रवाई भी हो सकती है। तेलंगाणा सहित कई राज्यों में इस तरह के आदेश और कोर्ट के फैसले भी सामने आ चुके हैं। वहीं कई जगहों पर जनजागरूकता के चलते लोग अब पर्यावरण और पशु संरक्षण को ध्यान में रखते हुए अलग तरीके से त्योहार मनाने लग रहे हैं।

निर्दोष जानवरों की जान लेना सही नहीं: डॉ. मिश्र के मुताबिक, देश में कई राज्यों में पशुबलि को लेकर कानून बने हुए हैं, लेकिन उनका पूरी तरह पालन नहीं हो पाता, जिससे कई निर्दोष जानवरों की कुर्बानी हो जाती है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों में प्रेम और अहिंसा का संदेश दिया गया है, इसलिए किसी भी प्राणी की जान लेना सही नहीं है।

कई जगहों पर केक काटकर मनाई गई बकरीद: उन्होंने यह भी बताया कि पिछले कुछ वर्षों में कई जगहों पर लोगों ने जनजागरूकता के चलते बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी छोड़कर केक काटकर प्रतीकात्मक रूप से त्योहार मनाया है। कुछ जगहों पर तो केक पर बकरे की तस्वीर लगाकर भी रस्म निभाई गई।

चोरों के सरदार को पकड़ने पुलिस बनी जनगणना

अधिकारी, 300 किलोमीटर तक पीछा कर दबोचा

दुर्ग। छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, चंडीगढ़ के विभिन्न जिलों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोरों के सरदार को दुर्ग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने दिल्ली में 15 दिनों तक कैंप किया। पुलिस को जब आरोपी के संबंध में जानकारी मिली तो जनगणना अधिकारी बनकर आरोपी नासिर हुसैन के छिपने वाले स्थान पहुंची और घर-घर जाकर जानकारी जुटाई। पुलिस के आने की भनक मिलते ही आरोपी कार में सवार होकर बिहार भाग रहा था, जिसका यमुना एक्सप्रेस-वे पर 300 किलोमीटर तक पीछा कर दबोचा गया। आरोपी के कब्जे से 20 लाख की संपत्ति जब्त की गई।



दरअसल, महंदा में नेहरू नगर, भिलाई थाना, सुपेला, पदमनाभपुर में हुई चोरियों का खुलासा किया गया था। दुर्ग पुलिस ने दिल्ली, मेरठ के अन्तराज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर आरोपी

हासिम खान निवासी शालीमार गार्डन मेरठ (उप्र) को 17 मई को गिरफ्तार किया था। आरोपी के साथ चोरी का जेवर खरीदने वाले ज्वेलरी शॉप संचालक सलीम खान निवासी मेरठ को भी पकड़ा गया था।

आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 60 लाख का सोना बरामद किया गया था। घटना में शामिल फरार आरोपी कुख्यात वा शातिर आरोपी नासिर हुसैन निवासी शाहीनबाग दिल्ली की तलाश की जा रही थी।

विशेष टीम का गठन

इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि शाहीन बाग व मदनपुर खादर, नोएडा क्षेत्र जैसे घनी आबादी, संकरी गलियारों तथा बहुमंजिला फ्लैटों वाले क्षेत्रों में लगातार ठिकाना बदलकर छिपा रहा था। इस जानकारी के बाद एसएसपी विजय अग्रवाल ने तत्काल विशेष टीम का गठन कर दिल्ली रवाना किया।

15 दिनों तक कैंप

पुलिस टीम ने पेशेवर व गोपनीय तरीके से क्षेत्र में 15 दिनों तक कैंप किया। पुलिस के सिविल स्टॉफ ने स्थानीय लोगों के बीच घुल-मिलकर बकरा विक्रेताओं के साथ रहकर व बकरा विक्रेता के साथ कई दिनों तक क्षेत्र में सक्रिय रहकर सदिध व्यक्तियों के ठिकानों की जानकारी जुटाई।

शराब दुकानों पर सीएम-मंत्री की फोटो लगाने की मांग

कोरबा। कोरबा में सुशासन तिहार 2026 के तहत एक अनोखा आवेदन सामने आया है। बाकिमोंगरा नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष मधुसूदन दास ने आबकारी विभाग से शराब दुकानों पर मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री की तस्वीरें लगाने की मांग की है। यह आवेदन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

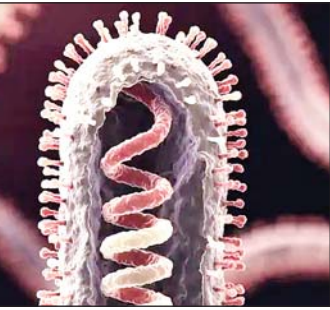
क्रमांक 262703300 में दर्ज इस मांग में जिला कोरबा, नगरीय निकाय बाकिमोंगरा नगर पालिका और वार्ड 7033003 मोंगरा का उल्लेख है। आवेदक मधुसूदन दास ने आबकारी विभाग को संबोधित करते हुए यह मांग रखी है।

मधुसूदन दास ने अपने आवेदन में तर्क दिया है कि राज्य के सभी कार्यों और योजनाओं में मुख्यमंत्री और संबन्धित मंत्री की तस्वीरें लगाई जाती हैं। इसी प्रकार, राज्य सरकार को बड़ा राजस्व देने वाली शराब दुकानों पर भी मुख्यमंत्री और आबकारी मंत्री की तस्वीरें लगाई जानी चाहिए। आवेदन पर आवेदक के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं। सुशासन तिहार 2026 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनता की समस्याओं और मांगों के निराकरण के लिए चलाया जा रहा एक अभियान है। इस अभियान के तहत नागरिक अपनी मांगें और शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।

इबोला वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ अलर्ट

● एयरपोर्ट पर बढ़ाई जाएगी स्क्रीनिंग, संदिग्ध मरीजों की तत्काल होगी पहचान, ● अस्पतालों में तैयारी के निर्देश

रायपुर। बुनियाभर में तेजी से फैल रहे इबोला वायरस को देखते हुए छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ ने संक्रमण की रोकथाम को लेकर सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश जारी किए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों की जांच बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि अगर कोई यात्री संदिग्ध नजर आता है तो उसकी जानकारी तुरंत स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचाई जाए।



अस्पतालों को भी तैयार रखने के निर्देश

स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को आइसोलेशन वार्ड, रेफरल और इमरजेंसी व्यवस्था तैयार रखने के लिए कहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत मरीजों का इलाज और प्रबंधन किया जा सके।

एयरपोर्ट पर रहेगा खास निगरानी सिस्टम

एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम की ओर से जारी निर्देश में रायपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को एयरपोर्ट पर एक नोडल अधिकारी तैनात करने को कहा गया है। यह अधिकारी यात्रियों की स्वास्थ्य जांच और पूरी व्यवस्था की निगरानी करेगा।

कांग्रेस नेता पर फर्जी आर्मस एवट का आरोप

सूरजपुर। विग्रामपुर नगर पंचायत शिवनंदनपुर चुनाव से पहले कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र जैन पर आर्मस एवट के तहत दर्ज मामले को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। भाजपा नेताओं ने नरेंद्र जैन पर कटार अड़ाने का आरोप लगाया था, हालांकि सीसीटीवी फुटेज में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस आरोप के विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में पार्टी के कई नेता थामे पहुंचे। उन्होंने पुलिस पर सत्ता के दबाव में काम करने का आरोप लगाया।

कांग्रेस पदाधिकारियों ने नरेंद्र जैन पर की गई कार्रवाई को फर्जी बताया है और यह कि सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। पदाधिकारियों का आरोप है कि राजनीतिक दृष्टि के चलते नरेंद्र जैन को झूठे आर्मस एवट में फंसाया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या का प्रयास बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग किया जा रहा है।

नेता प्रतिपक्ष महंत का बड़ा बयान

मैं रामभद्राचार्य को जगतगुरु नहीं मानता, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे सभी बाबा हैं फर्जी

मनेन्द्रगढ़। चिरमिरी में जगतगुरु रामभद्राचार्य की कथा चल रही है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत मनेन्द्रगढ़ पहुंचे। जहां मिडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि, मैं रामभद्राचार्य को मैं जगतगुरु नहीं मानता। इसलिए मैं उनकी कथा सुनने नहीं जाऊंगा।

उन्होंने आगे कहा कि, जिस प्रकार से भाजपा का प्रचार कर रहे हैं तो वह सिर्फ भाजपा के प्रचारक हैं। ऐसे बाबा लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसी जगह हमारे कांग्रेस के किसी आदमी को नहीं जाना चाहिए। हम तो कण कण में भगवान मानने वाले लोग हैं। हमारे तो कण-कण में भावान है। धीरेन्द्र शास्त्री सहित अन्य सभी बाबा फर्जी हैं।



सुशासन तिहार में महिला विधायक को जाने नहीं दिया गया

सुशासन तिहार में महिला विधायक शेरराज हरबंश को जाने से रोकने पर श्री महंत ने कहा कि, महिला विधायक को जाने नहीं दिया जा रहा है। कांग्रेसियों को रोका जा रहा है।

है। मुख्यमंत्री किस जगह उतरेंगे यह कलेक्टर एसपी को मालूम है, तो विधायक वहां गए तो रोक दिया जाता है। ये कहा जाता है कि कांग्रेस विधायक ऐसे प्रश्न करेंगे, जिसका जवाब सीएम के पास नहीं होगा। मुख्यमंत्री को जितना सुशासन करना है करते रहे, हम आने वाले दिनों में शासन में होंगे। पामगढ़ की महिला विधायक शेरराज हरबंश को सुशासन तिहार में जाने से कलेक्टर- एसपी ने रोका था।

ओड़िशा से स्कूटी में गांजा लाकर सरगुजा में खपा रहा था दंपती

● साढ़े चार लाख के माल के साथ गिरफ्तार

अंबिकापुर। सरगुजा जिले में नशे के कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में संभागीय आबकारी उडनवस्ता टीम ने शनिवार को बड़ी सफलता हासिल करते हुए ओड़िशा से गांजा लाकर सप्लाई करने वाले दंपती को गिरफ्तार किया है। टीम ने आरोपियों के कब्जे से करीब साढ़े चार लाख रुपए मूल्य का 22.600 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दोनो को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल दाखिल कर दिया गया।

जानकारी के अनुसार संभागीय आबकारी उडनवस्ता टीम को नशे के अवैध कारोबार की सूचना मिलने के बाद थाना सीतापुर क्षेत्र में विशेष गश्त अभियान चलाया जा रहा था। सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता के नेतृत्व में टीम बंदना

राजधानी रायपुर से गांव तक बिजली संकट गहराया

अधोषित कटौती और लो वोल्टेज से जनता परेशान

रायपुर। भीषण गर्मी के बीच छत्तीसगढ़ में बिजली व्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ाती नजर आ रही है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में अधोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दिन हो या रात, बिजली कभी भी गायब हो रही है और कई इलाकों में घंटों तक सप्लाई बाधित रहने से लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। सबसे ज्यादा परेशानी उन इलाकों में है जहां लगातार लो वोल्टेज के कारण कूलर, पंखे और धरलू उपकरण ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं।



पहले से कटौती की सूचना देता है और न ही शिकायतों का समय पर समाधान हो पा रहा है। लो वोल्टेज की समस्या ने धरलू उपभोक्ताओं के साथ व्यापारियों और छोटे उद्योगों को भी प्रभावित किया है। दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बार-बार बंद हो रहे हैं, वहीं कई जगह मोटर पंप तक नहीं चल पा रहे। इससे पेयजल संकट की स्थिति भी बनने लगी है। छात्रों व बच्चों को उमस भरी गर्मी में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है।

बिजली संकट को लेकर अब राजनीतिक सवाल भी उठने लगे हैं। विपक्ष का आरोप है कि

सरकार बिजली उत्पादन और वितरण व्यवस्था संभालने में नाकाम साबित हो रही है। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जिस राज्य को कभी बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बताया जाता था, वहां आज उपभोक्ताओं को अधोषित कटौती क्यों झेलनी पड़ रही है। दूसरी ओर बिजली विभाग और तकनीकी कारणों के चलते कुछ क्षेत्रों में सप्लाई प्रभावित हो रही है, हालांकि हालात सुधारने के प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रदेश में लगातार बढ़ रही बिजली मांग के बीच वितरण व्यवस्था की कमजोरियां भी सामने आने लगी हैं। कई जगह पुराने ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो रहे हैं और लाइन फॉल्ट की घटनाएं बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिजली बिल समय पर वसूल जाते हैं, लेकिन सुविधा के नाम पर उपभोक्ताओं को सिर्फ परेशानी मिल रही है। अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार और बिजली विभाग इस संकट से राहत दिलाने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ हालात और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है।

केनाल-लिक रोड के लिए बेदखली नोटिस पर विरोध

● जोगीडीपा के लोग पहुंचे रायगढ़ निगम

रायगढ़। जिले में जोगीडीपा-फोजदार पारा इलाके में प्रस्तावित केनाल लिंक रोड निर्माण को लेकर विवाद शुरू हो गया है। नगर निगम ने पहले चरण में करीब 25 से 30 लोगों को बेदखली नोटिस जारी किया है। इसके बाद बड़ी संख्या में स्थानीय महिला और पुरुष नगर निगम पहुंचकर विरोध जताया और महापौर से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं।

नगर निगम की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि, नजूल भूमि पर बिना अनुमति निर्माण किया गया है, जो नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 293 का उल्लंघन है। नोटिस में प्रभावित लोगों से निर्माण संबंधी अनुमति पर प्रस्तुत करने को कहा गया है।

दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।

महापौर बोलें- कम से कम लोग होंगे प्रभावित: मेयर जीवर्धन चौहान ने प्रभावित लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि परियोजना में कम से कम परिवार प्रभावित हों, इसका प्रयास किया जाएगा। हर परिवार का बेहतर तरीके से विस्थापन किया जाएगा।

महापौर ने प्रगति नगर परियोजना का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां 70 मकान टूटे थे और 120 लोगों को मकान उपलब्ध कराए गए थे।